लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

[खंड 12 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol.XII contains Nos.1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण

14 फरवरी, 1968 । 25 माघ, 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
200	नीचे से पंक्ति 3 में सदस्य के नाम से पहले 'श्री' शब्द जोड़ दीजिये ।
287	पंक्ति 28-29 को पंक्ति 31 के पश्चात् पढ़िये ।
293	नीचे से पंक्ति 3 में 'श्री [illegible]रन ([illegible]डागरा)' के स्थान पर 'श्री पी. विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम)' पढ़िये ।
294	छठी पंक्ति में 'श्री डी.ना.मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर पूर्व)' के स्थान पर 'श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर)' पढ़िये तथा '120' के बाद '121, 122, 123, 124, 125, 126' जोड़ दीजिये । नवीं पंक्ति में 'श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर)' के स्थान पर 'श्री मुहम्मद इस्माइल (बैरकपुर)' पढ़िये । ग्यारहवीं पंक्ति में 'श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा)' के स्थान पर 'श्री लकप्पा (तुमकुर)' पढ़िये । सोलहवीं पंक्ति में '275 और 274' शब्द निकाल दीजिये । सत्रहवीं पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िये : श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 274, 275 और 276 प्रस्तुत करता हूं ।

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3, बुधवार, 14 फरवरी, 1968/25 माघ, 1889 (शक)

No. 3, Wednesday, February 14, 1968/ Magha 25, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

*S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
31. वियतनाम की स्थिति के बारे में वार्ता	Talks on Vietnam Situation	187—193
32. वर्ष 1968-69 के लिए वार्षिक योजना	Annual Plan for 1968-69	193
39 1968-69 के लिये योजना परिव्यय	Plan Outlay for 1968-69	193—197
33. भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा धोखेबाजी	Defrauding by Indian Film Producers	197—199
34. इंगलैंड में सिख कर्मचारियों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Sikh Employees in U. K.	199—200
35. आकाशवाणी का भावी स्वरूप	Future set up of All India Radio	200—202

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S. Q.Nos.

36. आसाम पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों का तैनात किया जाना	Deployment of Pakistan Troops on Assam East Pak. Border	202—209

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
37.	चौथी पंचवर्षीय योजना में गैर सरकारी क्षेत्र का योगदान	Role of Private Sector in Fourth Plan	203
38.	ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायोग के प्रथम सचिव का निष्कासन	Expulsion of the First Secretary, Indian Deputy High Commission in Dacca	203
40.	प्रधान मंत्री के साथ शेख अब्दुल्ला की बातचीत	Sheikh Abdullah's talks with Prime Minister	204
41.	मिग 21 विमान	MIG 21 Aircraft	204—205
42.	राष्ट्रपति अयूब खां की "फ्रैंडस नाट मास्टर्स" नामक पुस्तक	President Ayub Khan's Book Friends not Masters	205
43.	फारस की खाड़ी	Persian Gulf	205—206
44.	विद्रोही नागाओं के हमले	Attacks by Rebel Nagas	206
45.	हांगकांग से निष्कासित भारतीय	Indians deported from Hongkong	206—207
46.	स्वेज के पूर्व में स्थित ब्रिटिश सैनिक अड्डे	Britain's Military Bases East of Suez	207—208
47.	एकारूसी अध्यापक का देश त्याग	Defection of a Russian Teacher	208—209
48.	पाकिस्तान में जातीय संहार	Racial Genocide in Pakistan	209
49.	पाकिस्तान की सुरक्षा सम्बन्धी तैयारियां	Pakistan's Defence Preparations	209
50.	टेलीविजन स्टेशन	T. V. Stations	210
51.	चीन के साथ सम्बन्ध	Relations with China	210
52.	मौरल री आर्मामेंट संगठन के नेता की कोहिमा की यात्रा	Visit of M. R. A. Leader to Kohima	210
53.	पश्चिम एशिया के बारे में यूगोस्लाविया के प्रस्ताव	Yugoslavia's proposals about West Asia	211
56.	स्वेज नहर को पुनः चालू करना	Reopening of Suez Canal	211
57.	पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अधिकारी का निष्कासन	Expulsion of an official of Pak. High Commission	212

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
58.	संयुक्तराष्ट्र संघ के रिकार्डों से जम्मू तथा काश्मीर को भारतीय राज्य क्षेत्र के भाग के रूप में निकाल दिया जाना	Exclusion of Jammu and Kashmir as part of Indian Territory from UNO Records	212
59.	अरब इसराइल संघर्ष	Arab Israel Conflict	212—213
60.	भारतीय प्रवासियों के भविष्य के बारे में भारत तथा सिंगापुर के बीच विचार-विमर्श	Talks between India and Singapore on future of Indian Settlers	213
अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
257.	केनिया में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन	Screening of Indian Films in Kenya	213
259.	सिपाहियों तथा अन्य रैंकों के वेतनक्रम तथा भत्ते	Pay scales and Allowances to sepoys and other Ranks	213—214
260.	सशस्त्र सेना में पदोन्नतियां	Promotion in Armed Forces	214
261.	आकाशवाणी में भर्ती	Recruitment in All India Radio	214—215
262.	अम्बाजारी में आयुध कारखाना बनाने के लिए ठेका	Contract for Erection of Ordnance Factory at Ambazari	215
263.	टेलीविजन सेटों का निर्माण	Manufacture of Television Sets	215—216
264.	कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission in Cambodia	216
265.	भारतीय राजनयिकों और सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा आरोप	Pak. Charge against Indian Diplomats and Army Officers	216—217
266.	हिन्दी समाचार बुलेटिन	Hindi News Bulletin	217
267.	चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Five Year Plan	217
268.	कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग	International Control Commission in Cambodia	218
269.	चीन द्वारा भारतीय सीमा के साथ-साथ सैनिकों का जमाव	Chinese concentration along Indian borders	218
270.	परमाणु हथियारों के प्रासर को रोकने के बारे में अमरीका तथा रूस से समझौता	Agreement between USA & USSR about non-proliferation of Nuclear Weapons	219

अता० प्रश्न सं०

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
271. आकाशवाणी से व्यापारिक प्रसारण	Commercial Broadcast on A. I. R.	219—220
272. ढाका में भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Dacca	220
273. करनाल के लिये ट्रांसमिटर	Transmitter for Karnal	220—221
274. संयुक्त राष्ट्र प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध	Ban on UN Publications	221
275. भारत में काम कर रहीं विदेशी संस्थाएं	Foreign Organisations Working in India	221
276. नेपाल के गृह मंत्री का वक्तव्य	Statement by Home Minister of Nepal	222
277. गैर-सरकारी पक्षों को दिये गये प्रतिरक्षा संबंधी क्रयादेशों का निष्पादन	Execution of Defence Orders placed with Private Parties	222
278. चौथी पंचवर्षीय योजना में अणु-शक्ति का विकास	Atomic Development under Fourth Plan	222--223
279. कच्छ न्यायधिकरण का पंचाट	Kutch Tribunal Award	223
280. भारत में विदेशियों की अचल सम्पति	Immoveable properties of Foreigners in India	223
281. सशस्त्र सेना के लिये नये वेतनमान	New Pay Scales for Armed Forces	223—224
282. सैनिक संचार व्यवस्था में सुधार	Improvement in the Army Communication System	224
283. ईरान के माध्यम से पाकिस्तान आने वाले अमरीकी शसत्रास्त्र	US Arms coming to Pakistan through Iran	224—225
284. भारत पर आरोप लगाने वाला पाकिस्तान का सुरक्षा परिषद् को पत्र	Pak. letter to Security Council Accusing India	225
285. दिल्ली नगर निगम का वर्ष 1968–69 का योजना परिव्यय	Plan outlay for Delhi Municipal Corporation for 1968-69	225—226
286. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संसद् कार्य सहायक का पद	Post of Parliament Assistant in I & B Ministry	226
287. चीन द्वारा वायु तथा भूमि सीमा का उल्लंघन	Land and Airspace Violations by China	226

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
288.	चीन द्वारा भारत विरोधी प्रचार	Anti Indian Propaganda by China	227
289.	व्यापारिक प्रसारण सेवा	Commercial Broadcasting Service	227
290.	दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन	Organisation of South East Asian Countries	227—228
291.	नेफा में विमानों से सामान गिराने का कार्य	Air Dropping Operations in NEFA	228—229
292.	प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं में निदेशकों के पदों पर वैज्ञानिकों की नियुक्ति	Appointment of Scientists as Directors in Defence Laboratories	229
293.	अनुसंधान तथा विकास संगठन में निदेशकों के पद	Post of Directors in R & D Organisation	229—230
294.	दक्षिण अफ्रीका के लिये ब्रिटिश हथियार	British Arms for South Africa	230
295.	तिब्बती लोगों द्वारा नेपाल जाने के लिये अनुमति का मांगा जाना	Permission sought by Tibetans to go to Nepal	230—231
296.	वायु सेना के कर्मचारियों के वेतनमान	Pay Scales of Air Force personnel	231
297.	रूसी पत्रिका में लेखों के बारे में मास्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा विरोधपत्र	Protest by Indian Emabssy in Moscow on Articles in Soviet Journals	231
298.	जोर्डन की ओर से पाकिस्तान द्वारा लड़ाकू विमानों की खरीद	Fighter Planes purchased by Pakistan on behalf of Jordon	231—232
299.	श्रीमती शीरी बाई का पाकिस्तान चले जाना	Emigration of Mrs. Shirin Bai to Pakistan	232
300.	पाकिस्तान में जा बसे मुसलमान	Muslims Migrated to Pakistan	233
302.	आकाशवाणी से अंग्रेजी में प्रसारण	Broadcasts in English from All India Radio	233
303.	अंग्रेजी समाचार बुलेटिन	English News Bulletins	233
304.	इंगलैंड में सिखों के प्रति भेदभाव	Discrimination against Sikhs in U.K.	233—234
305.	रूस से पनडुब्बियां	Submarines from USSR	234

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
306. हिन्दी में प्रसारण	Hindi Broadcasts	234—235
307. प्रतिरक्षा संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण	Modernisation of defence equipment	235
308. कच्छ न्यायाधिकरण पर खर्च	Expenditure on Kutch Tribunal	235
309. भारत में अमरीकी मिशन का नया उप-प्रधान	New Deputy Chief of US Mission in Ind!a	236
310. प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो	Press Information Bureau	236
311. हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी समिति	Committee on use of Hindi	236—237
312. जवानों के लिये हिन्दी की परीक्षा	Hindi Examination for Jawans	237
313. ब्रिटिश संग्रहालय में तांतिया टोपे के अवशेष	Relics of Tantia Tope in British Museum	237—238
314. सुपर जेट विमान	Super Jer Aircrafts	238
315. पूर्वी पाकिस्तान में नजरबन्द भारतीय लोग	Indians detained in East Pakistan	238—239
316. नागालैंड में शांति समझौता	Cease fire in Nagaland	239
317. दलाई लामा	Dalai Lama	239
318. सैनिक भूमि छावनी विभाग	Military Land Cantonment	239—240
319. कुछ विदेशी प्रकाशनों में काश्मीर को पाकिस्तान के भाग के रूप में दिखाया जाना	Kashmir shown as part of Pakistan in some Foreign Publications	240
320. वियतनाम में मिली-जुली सरकार का प्रस्तारण	Proposal of a coalition Government in vietnam	240—241
321. वियतनाम की लड़ाई में विषैली गैस और विषाक्त पदार्थों का प्रयोग	Use of poisonous gas and taxis agents in Vietnam War	241
322. सिन्हाली, बर्मी और पश्तो में कार्यक्रम	Programme in Sinhalese, Burmese and Pushto	241
323. सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारण केन्द्र	Broadcasting stations in Border Areas	241—242
324. सीमा क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाओं में आकाशवाणी के कार्यक्रम	Programmes in Languages spoken in Border Areas	242

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
325.	छावनी बोर्ड	Cantonment Boards	242
326.	दानापुर छावनी बोर्ड	Danapur Cantt. Board	243—244
327.	दानापुर छावनी बोर्ड	Danapur Cantt. Board	244
328.	उर्वरा भूमि का अधिग्रहण	Acquistion of Fertile Lands	244—245
329.	दरभंगा, गोरखपुर और मोतीहारी में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Darbhanga, Gorakhpur and Motihari	245
330.	बादशाह खान को निमंत्रण	Invitation to Badshah Khan	245—246
331.	प्रतिरक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाएं	Defence Research Laboratories	246
332.	प्रतिरक्षा प्रयोगशालाएं	Defence Laboratories	246
333.	पुरानी तथा अनुपयोगी मोटर गाड़ियां	Obsolete and Unserviceable Vehicles	246—247
334.	टेलीविजन स्टेशन	T. V. Stations	247—248
335.	वैमानिकी सम्बन्धी समिति	Committee on Aeronautics	248
336.	गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, 1967 के अधिनियम पर पाकिस्तान को आपत्ति	Pak. objection to enactment of Unlawful Activities Act, 1967	248
337.	प्रचार साधनों के बारे में चंदा समिति का प्रस्ताव	Chanda Committee's Proposal regarding Publicity Media	248—249
338.	चीन के साथ नागाओं की साँठ-गाँठ	Naga's Collusion with China	249
339.	पाकिस्तान के वायुसेनाध्यक्ष का दौरा	Pakistan Air Chief's visit	249—250
340.	1968—69 में उड़ीसा के लिए योजना में धन का नियतन	Plan Allocation for Orissa during 1968-69	250
341.	1967—68 के लिए उड़ीसा की योजना के लिए धन राशि का नियतन	Plan Allocation for Orissa for 1967-68	250
342.	नौसेना प्रशिक्षण संस्थान को पारादीप ले जाना	Shifting of Naval Training Establishment to Paradeep	250—251
343.	भारत और तुर्की के सम्बन्ध	Indo-Turkish Relations	251
344.	कृषि आय कर	Agricultural Income Tax	251

अता० प्रश्न संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
345.	कृषि क्षेत्र के लिये संसाधन	Resources for Agricultural Sector	251—252
346.	यमन के प्रधान मंत्री से सन्देश	Message from Yemeni Prime Minister	252
347.	हिन्दी प्रशिक्षण योजना	Hindi Training Scheme	252
349.	विद्रोही नागा नेताओं की चीन जाने की योजना	Rebel Nega Leaders Planning to China	252—253
350.	1965 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान पाकिस्तान द्वारा रोकी गई नावें तथा जहाज	Boats and Ships Impounded by Pakistan during 1965 Indo Pak. Conflict	253
351.	नागालैंड में जनमत संग्रह की मांग	Demand of Plebiscite in Nagaland	253—254
353.	श्रीलंका से राज्यहीन भारत मूलक व्यक्तियों का स्वदेश लौटना	Repatriation of Stateless Persons of Indian Origin from Ceylon	254
354.	दक्षिण पूर्व एशयाई देशों के बीच संयुक्त प्रतिरक्षा करार	Joint Defence of S. E. Asian Countries	254—255
355.	प्रधान मंत्री का नेफा का दौरा	P. M's visit to NEFA	255
357.	प्रमाण तथा परिक्षण संस्थान	Proof and Experimental Establishment.	255—256
358.	एवरो–748 विमानों का निर्माण	Manufacture of AVRO-748	256
359.	आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों का सेवा सम्बन्धी करार	Contract service of A. I. R. Staff Artistes	256
360.	राजनैतिक शरण के बारे में विदेशी दूतावासों को जारी की गई हिदायतें	Instructions issued to Foreign Embassies regarding Political Asylum	256—257
361.	वार्षिक योजना	Annual Plans	257
362.	चीन द्वारा अणु बम का विस्फोट	Chinese Atomic Explosion	257—258
363.	भारतीय समाचारपत्र	Indian Press	258
364.	भारतीय दूतावासों के हिन्दी जानने वाले कर्मचारी	Employees of Indian Embassies knowing Hindi	258—259

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
365.	चीन-नेपाल सीमा पर चीनियों द्वारा विमानों के लिये हवाई अड्डों का निर्माण	Chinese Jet Aerodromes on Sino Nepalese Border	259
366.	व्यापारिक प्रसारणों के लिए शुल्क	Charges for Commercial Broadcast	259
367.	व्यापार संबंधी प्रसारणों के लिये ठेके	Contract for Commerial Broadcast	259—260
368.	तारिक अब्दुल्ला	Tariq Abdullah	260
369.	गाजा में मारे गये भारतीय सैनिकों के परिवारों को प्रतिकर	Compensation for Indian soldiers killed in Gaza	260
370.	प्रसारण कार्यक्रमों में परिवर्तन	Changes in Broadcasting programmes	260—261
371.	ताशकन्द घोषणा का क्रियान्वयन	Implementation of Tashkent Declaration	261
372.	रोम में भारतीय दूतावास	Indian Embassy in Rome	261
373.	तेलगू भाषा की सामयिक पत्रिकायें	Telugu Periodicals	262
374.	बुन्देलखंड में रेडियो स्टेशन	Radio Station in Bundhelkhand	262
375.	दक्षिण अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावास	Indian Embassies in South African Countries	262—263
376.	कुरनूल में आकाशवाणी केन्द्र	Radio Station at Kurnool	263
377.	विशाखापत्तनम में नौसैनिक गोदी	Naval Dockyard at Visakhapatnam	263
378.	विदेशों में स्थिति भारतीय दूतावासों में हिन्दी में किया गया काम	Work done in Hindi in Indian Missions Abroad	263—264
379.	डा० धर्म तेजा का प्रत्यर्पण	Extradition of Do Dr. Dharma Teja	264—265
380.	गोलापाड़ा स्थित सैनिक स्कूल	Sainik School, Goalpara	265
381.	ओलूग जेड के मामले में अमरीकी दूतावास और ब्रिटिश उच्चायोग का रुख	Role played by US Embassy and British High Commission in Ouloug Zade Affair	265—266

अता० प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ AGES
382.	श्री लंका से भारत लौटने वाले व्यक्तियों को चीनियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना	Training of Ceylonese repartriates to India by Chinese	266
383.	चलचित्र वित्त निगम	Film Finance Corporation	266—267
384.	जनवरी 1968 में दिल्ली में विद्रोही नागा नेताओं का दौरा	Visit of Hostile Naga Chiefs to Delhi in Jan. 1968	267
385.	1962 में चीनियों द्वारा पकड़े गये भारतीय सैनिकों को बहकाया जाना	Indoctrination of Indian soldieres captured by Chinese in 1962	267
387.	शिक्षा प्रयोजनों के लिये टेलीविजन का प्रयोग	T.V. for educational purposes	267—268
388.	पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का तुर्की का वचन	Turkey's undertaking to supply arms to Pakistan	268
389.	पश्चिमी पाकिस्तान में प्रकाशित भारतीय लेखकों की पुस्तकें	Books of Indian authors published in West Pakistan	268
390.	चीन का सातवाँ अण्विक परीक्षण	China's 7th Nuclear Test	268—269
391.	भारत तथा जापान के बीच वार्ता	Discussions between India and Japan	269
392.	बेरुबाड़ी क्षेत्र का दिया जाना	Transfer of Berubari	269—270
394.	हिन्द महासागर में परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बियों का तैनात किया जाना	Deployment of Nuclear Powered Submarines in Indian ocean	270
395.	सरकारी उपक्रमों संबंधी अध्ययन दल	Study Team on Public Undertakings	270
396.	वार्षिक योजनाएं	Annual Plans	270
397.	चन्दा समिति	Chanda Committee	270—271
398.	पाकिस्तान के लिये ईरानी जहाज	Iranian Planes for Pakistan	271
399.	पाकिस्तान द्वारा वायु तथा भूमि सीमा का उल्लंघन	Air and Land Violations Committed by Pakistan	271—272
400.	भूमिगत नागा नेताओं की चीन की यात्रा	Underground Naga Leaders Visit to China	272
401.	लंदन के हवाई अड्डे पर रोक लिये गये भारतीय	Indians stranded at London Airport	272—273

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
402.	अशिष्ट तथा अश्लील इश्तहारों का लगाया जाना	Display of Indecent and Obscene Posters	273
403.	भारत से रूसी राष्ट्रजनों का देश त्याग	Defections of USSR Nationals from India	273—274
404.	अमृतसर जिले के देहातों के पास गोली चलाने का अभ्यास	Field Firing Practice near Villages in Amritsar District	274
405.	जंजीबार में भारतीय लोग	Indians In Zanzibar	274—275
406.	सेना के कर्मचारियों को पेंशन	Pension to Service Personnel	275
408.	मध्य प्रदेश के लिये वर्ष 1968--69 की वार्षिक योजना	Annual plan for 1968-69 for M.P.	275—276
409.	भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध	Indian Pak. Relations	276
410.	विमानों के पुर्जे बनाने का कारखाना	Aircraft Parts Manufacturing Factory	276—277
411.	सेना के प्रशिक्षण केन्द्रों में विदेशी प्रशिक्षणार्थी	Foreign Trainees in Army Training Centres	277
412.	गणतन्त्र दिवस की परेड में विदेशी केडिटों द्वारा भाग लिया जाना	Participation by Foreign Cadets in Republic Day Parade	277
413.	नई हिन्दी फिल्मों का प्रदर्शन	Exhibition of New Hindi Films	277—278
415.	हज यात्री	Haj Pilgrims	278
416.	हिन्द महासागर में ब्रिटिश अमरीकी अड्डे	Anglo US Bases in Indian Ocean	279
417.	मध्य प्रदेश में चांदमारी क्षेत्र	Shooting Ranges in Madhya Pradesh	279
418.	मध्य प्रदेश के हज यात्री	Haj Pilgrims from Madhya Pradesh	279—280
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		Calling attention to matter of urgent public importance	280—281
	श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु	Death of Shri Deen Dayal Upadhyaya	
	श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
	डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGE
स्थगन में प्रस्ताव	Motion for adjournment	282
आगाम में उपद्रव	Disturbances in Assam	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	282—283
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	283
प्राक्कलन समिति के प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद सम्बन्धी शिफारिशों पर की गई कार्यवाही बताने वाले सरकार के उत्तरों का स्वीकार करने के बारे में घोषणा	Announcement Re. acceptance of Government replies by Estimates Committee re. Defence Research and Development Laboratory; Hyderabad	283
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on private members bills and resolutions	283
उन्नीसवां प्रतिवेदन	Nineteenth Report	283
लोक लेखा समिति	Public accounts committee	283
तेरहवां प्रतिवेदन	Thirteenth Report	
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	284
चौबीसवें से अठाइसवें के प्रतिवेदन	Twenty-fourth to Twenty-eighth Reports	
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	284
तेरहवां प्रतिवेदन	Thirteenth Report	
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion of thanks on the president's Address (Not concluded)	285—295
श्री चन्द्रजीत यादव	Shri Chandra Jeet Yadav	
श्री मु० न० नाघनूर	Shri M. N. Naghnoor	
श्री रंगा	Shri Ranga	
श्री पी० वेंकटासुब्बैया	Shri P. Venkatasubbaiah	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	
स्थगन प्रस्ताव—जारी अस्वीकृत	Motion for Adjournment—negatived contd.	296—308
आसाम में उपद्रव	Disturbances in Assam	
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	
श्री डा० कर्णी सिंह	Shri Karni Singh	

श्री सीताराम केसरी Shri Sitaram Kesri
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया Shri D. N. Patodia
श्री रा० बरुआ Shri R. Barua
श्री जी० भा० कृपालानी Shri J. B. Kripalani
श्री मनुभाई पटेल Shri Manubhai Patel
श्री बलराज मधोक Shri Balraj Madhok
श्री तुलसीदास जाधव Shri Tulshidas Jadhav
श्री मनोहरन Shri Manoharan
श्री ही० ना० मुकर्जी Shri H. N. Mukerjee
श्री रणधीर सिंह Shri Randhir Singh
श्री प० राममूर्ति Shri P. Ramamurti
श्री हेम बरुआ Shri Hem Barua
श्री यशवन्तराव चव्हाण Shri Y. B. Chavan

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार, 14 फरवरी, 1968/ 25 माघ, 1889 (शक)
Wednesday, February 14, 1968/ Magha 25, 1889 (Saka)

———

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

वियतनाम की स्थिति के बारे में वार्ता

*31. श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्री वासुदेवन नायर :
डा० रानेन सेन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना शर्त बमबारी बंद कर दिये जाने के बाद "संगत प्रश्नों" पर अमरीका के साथ बातचीत करने के लिये हनोई द्वारा की गई घोषणा के बारे में क्या भारत सरकार वाशिंगटन के साथ सम्पर्क बनाये हुए है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अमरीका की सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) :

(क) और (ख) : भारत सरकार अमरीका और वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य सहित विभिन्न संबद्ध पक्षों के सम्पर्क में है। चूंकि स्थिति नाजुक है और विभिन्न सरकारों की प्रतिक्रिया गोपनीय है, इसलिए उसे बताना उचित न होगा, खास तौर से इसलिए कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन का अध्यक्ष है ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : एक ओर उत्तर वियतनाम द्वारा शान्ति के लिये शर्तों की घोषणा की जाती है तो दूसरी ओर ठेट समझौते का उल्लंघन किया जाता है और इसी प्रकार एक ओर अमरीका द्वारा शान्ति के लिये घोषणा की जाती है तो दूसरी ओर वियतनाम में और अधिक अमरीकी सेनाएं भेजी जाती हैं । क्या सरकार इन दोनों बातों की निरर्थकता को महसूस करती है ?

श्री ब० रा० भगत : किसी भी पक्ष द्वारा संघर्ष को बढ़ाये जाने वाली कार्यवाही करने पर हम उसकी निन्दा करते हैं । हमने इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी है कि पहले बिना शर्त के बमबारी बन्द करनी चाहिये और हमारी यह धारणा है कि यदि बमबारी बन्द हो जाती है तो उसके बाद शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत हो सकेगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या मैं पूछ सकती हूँ कि भारत सरकार मध्यस्थता करवाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है और युद्ध करने वाले देशों की परस्पर बातचीत करवाने के सम्बन्ध में भारत ने अपने प्रभाव का कहां तक प्रयोग किया है ?

श्री ब० रा० भगत : वियतनाम में अत्यधिक क्षति हो रही है और हम इस बात के लिये चिन्तित हैं कि किसी तरह इतने बड़े हत्याकान्ड का अन्त हो जाये। हालाँकि हम मध्यस्थ नहीं बनना चाहते, फिर भी अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में हम सम्बन्धित पक्षों से सम्पर्क बनाये हुए हैं और इस पेचीदा और कठिन मामले में शान्तिपूर्ण स्थिति बनाने के लिये हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महा-सचिव को स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अमरीका को बता दें कि वे वियतनाम से निकल जायें और इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिये ? क्या हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हमने अपनी स्थिति पहले भी स्पष्ट कर दी थी और अब भी स्पष्ट है, परन्तु मेरे विचार में संयुक्त राष्ट्र के महा-सचिव का यह काम नहीं है कि वह हमारे संदेश अमरीकी सरकार को दें ।

डा० रानेन सेन : भारत सरकार ने बहुत पहले यह दृष्टिकोण अपनाया था कि बमबारी समाप्त होने के बाद ही हेनोई बातचीत के लिये तैयार हो सकता है। बहुत सी अन्य सरकारों ने भी, जिनमें फ्रांस और ब्रिटेन शामिल हैं, बमबारी बन्द करने के लिये कहा था। परन्तु फिर भी अमरीका सरकार ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया था । क्या कारण है जिससे भारत सरकार उत्तर वियतनाम पर बमबारी बन्द करने के सम्बन्ध में विश्व के राष्ट्रों के अनुरोध को स्वीकार करने के लिये अमरीका को बाध्य नहीं कर सकती ?

श्रीमती इन्दिरा गाँधी : हमने अपने विचार अभिव्यक्त कर दिये हैं और हमारे अब भी वही विचार हैं । हमने अपने विचार बहुत स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किये हैं। मेरे विचार में

हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम अमरीका को इस सम्बन्ध में कुछ करने के लिये बाध्य कर सकें ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : राष्ट्रपति टीटो, प्रधान मंत्री कोसीगिन और महा-सचिव ऊ-थांत के साथ बातचीत करने के बाद क्या उत्तर वियतनाम पर बिना शर्त के बमबारी बन्द करने के भारत के अनुरोध को किसी ने स्वीकार किया है ? क्या हम कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में हमें कुछ सफलता मिली है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह केवल भारत का अनुरोध नहीं है, यह प्रधान मंत्री कोसीगिन, राष्ट्रपति टीटो और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का भी अनुरोध है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : आखिर इस बात-चीत का परिणाम क्या निकला है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझा है, इसके सिवाय इस बातचीत का और कोई परिणाम नहीं निकला है ।

श्री हेम बरुआ : युद्ध के भड़कने के दो कारण हैं—एक तो अमरीका द्वारा बमबारी करना और दूसरा रूस द्वारा वियतकांग सेनाओं को शस्त्रास्त्र सप्लाई करना । सरकार ने अमरीका के अपराध को तो स्वीकार किया है परन्तु क्या सरकार ने रूस की इस कार्यवाही की भी निन्दा की है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां तक मुझे जानकारी है, रूस वियतनाम को शस्त्रास्त्र सप्लाई कर रहा है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : संसार के इस भाग में संघर्ष समाप्त करने और मानव जाति को विनाश से बचाने के लिये क्या सरकार ने वियतनाम युद्ध के सम्बन्धित पक्षों के बीच बातचीत करवाने के लिये प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही की थी ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह हमारी इच्छा रही है परन्तु मुझे खेद है कि हमें इस सम्बन्ध में सफलता नहीं मिली ।

श्री राममूर्ति : क्या यह सच नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का एक काम उन चुनावों का निरीक्षण करना था जो 1956 में दक्षिण और वियतनाम में होने थे और अमरीका और दक्षिण वियतनाम की कठपुतली सरकार द्वारा जनेवा समझौते का उल्लंघन किये जाने के कारण वियतनाम में यह स्थिति पैदा हुई है ? अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि वह संसार को बताये कि अमरीका उक्त समझौते का उल्लंघन करने का दोषी है और इसलिये उसे वियतनाम से चला जाना चाहिये जिससे समस्या का समाधान हो सके ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने यह कहा है कि हमने इन सब मामलों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं । इस समय महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समस्या को युद्ध-क्षेत्र से हटा कर बातचीत करके सुलझाया जाये । इस कार्य को सम्भव बनाने के लिये सभी प्रयत्न किये जाने चाहिये ।

श्री राममूर्ति : क्या अमरीका ने उपरोक्त समझौते का उल्लंघन नहीं किया है ?

श्रीमती इन्दिरा गान्धी : अमरीका ने जनेवा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये थे ।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : प्रधान मन्त्री ने सभा को आश्वासन दिया है कि सभी प्रयत्न किये गये हैं जिनसे युद्ध अधिक न भड़के और उत्तर वियतनाम पर अधिक बमबारी न हो। क्या हम आशा करें कि अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष के रूप में भारत सभी प्रकार के प्रयत्न करेगा जिससे अमरीका उत्तर वियतनाम में अधिक युद्ध न बढ़ाये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जितनी प्रभावशाली कार्यवाही हम कर सकते हैं, कर रहे हैं ।

श्री गिरिराज शरण सिंह : क्या मैं प्रधान मंत्री से पूछ सकता हूँ कि क्या वियतकांग द्वारा हाल ही में युद्ध बढ़ाने के कारण, उत्तर वियतनाम में बमबारी के सम्बन्ध में, सरकार की नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी, नहीं ?

Shri Kanwar Lal Gupta : We must condemn the bombing of North Vietnam by America. May I know her views about the supply of arms by China and other countries to Vietcong ? I would also like to know whether Prime Minister had discussed any special proposal with Sri U. Thant or Shri Kosygin to stop this supply; if so, the nature thereof ?

Shrimati Indira Gandhi : The people of Viet Nam are fighting for the sake of their security and so long they are being attacked, we cannot ask them from where they get arms. (**Interruptions**) So far the question of talks with Shri Kosygin is concerned, neither we have put forth any new proposal nor any new thing has come up during these discussions.

Shri Chadra Jeet Yadav : When the opinion of general public in the country as well as in abroad is with the Government of India, whether Government is going to take any initiative for solving this problem in accordance with its conventions ? Whether Government is contemplating to convene any international conference in collaboration with other countries of the world so that this war could be brought to an end and peace is established in that part of the world ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat): We have expressed it in very clear terms that this problem would be solved on the conference table and not in the battle field. So far the question of taking initiative is concerned, we are already in contact with all the countries and we are expressing our opinion. But until the concerned parties are not willing to come to conference table, this type of conference cannot be convened.

Shri Chandra Jeet Yadav : I have asked whether Government of India have put forth any definite proposal, whether they are taking any initative and contemplating to convene a World Conference to gather public opinion ?

Shrimati Indira Gandhi : We can do so, if any useful purpose can be served by the same, but it appears that no useful purpose would be served at this moment.

Shri Maharaj Singh Bharati : In spite of so many appeals, the war of Viet Nam has not been stopped. The sufferings of Americans are no less than the sufferings of Vietnamese. If America feels that it has become a prestige issue for them, whether Government

have advised America, in the capacity of a friendly country, to withdraw from the battle field honourably otherwise there would be more sufferings ?

Mr. Speaker : Shri R. Barua.

श्री रा० बरुआ : क्या श्री ऊ थांट ने अपनी हाल ही की यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा एक साथ युद्ध बन्द करने के बारे में कोई बात कही थी जिसे उत्तर वियतनाम ने भी स्वीकार कर लिया था परन्तु बाद में इस पेशकश को वापिस ले लिया गया और इसलिये अब गतिरोध उत्पन्न हो गया है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे विचार में उत्तर वियतनाम के विदेश मंत्री ने कहा है कि यदि हवाई हमले बन्द कर दिये जायें तो सम्मेलन के सुझाव पर विचार किया जा सकता है ।

श्री नाथ पाई : जब मई 1965 में पहला हवाई हमला किया गया था तभी हमने कहा था कि इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के स्तर पर बातचीत होनी चाहिये । आज सारा विश्व विनाश के निकट है और जैसे-जैसे दक्षिण वियतनाम में अमरीका की हार होती जा रही है, वैसे वैसे खतरा अत्यधिक बढ़ रहा है । अपनी स्थिति स्पष्ट करने और अपने मित्र देशों के साथ मिल कर एक सामान्य विज्ञप्ति जारी करने के सिवाय भारत सरकार ने क्या किया है ? क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि वे कोई लाभप्रद भूमिका क्यों नहीं अदा कर सके ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि विश्व की घटनाओं में रुचि रखने वाले माननीय सदस्य ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है । यदि वह अमरीका और विश्व की स्थिति का अध्ययन करें तो उन्हें पता लगेगा (व्यवधान) संभवतः उन्होंने यहां की स्थिति का भी अध्ययन नहीं किया । लोगों को इस मामले के सम्बन्ध में पर्याप्त चिन्ता है और जो कुछ पहले कहा गया है वह उन घटनाओं के लिये न्यायोचित है ।

श्री नाथ पाई : मैं समझ नहीं सका कि मेरे प्रश्न का उत्तर क्या दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न को अधिक स्पष्ट होना चाहिये था ।

श्री नाथ पाई : इस प्रकार कह देने से मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला । मेरे विचार में हमने कोई बात नहीं सीखी ।

Shri Manubhai Patel : India, being a peace-loving country, can contribute towards settling the world disputes peacefully and in view of this India became the Chairman of International Control Commission. Whether Government would take some concrete steps to solve this problem if present efforts do not prove to be successful ?

Shrimati Indira Gandhi : There are certain prescribed rules under which the International Control Commissions is required to work. We cannot go beyond that.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : आज के अखबारों में यह समाचार है कि राष्ट्रपति जॉनसन ने कहा है "यदि हनोई चाहे तो हम आज ही जिनीवा जा सकते हैं"। क्या इसको अमरीका

की नीति में कोई परिवर्तन माना जायेगा ? क्या हमारी सरकार इसके बारे से सरकारी रूप से जानती है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमने अभी-अभी अखबारों में इसे देखा है और मैं नहीं समझती इससे कोई विशेष परिवर्तन आ जायेगा ।

Shri Madhu Limaye : Presently, the killing of one Viet Cong costs America an amount equal to Rs. 25 lakhs. Have our Government brought it to the notice of the American Government that if Rs. 25 lakhs are invested in the setting up of a factory, it would provide employment to at least 250 unemployed persons ?

Shri B. R. Bhagat : They themselves know that Vietnam oprations are costing them Rs. 100 million daily.

श्री सोनावने : क्या भारत सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि अमरीका वियतनाम में बम्बारी बन्द कर दे तो उत्तर वियतनाम और वियतकांग समझौता करने के लिये तैयार हो सकते हैं ?

श्री ब० रा० भगत : जी हां, ऐसा हमारा अनुमान है ।

श्री मनोहर लाल सोंधी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बौद्धधर्म के आधार पर दक्षिणपूर्व एशिया के साथ भारत के विशेष सम्बन्ध हैं, क्या प्रधान मंत्री ने दक्षिण वियतनाम में बौद्ध नेताओं के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया है, ताकि वर्तमान स्थिति में, जबकि वहां कोई सैनिक हल संभव नहीं है, दक्षिण वियतनाम में सिविल प्राधिकार का निर्माण करने के लिये बौद्ध शक्तियों को इकट्ठा किया जा सके ?

श्री ब० रा० भगत : हम निश्चय ही इस सुझाव पर विचार करेंगे ।

Shri S. M. Joshi : The conditions in Vietnam are deteriorating day by day and America is bound to face defeat. Has the Prime Minister made it clear to the American Government that if the latter persists in its present attitude, India will also have to take a certain position to protect her from the escalation of Vietnam war ?

Shri B. R. Bhagat : We are fully aware of the risk involved and seize every opportunity to voice our apprehensions. The recent utterances of American circles do not indicate the use of atom bombs.

Shri S. M. Joshi : Fear of escalation is there.

Shri B. R. Bhagat : That is, of course, there.

Shrimati Laxmi Kantamma : Has the reaction of the people of America to the Vietnam policy of American Government made any impact on the American Government ?

Shri B. R. Bhagat : The public opinion there must bear upon their Government ?

श्री पीलु मोडी : क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है कि यदि वियतनाम में अमरीकी फौजों की उपस्थिति का भारत में साम्यवादी खतरे को रोकने पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

श्री ब० रा० भगत : किसी खतरे को रोकने के लिये बाहरी सहायता प्राप्त करने में हम विश्वास नहीं रखते । हम स्वयं ही किसी भी संकट का मुकाबिला कर सकते हैं ।

वर्ष 1968–69 के लिए वार्षिक योजना

*32 **श्री देवीकी नन्दन पाटौदिया :** **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री प्रेम चन्द वर्मा : **श्री रमानी :**
श्री उमानाथ : **श्री प० राममूर्ति :**
श्री नायनार : **श्री देवराव पाटिल :**
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968–69 के लिये वार्षिक योजना के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस वर्ष के लिये संसाधनों और विकास प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के लिये पृथक-पृथक कितना धन नियत किया गया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

1968–69 के लिये योजना परिव्यय

*39. **श्री रामभद्रन् :** **श्री मयावन :**
श्री अंबचेजियान : **श्री रमानी :**
श्री उमानाथ : **श्री नायनार :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने 1968–69 के 2246 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय में वृद्धि करने का निणर्य किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो योजना के परिव्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी ;

(ग) क्या योजना आयोग केन्द्रीय योजना के अर्न्तगत योजनाओं के लिए 1,172 करोड़ रुपये को बढ़ा कर 1,300 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ।

(घ) क्या यह भी सच है कि राज्यों की अगले वर्ष की 1,600 करोड़ रुपये की योजना को घटा कर 1,350 करोड़ रुपये कर दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस कटौती पर राज्य सरकारों ने रोष प्रकट नहीं किया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क), (ख), (ग), (घ), और (ङ) : केन्द्रीय तथा राज्य बजटों के प्रस्तुत किये जाने के बाद वर्ष 1968-69 की केन्द्रीय तथा राज्य योजनाओं के परिव्ययों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी । वार्षिक योजना 1968-69 सम्बन्धी दस्तावेज चालू बजट सत्र के दौरान सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या सरकार का ध्यान हमारी वार्षिक योजनाओं के लिये विदेशी सहायता के सम्बन्ध में विश्व बैंक के प्रतिवेदन और श्री जार्ज वूड्स द्वारा हाल ही में दिल्ली में दिये गये वक्तव्यों की ओर दिलाया गया है और इस हद तक अगले वर्ष हमारी विदेशी सहायता पर असर पड़ने की संभावना है । क्या वाशिंग्टन और मास्को, दोनों ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि भविष्य में हमें दी जाने वाली विदेशी सहायता की मात्रा हमारे कार्य पर निर्भर करेगी ?

श्री ब० रा० भगत : संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के अध्यक्ष द्वारा दिये गये वक्तव्यों से हम अवगत हैं । जहां तक सहायता की संभावना का संम्बन्ध है, वित्त मंत्री समय-समय पर अपने वक्तव्य देते रहते हैं । यह सच है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने हमेशा ही इस बात पर बल दिया है कि कोई भी सहायता उसके उपयोग पर निर्भर करती है ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या इसपर असर पड़ेगा ? आपका क्या अनुमान है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : यदि विदेशी सहायता नहीं आती है तो माननीय सदस्य को इस पर अफसोस नहीं होना चाहिये क्योंकि वह हमेशा ही यही कहेंगे कि इसके कारण हम अपना ऋण बढ़ा रहे हैं ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : अगले वर्ष की योजना बनाते समय क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखेगी कि सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजनाओं में पैसा लगाने का अभी तक कोई परिणाम निकला है और इसलिये जब तक पहले लगाई गई पूंजी से कोई लाभ होना आरम्भ न हो नई परियोजनाओं में कोई पूंजी नहीं लगाई जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : बजट के सभापटल पर रखे जाने के पहले इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

श्री हिम्मत सिंहका : 1968-69 की योजना में कितनी विकास दर प्राप्त करने का इरादा है और वह चालू वर्ष के अनुमान के मुकाबिले कैसी है ?

श्री ब० रा० भगत : जैसा कि बताया गया है इस वर्ष विकास की दर पिछले वर्ष की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक है ।

Shri Prem Chand Verma : Will the Government consider the requests of the State Governments for increase in the annual plan allocations ?

Shri B. R. Bhagat : As regards the State Government plans for the allocation of Rs. 590 crores was made by the Centre, but they did not fulfil their commitment for the the matching grants. In the same way the plans of the State Governments also lapsed and the Finance Minister stated that during the next year also a central assistance of the order of Rs. 590. crores will be given. Since the States are not able to raise enough resources, their plans will not make much headway.

श्री रमानी : यदि विश्व बैंक या सार्थ संघ के देशों से संसाधान नहीं मिले तो क्या सरकार स्वीकृत या चालू परियोजनाओं में कटौती करेगी और यदि हां तो उन परियोजनाओं के क्या नाम हैं और किस नीति के आधार पर सरकार ऐसा करने जा रही है ?

श्री ब० रा० भगत : यह सारा प्रश्न काल्पनिक है। हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि चालू योजनाओं में कटौती नहीं की जायेगी।

श्री उमानाथ : माननीय वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया था कि जहां तक संसाधानों का सम्बन्ध है घाटे की अर्थव्यवस्था नहीं की जायेगी। परन्तु हम देखते हैं कि 200 से 300 करोड़ रु० की घाटे की अर्थव्यवस्था की गई है। क्या यह सरकार की असफलता है या सरकार ने उस नीति को छोड़ दिया है ? क्या चालू योजना में सरकार घाटे की अर्थव्यवस्था को संसाधनों के रूप में प्रयोग करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : इन बातों को जानने के लिये माननीय सदस्य को 15 दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी, अर्थात् बजट के पेश किये जाने तक।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य भविष्य के बारे में नहीं अपितु भूतकाल के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या कोई घाटे की अर्थव्यवस्था की गई थी।

श्री मोरारजी देसाई : बजट के समय ये सब लेखे दिये जाते हैं। उस समय ही मेरे सामने पूरा चित्र हो सकता है।

श्री नायनार : राज्यों के लिये प्रस्तावित योजना व्यय से पता चलता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लगभग 100 करोड़ रु० की कमी होगी। इससे राज्यों का विकास कार्य और धीमा हो जायगा और प्रादेशिक विकास भी अधिक असंतुलित हो जायगा। इसको ध्यान में रखते हुए, क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने उनको चालू वर्ष में आवंटित की गई विधियों पर असंतोष व्यक्त किया है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि राज्य योजना व्यय में कमी हुई है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर ही है। जैसा कि मैंने बताया 590 करोड़ रु० की सहायता दी गई थी और राज्यों को भी कुछ संसाधान जुटाने थे। उन्होंने उन संसाधानों को नहीं जुटाया और अन्य साधनों को भी नहीं जुटाया। मैंने यह भी चेतावनी दे दी है कि अगले वर्ष केन्द्रीय सहायता इतनी ही रहेगी और राज्य योजनाओं में और कमी होने की सम्भावना है क्योंकि उनके पर्याप्त संसाधन जुटाने की सम्भावना नहीं है।

Shri Deorao Patil : May I know whether the annual plan is being made agriculture-oriented to raise the agricultural production and whether some amount is being laid in this plan for the procurement of foodgrains at the time of harvest ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : हम यथासम्भव अधिक मात्रा में अनाज खरीद कर भण्डार बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । इससे मूल्यों को समर्थन मिलेगा ।

Shri Rahgvir Singh Shastri : May I know whether some new programmes are also included in the annual plan apart from the programmes already in progress ?

Shri B. R. Bhagat : We try to give priority to the agricultural programmes in the annual plan. The details will be made known at the time of the presentation of the budget.

Shri Ram Charan : May I know whether Government will try to remove the imbalance in the regional development at the time of making allocations in the 4th and 5th five year plans ?

Shri B. R. Bhagat : The aspect of imbalance will be considered in the fourth plan.

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी : क्या योजना आयोग ने चालू परियोजनाओं की जांच की है ? कल ही हमने सुना कि राजस्थान नहर परियोजना को अचानक बन्द कर दिया गया है और हजारों मजदूरों की छंटनी कर दी गई है । क्या वार्षिक योजना बनाते समय इन सब बातों को ध्यान में रखा गया है ?

श्री ब० रा० भगत : वार्षिक योजनाओं में सभी चालू परियोजनाओं को जारी रहने दिया जायेगा । उन्हें बन्द नहीं किया जायेगा ।

Shri Abdul Ghani Dar : Are Government aware that U. S. Government have issued a circular to its leading traders and industrialists to the effect that India Government is in the process of liquidation and that they should safeguard their interests in India ?

Shri B. R. Bhagat : We are not aware of any such circular having been issued.

Shri Sheo Narain : May I know whether the Indian planners will be sent to Russia for training ?

Shri B. R. Bhagat : There is no need to send them for training.

Shri Rabi Ray : May I know whether during the fourth Five year plan Government propose to divert the electric power from domestic consumption to irrigation and supply to drinking water in rural areas ?

Shri B. R. Bhagat : Priority has been given to providing irrigational facilities and drinking water. As regards making a cut in the domestic consumption, it will be known at the time of Budget.

श्री बेदव्रत बरुआ : योजनाओं के आरम्भ से ही सरकारी क्षेत्र ने बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी लगायी । अब यह सूचना मिली है कि योजना को बनाये रखने के नाम पर सरकार द्वारा लगाई गई पूँजी को न्यूनतम कर दिया गया है ।

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना के तैयार हो जाने पर ही राजकीय क्षेत्र को उसका भाग और कार्य उपलब्ध हो सकेगा । जहां तक इस वर्ष की या अगले वर्ष की वार्षिक योजना के सम्बन्ध में नीति सम्बन्धी निर्णय का प्रश्न है इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि जो परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं उनको जारी रखा जायेगा और उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी ताकि उनमें लगाई गई पूंजी का पूरा उपयोग किया जा सके । स्रोतों की उपलब्धता होने पर ही नई परियोजनाओं को आरम्भ किया जा सकता है । लेकिन कुछ परियोजनाओं जैसे उर्वरक और अन्य उद्योगों को जिनसे उत्पादन में वृद्धि होती है प्राथमिकता दी गई है ।

श्री लोबो प्रभु : वित्त मन्त्री ने पहले शिकायत की थी कि हम योजना से बंधे हैं । चूंकि यह चालू वर्ष की योजना का बजट से सम्बन्ध है तो क्या यह निष्कर्ष निकाला जाये कि योजना आयोग वित्त मन्त्री से बंधा है । मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या योजना आयोग ने वित्त मन्त्री का ध्यान देश में फैली बेकारी की ओर दिलाया है और उनसे निवेदन किया है कि इसे हर प्रकार से यहां तक घाटे की व्यवस्था करके भी दूर करना चाहिये ।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं स्वयं योजना आयोग का सदस्य हूँ । योजना आयोग के मन्त्री, उनके सदस्य या मेरे विचारों में कोई भिन्नता नहीं है । अतः यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Hukam Chand Kachwai : There have been agitations by the Government employees in different states of the Country regarding increasing in dearness allowances. Whether Central Government intends to give some financial assistance to those States ? If so, the amount of assistance to be given, because there has been a great econonmic crisis in those States and they are not able to do their work.

Shri B. R. Bhagat : The Finance Minister has told that he is not prepared to give financial assistance to those States for increasing the dearness allowances of their employees.

Shri Hukam Chand Kachwai : There is a great economic crisis and the Government could not work without it.

Shri Morarji Desai : The central Government have not so much resources as to give financial assistance to other States.

भारतीय फिल्म निर्माताओं द्वारा धोखेबाजी

*33. श्री प० गोपालन : श्री नायर :
श्री उमानाथ : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्री 18 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4683 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भारतीय चलचित्र निर्माताओं तथा विज्ञापन अभिकरणों द्वारा 'सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन' का वाणिज्य सेवा के साथ मिल कर की गई कई लाख रुपये की धोखेबाजी के बारे में इस बीच जांच पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उप-पतियां क्या हैं ; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) जी, नहीं, जांच अभी चल रही है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

श्री प० गोपालन : क्या सरकार कोई कार्य प्रणाली का पता लगा रही है कि जिसके द्वारा धोखेबाजी का पता लग सके। यदि हां तो ऐसी धोखेबाजी भविष्य में फिर न हो, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : श्री लंका सरकार इस सम्बन्ध में जाँच कर रहा है और जिन देशों में श्री लंका सरकार ने जांच की है हम उनसे सम्पर्क बनाये हुए हैं । स्थिति को स्पष्ट करने में कुछ समय लगेगा ।

श्री प० गोपालन : चूंकि इस मामले में श्री लंका सरकार का भी हाथ है अतः मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या श्री लंका सरकार से इस सम्बन्ध में कार्यवाही की गई है । यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

श्री के० के० शाह : मैं बता चुका हुं कि भारत सरकार और श्री लंका सरकार दोनों ही इस जांच में रुचि रखती हैं। श्री लंका सरकार जांच कार्य कर रही है और हम उससे सम्पर्क बनाये हुए हैं ।

श्री नायनार : 18 दिसम्बर, 1967 को माननीय मन्त्री ने उत्तर दिया था कि इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस धोखेबाजी में भारत सरकार के कुछ पदाधिकारियों का हाथ है। यदि हां, तो उन पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। क्या जाँच की रिपोर्ट को भी छिपाया जा रहा है ?

श्री के० के० शाह : रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 'सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन' के पदाधिकारी और इस देश के कुछ सिनेमा उत्पादक और विज्ञापक इसमें शामिल हैं । सम्बद्ध अधिकारी श्री लंका सरकार के हैं । जहाँ तक सिनेमा उत्पादकों और विज्ञापकों का सम्बन्ध है वे इसी देश के हैं। इस आरोप के आधार पर जाँच की जा रही है ।

श्री उमानाथ : मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वह सभा को सूचित करेंगे कि वह किस प्रकार की धोखेबाजी के आरोप हैं और उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में जाँच पूरी होने में इस पर निर्णय देने में कितना समय लगेगा ?

श्री के० के० शाह : यह आरोप लगाया गया है कि कुछ सिनेमा के गाने कुछ उत्पादकों के कहने पर यहाँ वाणिज्यक विज्ञापनों में और 'सीलोन ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन' में दोहराये गये हैं और हमारे देश से कुछ अनजानी चिटें भेज कर रुपया प्राप्त किया गया है। इस आधार पर जाँच की जा रही है ।

श्री उमानाथ : वह कब पूरी होगी ?

श्री के० के० शाह : यह कहना बहुत कठिन है । कुछ चीजों के सम्बन्ध में मैं नहीं

कह सकता क्योंकि उनको पसन्द नहीं किया जायेगा। श्री लंका सरकार ने वहां कुछ पदाधिकारियों को भेजा है और जांच जारी है।

Shri Mohammad Ismail : Whether the Minister indicate the names of those firms ?

श्री के० के० शाह : जांच चल रही है।

Shri Madhu Limaye : Who is making the investigation ?

श्री के० के० शाह : श्री लंका सरकार के कुछ पदाधिकारी यहां जांच करने के लिये आये हैं। हम उनके नाम ज्ञात करने में असफल रहें हैं। हमने वित्त विभाग को मामला सौंपा है।

Restrictions on Sikh Employees in U. K.

34. Shri Kanwar Lal Gupta : Shri R. S. Vidyarthi
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Wolverhampton Transport Co. of Britain has forbidden the Sikhs from wearing turban and keeping beard, if they want to keep up their employment ;

(b) whether it is a fact that such restrictions also exist in other parts of U. K.; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh):

(a) Yes, sir.

(b) No, sir.

(c) The matter has been raised by the Indian High Commission at U. K. with the Home Affairs of Britain and Wolverhampton Co-operation.

Shri Kanwar Lal Gupta : What has been the result of the action taken by the Government and the number of people effected as a result of imposing these restrictions ?

Shri Surendra Pal Singh : This matter has been raised with the British Home Office and the Wolverhampton Transport Co. and we have been successful in many such cases and such types of restrictions or ban have been lifted. Now there are only in one or two places where these types of restrictions are still there. We hope that we will be successful in those cases also.

Shri Kanwar Lal Gupta : What is the result in this matter ?

Shri Surendra Pal Singh : No result has come out of it. In this respect matter is being discussed with the Government of U. K. and Wolverhampton Transport Co. Both of us are trying to get this ban lifted.

Shri Kanwar Lal Gupta : There have been people in all the countries to follow religion. In such circumstances whether the Government will make such provision through U. N. or through some other source so that some body's religion may not be interfered as a result of the restrictions imposed in the services on the basis of religion.

Shri Surendra Pal Singh : I am also of the view that there should not be any restrictions on the basis of religion. The Government of Britain is also of the same view, but there are certain other local matter also.

श्री गु० सि०ढिल्लो : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पंजाब की किसी सिख संस्था जैसे सिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी, मुख्य खालसा दीवान और दूसरी संस्थाओं ने ब्रिटेन की कुछ कम्पनियों द्वारा इस कार्यवाही के किये जाने का विरोध किया है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस मामले के सम्बन्ध में विभिन्न संगठनों ने भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है।

आकाशवाणी का भावी स्वरूप

*35. **डा० रानेन सेन** : **श्री वासुदेवन नायर** :
श्री वीरेश्वर कलिता :

क्या सूचना तथा प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के भावी ढाँचे के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) आकाशवाणी के भावी ढाँचे के बारे में सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता, इसके स्वरूप के बारे में बताना कठिन है।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व इस सम्बन्ध में चन्दा समिति ने कुछ सिफारिशें की थीं और सभा में उनके सम्बन्ध में कुछ चर्चा भी की गई थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार को कोई निर्णय लेने में इतना अधिक समय क्यों लगता है ?

श्री के० के० शाह : चंदा समिति ने पाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। हमने उसके चार प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में की गयी लगभग सब सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है। इस प्रतिवेदन की केवल 22 सिफारिशों के सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया है। चर्चा जारी है और हमें आशा है कि इस सम्बन्ध में यथाशीघ्र निर्णय ले लेंगे।

डा० रानेन सेन : उन सिफारिशों में बी० बी० सी० की भांति एक स्वायत्त शासी निकाय बनाने की भी मुख्य सिफारिश की गई थी। क्या इस महत्वपूर्ण सिफारिश के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय लिया है ?

श्री के० के० शाह : जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस सम्बन्ध में मेरे तथा वित्त विभाग के बीच चर्चा हो रही है।

डा० रानेन सेन : इस सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने में बहुत समय लग रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय लेने में इतना समय क्यों लगा रही है ?

श्री के० के० शाह : इसका कारण यह है कि उसका आशय बहुत विस्तृत है और सब पहलुओं के विभिन्न आशयों पर ध्यान देना होता है।

वासुदेवन नायर : यह सर्व विदित है कि भारत सरकार और केन्द्र स्थित सत्तारूढ़ दल द्वारा ऑल इंडिया रेडियो का प्रयोग प्रचार के लिये किया जा रहा है। ऑल इण्डिया रेडियो को स्वायत्त शासी बनाने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का

सब मान्यता प्राप्त दलों के नेताओं से इसको निष्पक्ष रूप से प्रयोग करने के सम्बन्ध में चर्चा करने का प्रस्ताव है।

श्री के० के० शाह : माननीय सदस्य द्वारा दिये गये प्रथम सुझाव से मैं सहमत नहीं हूँ। इसके विपरीत मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि ऑल इण्डिया रेडियो के कार्य से सब राज्य सरकारें सन्तुष्ट हैं। विपक्षी दलों के नेताओं से हुई बात को भी ध्यान से नहीं निकाला गया है।

श्री रंगा : माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उन्हें राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करनी चाहिये।

श्री वीरेश्वर शाह : माननीय मन्त्री ने यह बताया कि चन्दा समिति ने कुछ सिफारिशें की थी और उनमें से कुछ सरकार ने स्वीकार कर ली हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ने कौन-सी सिफारिशें स्वीकार की हैं ?

श्री के० के० शाह : कुछ सिफारिशों पर लिये गये निर्णयों को सभा-पटल रख दिया गया है और कुछ को सभा-पटल पर रख दिया जायेगा। लगभग 500 सिफारिशों में से केवल 22 सिफारिशों पर निर्णय लेना बाकी है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या चंदा समिति के सिफारिशों के अतिरिक्त, माननीय मंत्री विभिन्न पहलुओं जैसे ऑल इण्डिया रेडियो के कलाकारों की सेवा की शर्तें इत्यादि के विषय में भी विचार कर रहे हैं। अभी हाल ही में कन्नड़ भाषा के समाचार प्रसारित करने वाले ऑल इण्डिया रेडियो के कलाकार, श्री जोशी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी परन्तु उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि वह अस्थायी कलाकार थे। क्या सरकार ने ऑल इण्डिया रेडियो के कलाकारों को स्थायी घोषित करने के लिये कोई निर्णय लिया है ताकि उन्हें पेन्शन इत्यादि मिल सके।

श्री के० के० शाह : श्री जोशी जी की पत्नी को उसी दिन 1,000 रुपये दिये गये थे। कर्मचारियों की कठिनाइयों के सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है।

श्री बलराज मधोक : माननीय मंत्री ने बताया कि विपक्षी दलों से परामर्श किया गया। वह परामर्श औपचारिक था या अनौपचारिक ? दूसरे, क्या सब चन्दा समिति की इस सिफारिश का कि ऑल इण्डिया रेडियो को बी० बी० सी की भाँति स्वायत्त शासी बना देना चाहिये, सब सदस्यों ने समर्थन किया है। जब सब विपक्षी दल एकमत हैं तो और क्या परामर्श की आवश्यकता है ?

श्री के० के० शाह : सब विपक्षी दलों के ऐसे विचार नहीं हैं। वे सब औपचारिक परामर्श थे और मैं उनकी जानकारी नहीं देना चाहता।

श्री नाथ पाई : एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने यह बताया था कि ऑल इण्डिया रेडियो को स्वायत्त निगम बनाने के सम्बन्ध में चन्दा समिति की सब सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। मेरे विचार में समिति ने इस सम्बन्ध में सब पहलुओं पर विचार कर स्वायत्त निगम स्थापित करने का एक मत से सिफारिश की है। केवल मोरारजी देसाई के

आशय से नहीं। अब कहा जाता है कि वित्त मन्त्रालय से परामर्श किया जा रहा है। स्वायत्त निकाय को निर्माण करने के सम्बन्ध में वित्त मंत्रालय की अनुमति का अधिक महत्व नहीं है। क्या आपका इसे स्वीकार करने का विचार है? सिफारिश का वित्तीय पहलू दूसरी बात है। मुख्य बात भारत के स्वायत्त निगम की स्थापना है। वित्तीय पहलुओं के सम्बन्ध में आप विचार कर रहे हैं या आपने जो समिति नियुक्त की है वह विचार कर रही है?

श्री के० के० शाह : समिति के विचार को यथासम्भव प्राथमिकता दी जायगी। समिति को साक्ष्यों के सम्बन्ध में विचार करने का अधिकार है। दुर्भाग्य से साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनको बरबाद कर दिया गया था। जो सामग्री उपलब्ध थी, मुझी को एकत्रित करनी पड़ी।

Shri Shri Chand Goel : The hon. Minister has just told that all the opposition parties are not in favour of establishing an autonomous Corporation. I want to know the parties who have opposed it.

श्री के० के० शाह : यह वक्तव्य सच नहीं है। वह परामर्श अनौपचारिक था। मैं उसको गुप्त रखना चाहता हूं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

आसाम-पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों का तैनात किया जाना

*36. श्री लीलाधर कटकी : श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री श्रीगोपाल साबू : श्री शशिभूषण बाजपेई :
श्री मणिभाई जे० पटेल : श्री हरदयाल देवगुण :
श्री गार्डिजगन गौड : श्री सीताराम केसरी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान के प्राधिकारियों ने आसाम-पूर्वी पाकिस्तान की समूची सीमा पर हाल में और अधिक सैनिक तैनात कर दिये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि सैनिकों ने सीमा पर, विशेषकर कछार और गारो पहाड़ियों के क्षेत्रों में, जमीनदोज मोर्चे बना लिये हैं और खाइयाँ खोद ली हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि ताशकन्द घोषणा के बाद सैनिकों का यह नया जमाव सबसे अधिक बताया जाता है; और

(घ) यदि हां तो भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ग) आसाम-पूर्वी पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेनाओं का कोई असाधारण जमाव का सार्थक सैनिक कार्यकलाप हमारे नोटिस में नहीं आया है।

(घ) अपनी सीमा के उस पार सैनिक संवर्धनों का सतर्कता से ध्यान रखा जाता है, और देश की सुरक्षा को सुरक्षित रखने के उचित उपाय किये जाते हैं ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान

*37. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री राममूर्ति : **श्री चक्रपाणि :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान योजना आयोग के सदस्य, श्री वेंकटरामन के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सरकार चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने में गैर-सरकारी क्षेत्र का सहयोग लेने के बारे में सोच रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) जी हां । क्रमिक योजनाओं की तैयारी से सम्बन्धित गैर-सरकारी क्षेत्र-कार्यक्रमों के बारे में गैर सरकारी क्षेत्र के प्रमुख सदस्यों तथा संगठनों से परामर्श करना एक साधारण बात रही है । चौथी योजना की तैयारी में, गैर-सरकारी क्षेत्र से इसी प्रकार की सलाह-मशवरा करने का प्रस्ताव है ।

ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायोग के प्रथम सचिव का निष्कासन

*38. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री समर गुह :**
श्री मयावन : **श्री अंबचेजियान :**
श्री बलराज मधोक : **श्री निहाल सिंह :**
श्री रा० रा० सिंह देव : **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री न० कु० सालवें : **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री जुगल मण्डल : **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री न० कु० सांधी :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढाका स्थित भारतीय उप-उच्चायोग के प्रथम सचिव, श्री पी० एन० ओझा, के पाकिस्तान से निष्कासन के क्या कारण थे; और

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) 6 जनवरी 1968 को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने ढाका-स्थित भारतीय उप हाई कमीशन के प्रथम सचिव, श्री पी० एन० ओझा को पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध कार्यवाहियों में कुछ पाकिस्तानियों को कथित सहायता देने के लिये तत्काल निकाल दिये जाने की मांग की ।

भारत सरकार ने श्री ओझा के विरुद्ध आरोपों से स्पष्ट इनकार किया और श्री ओझा को निकाले जाने की पाकिस्तान सरकार की अनावश्यक मांग के खिलाफ विरोध प्रकट किया ।

प्रधान मंत्री के साथ शेख अब्दुल्ला की बातचीत

*40. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री अंबचेजियान :
श्री सीताराम केसरी :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री रामजी राम :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री शारदा नन्द :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री वसन्त :
श्री रा० स्व० विद्यार्थी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री जो० ना० हजारिका :
श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री राम भज्जन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री क० लक्कपा :
श्री हेम राज :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ना० स्व० शर्मा :
श्री लक्षण लाल कपूर :
श्री रा० क० सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1968 में शेख अब्दुल्ला ने उनसे मुलाकात की थी और बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बार मुलाकात हुई थी ; और

(ग) किन-किन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ तथा क्या-क्या निर्णय किये गये ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) शेख अब्दुल्ला की रिहाई के बाद उनसे मेरी दो बार मुलाकात हुई । पहली मुलाकात 4 जनवरी को और दूसरी 20 जनवरी, 1968 को । बातचीत आम किस्म की थी और कोई निर्णय लिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

मिग-21 विमान

*41. श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री यशपाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मिग-21 विमान के निर्माण में आज तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) देश में निर्मित पहले मिग-21 विमान की परीक्षण उड़ान के लिये मूलत: कौन-सी तारीख निर्धारित की गई थी और क्या बाद में यह तारीख बदली गई और यदि हां, तो कितनी बार ;

(ग) क्या मिग-21 परियोजना की प्रगति में विलम्ब के संबंध में देश के उड्डयन क्षेत्रों में चिन्ता व्यक्त की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) देश में मिग-21 के निर्माण ने शड्यूल के अनुसार और अधिक प्रगति की है। वृहत् संयोजनों से निर्माण की पहली प्रावस्था लगभग संपूर्ण हो चुकी है। उद्संयोजनों तथा विस्तारों से निर्माण की प्रावस्था में अच्छी प्रगति की है। खास पदार्थों से निर्माण की अन्तिम प्रावस्था के अन्तर्गत, विमान उत्पादन रेखा से लगभग 2 वर्षों में बाहर आने शुरू हो जाएंगे।

(ख) वृहत् संयोजनों से संयोजित पहले विमान की परीक्षण उड़ान शड्यूल के अनुसार 1966 में होनी थी। इसका पाबंदी से पालन किया गया था।

(ग) ऐसे टिप्पण का सरकार को ज्ञान नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रपति अयूब खाँ की "फ्रैंड्स नाट मास्टर्स" नामक पुस्तक

*42. श्री रा० स्व० विद्यार्थी : श्री जार्ज फरनेंडीज :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रपति अयूब द्वारा अपनी "फ्रैंड्स नाट मास्टर्स" नामक पुस्तक में भारत के विरुद्ध घृणा का जो चित्र पेश किया गया है क्या उसको निष्प्रभावी बनाने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या भारत सरकार ने अपने विदेश-स्थित मिशनों के माध्यम से पाकिस्तान के राष्ट्रपति के भारत विरोधी विचारों के विरुद्ध व्यापक प्रचार आरम्भ किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) इस पुस्तक में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों पर जाने-माने विचारों को ही व्यक्त किया है और उसमें भारत के बारे में कई गलत बयानियां हैं। भारत सरकार ने गलत-बयानियों का खंडन और पर्दाफाश करने के लिये पर्याप्त कार्रवाई की है और वह ऐसा करती रहेगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

फारस की खाड़ी

*43. श्री प्रेम चन्द वर्मा : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंग्रेजों के इस निर्णय के परिणाम स्वरूप कि वे वर्ष 1971 में फारस की खाड़ी से हट जायेंगे, इस खाड़ी के आधिपत्य के मामले में ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, के बीच हो रहे परामर्शों का सरकार को पता है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस कार्यवाही के फलस्वरूप देश के हितों की किस प्रकार रक्षा करने का विचार है; और

(घ) क्या इस मामले में ब्रिटिश सरकार के साथ कोई परामर्श हुआ है और यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ब्रिटेन की सरकार ने 16 जनवरी 1968 को जो घोषणा जारी की थी और जिसमें उसने अपनी यह मंशा बताई थी कि वह इस खाड़ी से अपनी फौजें हटाना चाहती है, इस क्षेत्र की सरकारों के बीच सलाह मशविरा हुआ है ।

(ख) से (घ) चूँकि यह क्षेत्र भारत के इतने करीब है इस कारण और इस क्षेत्र के ढांचे में परिवर्तन से भारत के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना के कारण, भारत सरकार इन घटनाओं का बारीकी से अध्ययन कर रही है और जिस किसी सरकार से सलाह करने की जरूरत होती है, उससे सलाह करती है और आवश्यकता पड़ने पर सलाह करती रहेगी ।

Attacks by Rebel Nagas

*44 **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of attacks made by the rebel Nagas on the Military and Police Establishments of India in the area inhabited by the Nagas (including Manipur) after the adjournment of the last Session of Lok Sabha :

(b) the number of casualties and the amount of monetary loss suffered on account of these attaks ; and

(c) the steps proposed to be taken for counteracting these attacks ?

The Deputy Minister in the Ministry of External affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

(a) and (b) During the period two incidents were reported of firing by Underground Nagas on armed police patrols in Manipur. There was no loss of life or property.

(c) The State Government and the Manipur Administration are taking necessary steps to prevent the commission of unlawful acts by the Underground Nagas and protect the life and property of citizens. They have issued instructions to Administrative Officers to use police force and, if necessary, call upon the security forces in aid of civil power, to prevent the commission of violent acts.

हांगकांग से निष्कासित भारतीय

***45. श्री यज्ञ दत्त शर्मा :** **श्री ओंकार लाल बेरवा ।**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश निवास सम्बन्धी कानूनों का उल्लंघन करते हुये बहुत से भारतीयों को हांगकांग से निष्कासित किया जा रहा है और उन्हें वहां प्रवेश करने की मनाही कर दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि वहां स्थित भारतीय उच्च आयुक्त इन मामलों में भारतीयों की पर्याप्त मदद नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) :

(क) पिछले छह महीने में 13 भारतीय राष्ट्रिक हांगकांग के हवाई अड्डे पर रोके गये थे । हांगकांग स्थित अपने कमीशन के हस्तक्षेप से इनमें से 8 व्यक्ति रिहा करा लिये गये थे । बाकी 5 भारतीयों को प्रवेश अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इनमें से कुछ तो हांगकांग साधन-हीन परिस्थितयों में अथवा पर्याप्त धन के बिना आये थे; कुछ को इसलिये नहीं घुसने दिया गया कि रोजगार का संतोषजनक प्रस्ताव नहीं था । कुछेक मामले गलत बयानी के भी थे । हांगकांग के अधिकारीगण आप्रवास कानून का उल्लंघन करके हांगकांग में भारतीयों के प्रवेश को वर्जित नहीं कर रहे हैं, बशर्ते कि उन्होंने प्रवेश की जो शर्तें रखी हैं वे पूरी होती हों ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) हांगकांग स्थित हमारे कमीशन ने प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप किया और हांगकाग में जो भारतीय रोक लिये गये थे उनमें से 8 को उनसे रिहा करा लिया । हमारे कमीशन ने इस मामले को हांगकांग के आप्रवासी अधिकारियों के साथ भी उठाया जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी तरफ से अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया है और भारतीयों के प्रति भेदभाव बरते जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता । बहरहाल, उनकी यह सामान्य नीति है कि वे ऐसे विदेशियों को हांगकांग में नहीं घुसने देते जिनके पास पर्याप्त धन न हो और जिनके साधनहीन हो जाने की और हांगकांग सरकार पर बोझ बन जाने की सम्भावना हो या जिनके पास ऐसे रोजगार का निश्चित प्रस्ताव न हो जिसके लिये हांगकांग का कोई निवासी उपयुक्त न हो ।

स्वेज के पूर्व में स्थित ब्रिटिश सैनिक अड्डे

*46. **श्री धीरेश्वर कलिता :** **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री निहाल सिंह **श्री बलराज मधोक :**
श्री मोलहू प्रसाद : **श्री टी० पी० शाह :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने यह निर्णय कर लिया है कि वह स्वेज के पूर्व स्थित अपने सैनिक अड्डों को वर्ष 1971 तक छोड़ देगा;

(ख) क्या यह निर्णय हिन्द महासागर स्थित द्वीप समूहों में प्रस्तावित ब्रिटिश सैनिक अड्डों पर भी लागू होगा;

(ग) क्या सरकार ने इस संभावना पर विचार किया है कि ब्रिटेन इन हिन्द महासागर स्थित अड्डों को अन्तिम रूप से छोड़ने के पहले उन्हें अमरीका को सौंप देगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने यह घोषणा 16 जनवरी 1968 को 'हाउस आफ कामन्स' में की थी । लेकिन 10,000 तैयार सैनिकों का एक दल हांगकांग में बना रहेगा ।

(ख) अवमूल्यन के दबाव का मुकाबला करने के एक कदम के रूप में हिंद महासागर के ब्रिटिश प्रदेश में अलडबरा की योजनाओं पर काम आगे न बढ़ाने के निश्चय की घोषणा नवबंर 1967 में की गई थी । दूसरे द्वीप समूहों के विषय में ब्रिटेन की योजना के बारे में कोई और सूचना सुलभ नहीं है ।

(ग) और (घ) यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमरीका की रक्षा के उद्देश्य से इन द्वीपों की सुलभता के बारे में 30-12-66 को इन दोनों सरकारों के बीच जो करार सम्पन्न हुआ था उसके विषय में हमारी सरकार को मालूम है, और उसने इस क्षेत्र में सैनिक अड्डे बनाने की कथित रिपोर्ट के बारे में अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है। दोनों की सरकारों ने इस बात को अस्वीकार किया है कि वे हिंद महासागर के ब्रिटिश प्रदेश में कोई सैनिक अड्डा बनाना चाहती हैं। उन्होंने कहा है कि दूर पूर्व के साथ संचार सुविधाओं के लिये एक मार्ग केन्द्र स्थापित करने का इरादा है। यूनाइटेड किंगडम ने अलडबरा की यह योजना रद्द कर दी है । भारत सरकार ने इन सब बातों पर ध्यान रखा है; फिर भी, स्थिति पर बराबर निगाह रखी जाती है ।

एक रूसी अध्यापक का देश त्याग

*47. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री स० कुन्डू :**
श्री हेम बरुआ :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक रूसी अध्यापक ने, जो दिसम्बर 1967 में भारत आया था, भारत स्थित ब्रिटिश दूतावास में शरण ली थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत सरकार ने उसे विमान द्वारा ब्रिटेन जाने की अनुमति दी थी; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रूस ने भारत सरकार के निर्णय को गंभीर मामला समझा है और यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) श्री अजीज उलग्जादे नाम का एक रूसी युवक दिसम्बर 1967 में भारत आया था और उसने यूनाइटेड किंगडम के भारत-स्थित हाई कमीशन में शरण लेने की असफल कोशिश की और बाद में संयुक्त राज्य अमरीका के राजदूतावास में प्रश्रय पा लिया ।

(ख) भारत सरकार ने उसे इजाजत दे दी थी कि वह भारत छोड़कर जहां भी जाना चाहे चला जाये ।

(ग) भारत सरकार ने सोवियत सरकार को इस मामले के तथ्यों से पूरी तरह अवगत रखा और उन्हें इस बात का पूरा मौका दिया कि उस व्यक्ति को सोवियत संघ लौटने के लिये

किसी तरह राजी कर सकें तो कर ले । सोवियत राजदूतावास ने इस मामले में भारत सरकार के निर्णय का विरोध-प्रदर्शन किया था । भारत सरकार ने बताया कि उसे अपने कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप ही कार्यवाही करनी पड़ी है । कोई व्यक्ति कहीं भी व्यक्तिगत रूप से इस तरह की कार्यवाही कर सकता है, इससे भारत और सोवियत संघ के वर्तमान मित्रतापूर्ण संबंधों पर बुरा असर नहीं पड़ सकता जो कि आपसी सम्मान और समझ-बूझ की गहरी नींव पर आधारित हैं ।

पाकिस्तान में जातीय संहार

*48. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के बहाने पश्चिम तथा पूर्व पाकिस्तान में प्रति दिन 2000 पुरुष हिन्दुओं की अनिवार्य नसबन्दी करके छलपूर्ण तथा शनैः शनैः जातीय विनाश का कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि केवल ढाका में ही प्रति दिन 200 हिन्दू युवतियों का अनिवार्यतः ट्यूबेक्टोमी आपरेशन (बन्ध्यकरण) किये जाते हैं ; और

(ग) पाकिस्तान में हिन्दू अल्प-संख्यकों के इस धीमे विनाश को रोकने के लिये सरकार का विचार क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) सरकार के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Pakistan's Defence Preparations

*49. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Tulshidas Jadav : **Shri Valmiki Choudhary** :
Shri B. K. Das Chowdhury : **Shri Shiv Kumar Shastri** :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the latest estimate of Pakistan's defence preparations and concentration of forces on the Western and Kashmir borders ; and

(b) whether in view of the recent statements of the Pakistani leaders the likelihood of Pakistan using her defence potential against India has increased recently ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) Since 1965 Pakistan has virtually doubled its land forces which now include 2 armoured divisions. In addition it has a large strength of irregular forces. As far as air strength is concerned, the number of squadrons of modern combat aircraft have also been doubled since 1965. Pakistan has also long term plans for the expansion of its Navy. Apart from maintaning its usual concentrations of armed forces across our borders and the Cease Fire Line in Jammu & Kashmir, Pakistan due to proximity of location is able to move up more forces in a short time.

(b) Government keep a careful watch on activity having a bearing on the security. There is no reason to be alarmed as the bellicose statements of Pakistani leaders are obviously intended to produce this effect on us and keep up the morale of their own country-men.

टेलीविजन स्टेशन

*50. श्री ईश्वर रेड्डी : श्री मोहसिन :
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के मुख्य नगरों में टेलीविजन स्टेशन स्थापित करने के मामले में क्या प्रगति हुई है तथा उन स्टेशनों से कितनी दूरी पर टेलीविज़न के कार्यक्रम देखे जा सकते हैं ; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आकाशवाणी के पास फिलहाल दिल्ली में केवल एक प्रयोगात्मक टेलीविजन केन्द्र है । इसका सितम्बर, 1959 में उद्घाटन किया गया था और इसकी सीमा 40 कि० मी० है । दिल्ली के केन्द्र को मजबूत करने के अलावा अन्य बड़े शहरों में टेलीविजन केन्द्र की स्थापना का काम, आवश्यक स्रोतों, जिसमें विदेशी मुद्रा भी है, की उपलब्धि पर ही, हाथ में लिया जायेगा ।

(ख) आकाशवाणी ने अब तक दिल्ली के टेलीविजन केन्द्र पर 28·4 लाख रुपये खर्च किये । इसमें उस सामान की कीमत नहीं है जो उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ। आवर्ती खर्चा शामिल नहीं किया गया है ।

चीन के साथ सम्बन्ध

*51. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1967 में सीमा पर हुई मुठभेड़ों के बाद भारत के विरुद्ध चीन में शत्रुतापूर्ण प्रचार में कोई स्पष्ट कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या समझौता करने के लिए नये सिरे से पहल करने का सरकार का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) चीन सरकार के वर्तमान रवैये के कारण कोई पहल नहीं की जा सकती ।

मौरल री-आर्मामेंट संगठन के नेता की कोहिमा की यात्रा

*52. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौरल री-आर्मामेंट संगठन के एक नेता 27 दिसम्बर 1967 अथवा उसके आसपास छिपे नागाओं से मिलने के लिए कोहिमा गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उसे किन परिस्थितियों में वहां जाने की मंजूरी दी गई थी ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) नागालैंड राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, श्री राज मोहन गांधी दिसम्बर, 1967 के चौथे सप्ताह में कोहिमा गए थे । उन्होंने संबंद्ध डिप्टी कमिश्नर से यात्रा की अनुमति ले ली थी । सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि श्री गांधी अपने प्रवास में किसी छिपे नागा नेता से मिले थे ।

पश्चिम एशिया के बारे में यूगोस्लाविया के प्रस्ताव

*53. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को पता है कि यूगोस्लाविया ने अनुरोध किया है कि अरब देशों को पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु इसरायल देश के अस्तित्व की वास्तविकता मान लेनी चाहिये ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है और अरब देशों के सामने इस आशय का कोई प्रस्ताव रखा है ; और

(ग) इसरायल के साथ सरकार का कब से दौत्य संबन्ध स्थापित करने का विचार है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार का ख्याल है कि राष्ट्रपति टीटो के प्रस्तावों में पश्चिम एशियाई संकट को हल करने के लिए मुनासिब आधार हैं।

(ग) इसराईल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

स्वेज नहर को पुनः चालू करना

*56. श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री धीरेन्द्र नाथ :
श्री न० कु० सांबी :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वेज नहर में से जहाजों के गुजरने के प्रश्न पर पैदा हुए वर्तमान गतिरोध को दूर करने के लिए कोई प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है ;

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) पश्चिम एशिया का संकट जब से शुरू हुआ है, तब से ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य जगहों पर अन्य देशों से मिलकर स्वीकार्य हल खोजने में सहायता देने की भारी कोशिश की है जिससे कि उस क्षेत्र में स्थायी रूप से शांति और स्थिरता आ जाए। सामान्य नौ परिवहन के लिए स्वेज नहर तब ही खुलने की प्रत्याशा की जाती है जब कि पश्चिम एशिया के संकट का समाधान हो जाए और उस इलाके में शांति और स्थिरता फिर से स्थापित हो जाए ।

(ख) 22 नवम्बर, 1967 को सुरक्षा परिषद ने पश्चिम एशिया पर एक राय होकर एक प्रस्ताव पास किया जिसमें भारत ने साथ दिया। प्रस्ताव की व्यवस्थाओं के अनुसार, महा-सचिव का एक विशेष प्रतिनिधि पश्चिम एशिया के संकट का समाधान करने की दिशा में संबद्ध देशों की राजधानियों में जाता रहा है।

पाकिस्तानी उच्च आयोग के एक अधिकारी का निष्कासन

*57. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री श्रीधरन :
श्री क० लक्कप्पा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढाका से एक भारतीय राजनयज्ञ, श्री ओझा के निष्कासन के तुरन्त बाद जनवरी, 1968 में सरकार ने पाकिस्तानी उच्च आयोग के एक अधिकारी, श्री एम० एम० अहमद को निष्कासित कर दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो श्री अहमद को निष्कासित करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) पाकिस्तान हाई कमीशन के परामर्शदाता, श्री एम० एम० अहमद को 6 जनवरी, 1968 को निकाल दिया गया था ।

(ख) वे जासूसी करने में शामिल थे और भारत में राष्ट्र-विरोधी लोगों को हथियार और रुपया-पैसा बांटते रहे थे ।

Exclusion of Jammu and Kashmir as Part of Indian Territory from U. N. O. Records

*58. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government of India have asked U. N. O. as to the reasons for excluding the areas of Jammu and Kashmir from the territorial data in regard to Indian territory;

(b) if so, the nature of the reply given by U. N. O., and

(c) further action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri B. R. Bhagat) (a) Yes, Sir The matter was taken up with the U. N. Secretariate in 1960 and on several occasions subsequently.

(b) and (c) : The U. N. Secretariat are still examining the matter.

Arab-Israel Conflict

*59. **Shri Shiv Kumar Shastri :** **Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether any appropriate solution of the Arab-Israel conflict has been found out;

(b) whether Israel has put forward certain conditions in regard to this much-awaited solution, which are not acceptable to the Arab countires ; and

(c) If so, the reaction of Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Exterual Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) It is the Government of India's firm belief that there should be an early settlement of the West Asian crisis and Government's efforts have been directed towards achieving an early settlement.

भारतीय प्रवासियों के भविष्य के बारे में भारत तथा सिंगापुर के बीच विचार-विमर्श

*60. **श्री मणिभाई ज० पटेल :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**

श्री चं० चु० देसाई :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा सिंगापुर के बीच इस सम्बन्ध में वार्ताएं हुई हैं कि सिंगापुर गणराज्य से अंग्रेजों द्वारा अपना नौसैनिक अड्डा हटाये जाने के बाद भारत उसे क्या, कैसी तथा कितनी सहायता देगा ;

(ख) क्या भारत मूलक लोगों की बेरोजगारी की समस्या पर भी विचार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलिराम भगत) : (क) और (ख) सिंगापुर के नौसैनिक अड्डे से ब्रिटेन के हटजाने के सम्भावित परिणामों पर सिंगापुर सरकार ने अपनी चिंता प्रकट की है, खासकर इस वापसी के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी की समस्या पर। इसका असर 8000 से भी ज्यादा भारतीय मूल के व्यक्तियों पर पड़ सकता है जो कि इस अड्डे पर जा सकते हैं। इनमें से 3–4 हजार भारतीय नागरिक हो सकते हैं।

(ग) सिंगापुर सरकार पहिले अपने नागरिकों को फिर से नौकरी देने की कोशिश करेगी, जिनमें उनके यहां के भारतीय मूल के नागरिक भी शामिल हैं; वह दूसरे कुशल कर्मचारियों को भी खपाने की कोशिश करेगी। जो लोग अपने देश को वापस जाना चाहते हैं उनकी ग्रेचुइटी और प्राविडेन्ट फंड की वापसी को सुविधाजनक बनाने के भी आदेश उन्होंने दिए हैं। सिंगापुर की सरकार ने हमें आश्वासन दिलाया है कि भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा।

केनिया में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन

257. **श्री न० कु० साल्वे** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केनिया के सभी सिनेमा घरों में भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामलों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिपाहियों तथा अन्य रैंकों के वेतनक्रम तथा भत्ते

259. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों अंगों के सिपाहियों तथा अन्य रैंकों को वर्ष 1947 और वर्ष 1960 में तथा इस समय दिए जा रहे पृथक-पृथक वेतनक्रमों तथा भत्तों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस समय सिपाहियों, नौसैना के रेटिंग तथा वायु सेना के अन्य रैंकों को दी जाने वाली राशन की वस्तुओं तथा वर्दी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपर्युक्त मांग (क) और (ख) उल्लखित वेतनक्रमों में यदि कोई विषमता है तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सशस्त्र सेना में पदोन्नतियां

260. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना के किसी अधिकारी को मेजर, लेफ्टिनेन्ट कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल तथा लेफ्टिनेन्ट जनरल के पद पर पदोन्नत होने में कितने-कितने वर्ष का समय लगता है ;

(ख) डाक्टरी में पूरी तरह योग्य न होने के कारण कितने प्रतिशत अधिकारियों की पदोन्नति नहीं होती है ;

(ग) भारतीय सेना के तीनों अंगों में अधिकारियों के वर्तमान वेतनक्रम क्या हैं तथा उनके वेतनक्रम वर्ष 1947, 1954 तथा 1960 में क्रमशः क्या थे ;

(घ) सेना के तीनों अंगों में मेजर के अथवा उसके बराबर पद पर; लेफ्टिनेन्ट कर्नल के पद पर अथवा उसके बराबर पद पर कर्नल के पद पर, अथवा उसके बराबर पद पर, ब्रिगेडियर अथवा उसके बराबर पद पर, क्रमशः कितने अधिकारी कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) सशस्त्र सेना के तीनों अंगों के अधिकारियों को इस समय दिये जाने वाले, यदि कोई दिया जाता हो, भत्ते का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । (पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 43/68)

आकाशवाणी में भर्ती

261. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 3 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4365 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति 16 नवम्बर, 1967 को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की सभी श्रेणियों की सेवाओं में कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व असाधारणतया अधिक है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भर्ती के केन्द्र हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों में भर्ती केन्द्र खोलने के लिये कार्यवाही की जायेगी ;

(ग) क्या आकाशवाणी की सेवाओं में राज्य-वार प्रतिशतता सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार की यह नीति नहीं है कि सरकारी पदों पर राज्यानुसार प्रतिशत के आधार पर भर्ती की जाए ।

(ग) और (घ) जी, नहीं, राज्यवार प्रतिशतता देना सम्भव नहीं है ।

अम्बाजारी में आयुध कारखाना बनाने के लिए ठेका

262. **श्री अनन्त राव पाटिल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अम्बाजारी-नागपुर में आयुध कारखाना बनाने के लिये ठेकेदारों से प्राप्त चार टेंडरों में से निकवोम मैटल वर्क्स लिमिटेड का टेंडर सब से कम राशि का था ;

(ख) क्या मैसर्स रिचर्डसन एण्ड कुडारु से प्राप्त अन्य टेंडर स्वीकार किया गया था यद्यपि यह तीन लाख रुपये से अधिक का था ; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर सबसे कम राशि का टेंडर अस्वीकृत किया गया और अन्य टेंडर स्वीकार किया गया ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र का जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Manufacture of Television Sets

263. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the cost of the foreign parts for Television sets required to be imported and the names of the models for which they will be imported ;

(b) the types of the television sets which have been manufactured by the Central Electronic Research Institute, Pilani and by adopting their system, at what retail price a person will be able to sell a particular type of a television set ; and

(c) the cost of the foreign parts required to be imported or the manufacture of each television set ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri M. R. Krishna) :

(a) to (c) : Central Electronics Engineering Research Institute Pilani have developed indigenous knowhow for manufacture of TV Sets. Two parties have been licensed to manufacture 10,000 sets each per year based on this knowhow. Central Electronics Engineering Research Institute Pilani have also taken up manufacture of 1000-TV sets on a pilot production basis. These sets are of "black and white" type and are in two sizes-23" Screen and 19" Screen. Their prices are planned to be Rs. 1500/- and Rs. 1350/- respectively. The import content per television set is expected to be about Rs. 250/- for the 23"

receiver and about Rs. 200/- for the 19" receiver to start with and this will be progressively brought down.

कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

264. श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री य० आ० प्रसाद :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री नायनार :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री श्रीनिवास मिश्र :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के चेयरमैन के रूप में भारत ने आयोग को पुनः सक्रिय बनाने के लिये अन्य सदस्यों से बातचीत शुरू की थी ; और

(ख) : यदि हां, तो विभिन्न सदस्य देशों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) और (ख) ; भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन के कार्यों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण कमीशन के अन्य दो सदस्यों, अर्थात् कनाडा और पोलैंड के साथ बराबर संपर्क बनाए हुई है । राजनयिक सूत्रों के जरिये अन्य सरकारों की जो प्रतिक्रियाएँ गुप्त रूप से भेजी जाती हैं, उन्हें बताया नहीं जाता है ।

भारतीय राजनयिकों और सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध पाकिस्तान द्वारा आरोप

265. श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री हेम बरुआ :
श्री समर गुह :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिकों और सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि पूर्वी पाकिस्तान में भारत प्रेरित विद्रोह में उनका हाथ है ; और

(ख) : यदि है; तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) : जी, हां ।

(ख) : भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से इन आदमियों को अस्वीकार किया है और इस

तरह के अनावश्यक और मनगढ़ंत आरोप लगाने के खिलाफ़ पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है ।

Hindi News Bulletin

266. **Dr. Surya Prakash Puri** : **Shri Ramji Ram** :
Shri Ram Avtar Sharma : **Shri Shiv Kumar Shatri** :

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the All-India Radio propose to broadcast Hindi News Bulletins prior to the English news bulletines from Delhi in order to promote Hindi ;

(b) whether it is also a fact that the news in Hindi will be broadcast after being received direct from Hindi news agencies instead of translating them from English ;

(c) if so, when will this scheme be introduced ; and

(d) the details of other measures adopted by the All-India Radio to promote Hindi ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah):

(a) A recommendation made by the Central Hindi Committee that Hindi Bulletins of A. I. R. Should precede bulletins in English will be dully considered by Government. However, some Hindi news bulletins are already being broadcast before the English news bulletins.

(b) and (c) There is a proposal to subscribe to one or more Hindi News Agencies, and a decision is expected to be taken shortly. When the prpoosal is implemented, some of the news items covered by such Agency/Agencies will surely be included in the news bulletins in original instead of translating all the items from English.

(d) The measures adopted to promote Hindi include :

(i) Broadcast of a large variety of Hindi programmes from stations situated in Hindi speaking areas to reach all sections of the people,

(ii) Broadcast of some Hindi programmes including Hindi news Bulletins from stations situated in non-Hindi speaking areas, and

(iii) Supply of Hindi rendered scripts to stations for retranslation into the regional languages concerned for broadcast purposes.

चौथी पंचवर्षीय योजना

267. **श्री देवकीनन्दन पटोदिया** : **श्री बे० कु० दास चौधरी** :
श्री प्रेमचन्द वर्मा : **श्री योगेन्द्र शर्मा** :
श्री यशपाल सिंह : **श्री रा० बरुआ** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब तक तैयार हो जायगा तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के संभावित लक्ष्य क्या हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : चौथी योजना की तैयारी का काम शुरू किया जा चुका है । यह प्रस्ताव है कि चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप सितम्बर 1968 तक तैयार करके राष्ट्रीय विकास परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाये । इस समय लक्ष्य की ओर संकेत करना संभव नहीं है ।

कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग

268. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि कम्बोडिया की सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय आयोग से अनुरोध किया है कि उस देश की क्षेत्रीय अखंडता के अतिक्रमण संबंधी शिकायतों की जांच पुनः आरम्भ की जाये ;

(ख) : यदि हां, तो क्या उस आयोग ने इस विषय में कोई निर्णय किया है ; और

(ग) : क्या नया उत्तरदायित्व लेने के लिये इस आयोग की वित्तीय स्थिति सुधर गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) जो जिम्मेदारियां कमीशन उठाता है, वे 1954 के जेनेवा करार के अन्तर्गत आती हैं और इस विषय में वित्तीय तथा अन्य आवश्यकताओं पर कमीशन विचार करेगा और सह-अध्यक्षों के जरिये जेनेवा सम्मेलन के सदस्यों को इसकी रिपोर्ट देगा ।

चीन द्वारा भारतीय सीमा के साथ-साथ सैनिकों का जमाव

269. **श्री देवकीनन्दन पटोरिया** : **श्री यशपाल सिंह** :
श्री काशीनाथ पाण्डे : **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री जुगल मंडल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जनवरी, 1968 के स्टेट्समैन में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार चीनी सिक्कम, भूटान, नेपाल और भारत की सीमाओं के पास सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कर रहे हैं और पूरी सीमा के साथ साथ थोड़े ही समय में अपनी शस्त्र सेनाओं को ला रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चीन भूटान की सीमा के पास अपनी सेना का जमाव कर रहा है ;

(ग) क्या शिगात्से और त्होका के बीच सड़कों का निर्माण हो जाने से चीन के लिये सिक्कम में नाथूला की सीमा से लगने वाले चुमिथांग क्षेत्र को अपने सैनिक भेजना अब सम्भव हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) हमारी उत्तरी सीमा तथा सिक्किम, भूटान और नेपाल की सीमाओं के पार चीनी सड़क निर्माण कार्य में लगे हैं और वहां पर चीनी सेना बहुत अधिक संख्या में विद्यमान रहती है। चीनी सेना की सैन्य संचालन क्षमता अब बहुत सुधर गई है । सरकार सीमा पार होने वाली चीनी गतिविधियों के प्रति सतत् रूप से जागरूक रहती है जिससे भारत के राज्य क्षेत्र की रक्षा की जा सके और उनकी गतिविधियों के जवाब में कार्यवाही के उपाय खोजे जा सकें ।

परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में अमरीका तथा रूस में समझौता

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री ना० स्व० शर्मा : **श्री शारदा नन्द :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री राम भद्रन : **श्री समर गुह :**
श्री धीरेश्वर कलिता : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री दीवीकन :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री मोहसिन :**
श्री श्रीनिवास मिश्रा : **श्री प० न० सोलंकी :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव : **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री लीलाधर कटकी : **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री श्रीगोपाल साबू : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री यशपाल सिंह : **श्री मधु लिमये :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के बारे में अमरीका और रूस के बीच कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि, हां तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ; उन्होंने जेनेवा में एटमी हथियारों का विस्तार न करने के विषय पर ऐसी ही संधियों के संशोधित मसौदों को पेश किया है ।

(ख) जेनेवा में 18 राष्ट्रों की निरस्त्रीकरण समिति के सम्मुख अमरीका और रूस ने 18 जनवरी, 1968 को संधि का जो संशोधित मसौदा पेश किया था, उसकी एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 44/68]

(ग) जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव नम्बर 2028 (XX) में कहा गया है । संशोधित पाठ पूर्ण रूप से उन सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं हैं जिसपर यह संधि आधारित होनी चाहिए ।

आकाशवाणी से व्यापारिक प्रसारण

271\. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** **श्री रामभद्रन :**
श्री जार्ज फरनेंडीज : **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री काशी नाथ पाण्डे : **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री वेदव्रत बरुआ : **श्री धीरेन्द्रनाथ देव :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री प्र० ना० सोलंकी :**
श्री य० अ० प्रसाद : **श्री रा० रा० सिंह देव :**

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी द्वारा व्यापारिक प्रसारण संबन्धी योजना के कार्यकरण का अब तक क्या अनुभव रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी द्वारा व्यापारिक प्रसारण कुछ और केन्द्रों से भी किया जायगा ; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या आकाशवाणी के विज्ञापनों से समाचारपत्रों की विज्ञापन आय पर प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) रेडियो से विज्ञापन द्वारा आकाशवाणी को अब तक कुल कितनी आय हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण के बम्बई पायलट प्रोजेक्ट के काम का अनुभव पूर्णतः संतोषजनक रहा है । इसकी मांग इतनी है कि वह पूरी नहीं की जा सकती ।

(ख) जी, हां । इस सेवा का किन-किन केन्द्रों में विस्तार किया जाएगा, इसके बारे में अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) आकाशवाणी से वाणिज्यिक विज्ञापनों से समाचार-पत्रों की विज्ञापनों से होने वाली आय में कोई खास फर्क पड़ा मालूम नहीं होता ।

(घ) जनवरी 1968 को समाप्त होने वाली तिमाही में विज्ञापन एजेन्सियों का कमीशन देकर जो शुद्ध आय हुई वह 9,60,000 रुपये थी ।

ढाका में भारतीय दूतावास

272. **श्री न० कु० सांघी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ढाका में भारतीय राजनयिकों/भारतीय दूतावास के कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है : और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कारवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : ढाका-स्थित भारतीय उप हाई कमीशन के अमले के सदस्यों की हमेशा ही कड़ी निगरानी रखी जाती रही है और वह इस वर्ष के आरम्भ से कड़ी कर दी गई है । कई अवसरों पर पाकिस्तान-स्थित भारतीय मिशनों ने भारतीय राजनियकों को परेशान किए जाने की घटनाओं के खिलाफ पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया है जो कि वियना अभिसमय का उल्लंघन है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्वीकृत सिद्धांतों के विरुद्ध है ।

करनाल के लिये ट्रांसमिटर

273. **श्री अदुल गनी दार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को करनाल जिला में एक ट्रांसमिटर कालोनी स्थापित करने के लिये कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह किस से प्राप्त हुआ है और इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) जिला करनाल में पूंडरी के कुछ नागरिकों से उनके नगर में एक ट्रांसमिटर कालोनी स्थापित करने के लिये एक प्रतिवेदन मिला है। हरयाना राज्य में प्रस्तापित ट्रांसमिटर के स्थान के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है ।

संयुक्त राष्ट्र प्रकाशनों पर प्रतिबन्ध

274. श्री प० गोपालन : श्री उमानाथ :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन 'एशिया तथा सुदूर पूर्व में आर्थिक विकास'—'इकाफी' का कार्य' पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) 'एशिया और दूर पूर्व में आर्थिक विकास को सहायता देना'—इकाफे का कार्य'—शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन भारत में नहीं आने दिया गया क्योंकि इसमें ऐसे नक्शे थे जिनमें जम्मू तथा काश्मीर राज्य को भारत से अलग एक पृथक राज्य के रूप में दिखाया गया था और इस तरह भारत की प्रादेशिक आखंडता पर उँगली उठाई गई थी ।

भारत में काम कर रहीं विदेशी संस्थाएं

275. श्री प० गोपालन : श्री गणेश घोष :
श्री उमानाथ :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले विदेशी अभिकरणों, संगठनों और प्रतिष्ठानों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इन संस्थाओं की गतिविधियों पर सरकार का कोई नियन्त्रण है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

नेपाल के गृह-मन्त्री का वक्तव्य

276. **श्री प० गोपालन :** **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री अनिरुद्धन : **श्री चपला कान्त भट्टाचार्य :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेपाल के गृह-मन्त्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि कुछ गैर-जिम्मेदार भारतीय लोग उनके देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री , योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हां ।

(ख) नेपाल के महामहिम की सरकार को यह आश्वासन दे दिया गया है कि भारत सरकार नेपाल के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती । इन आश्वासनों को स्वीकार कर लिया गया है ।

गैर सरकारी पक्षों को दिये गये प्रतिरक्षा संबंधी क्रयादेशों का निष्पादन

277. **डा० रानेन सेन :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को दिये गये प्रतिरक्षा संबंधी क्रयादेशों का निष्पादन वर्ष 1967 के पूर्वार्ध में संतोषजनक नहीं हुआ है ।

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रतिरक्षा सम्बन्धी क्रयादेश बन्द करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1966-67 में गैर-सरकारी क्षेत्र को कितने मूल्य के प्रतिरक्षा संबंधी क्रयादेश दिये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में अणु-शक्ति का विकास

278. **डा० रानेन सेन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में अणु-शक्ति के विकास संबन्धी कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस पर कुल कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) से (ग) चौथी योजना में अणु–शक्ति के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

कच्छ न्यायाधिकरण का पंचाट

279. श्री अद्‌धाकर सूपकार : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री लीलाधर कटकी : श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री श्रीगोपाल साबू : श्री नारायण रेड्डी :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय : श्री न० कु० सांघी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ न्यायाधिकरण ने अपना पंचाट दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह पंचाट कब देगा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान सूचना के अनुसार इस पंच-निर्णय की घोषणा 19 फरवरी, 1968 को होनी है।

भारत में विदेशियों की अचल सम्पत्ति

280. श्री अद्‌धाकर सूपकार : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में विदेशियों तथा विदेशी फर्मों का अचल सम्पत्तियों का अनुमानित मूल्य क्या है ; और

(ख) क्या इस देश में विदेशियों द्वारा अचल सम्पत्ति के अर्जन पर कोई प्रतिबन्ध अथवा सीमा नहीं है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) यह सूचना अभी सुलभ नहीं है और राज्य सरकारों से इकट्ठी की जाने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सशस्त्र सेना के लिये नये वेतनमान

281. श्री रमानी : श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री नायनार : श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वायु सेनाध्यक्ष ने नेफा में हाल में दिये गये एक वक्तव्य मे, जो कि स्थानीय समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है, और आकाशवाणी से प्रकाशित

हुआ है, कहा है कि सरकार सशस्त्र सेना के आफिसरों और जवानों के लिये एक महीने के अन्दर नये वेतनमानों की घोषणा करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो नये वेतनमानों की घोषणा कब तक हो जाने की संभावना है और उनका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) और (ख) जी, नहीं। वायु सेनाध्यक्ष ने सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों को उपलब्ध कुछ भत्तों और रियायतों में सुधार का जिक्र किया था, जिनके सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

सैनिक संचार व्यवस्था में सुधार

282. श्री वेणी शंकर शर्मा : श्री श्रीगोपाल साबू :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1965 मे पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान हमारी एड्वान्सड् लाइनों में संचार व्यवस्था ने समुचित रूप से काम नहीं किया क्योंकि युद्धरत सेनाओं को भेजे गये वायरलैस सैट पुराने थे ; और

(ग) यदि हां, तो हमारी संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। संचार लाइन के ठीक से काम न करने के जो छुट-पुट मामले हुए थे, उनके स्थान पर संचार के दूसरे साधन जुटा दिये गये थे।

(ख) अपनी संचार व्यवस्था को सुधारने के प्रश्न पर सरकार निरन्तर विचार करती है तथा यह प्रयास किया जाता है कि सशस्त्र सेना को आधुनिकतम तथा विश्वसनीय संचार के उपकरण दिये जायें।

ईरान के माध्यम से पाकिस्तान आने वाले अमरीकी शस्त्रास्त्र

283. श्री दी चं० शर्मा : श्री समर गुह :
श्री प्र० के० देव : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री बलराज मधोक : श्री वसवन्त :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को अमरीका से ईरान के जरिये लड़ाकू विमान, टैंक तथा अन्य शस्त्रास्त्र मिलने वाले हैं जिसका आश्वासन अमरीका के राष्ट्रपति ने उस समय दिया था जब वह हाल में पाकिस्तान रुके थे ;

(ख) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में ईरान के एक जनरल हाल में पाकिस्तान गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) पाकिस्तान ने विगत समय में ईरान के जरिये अमरीकी हथियार और गोला-बारूद प्राप्त करने की जो कोशिशें की है, उनके बारे में सरकार को जानकारी है। बहरहाल, अमरीका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को जिस तरह का आश्वासन दिया है, उसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है।

(ख) शाही ईरानी सशस्त्र सेनाओं के चीफ आफ द सुप्रीम कमांडर्स स्टाफ जनरल बहराम अरियाना ने पाकिस्तान के प्रधान सेनापति के निमंत्रण पर पाकिस्तान की 12 दिन की यात्रा की थी। लेकिन यह मालूम नहीं है कि इस यात्रा का सम्बन्ध पाकिस्तान को अमरीकी हथियार देने से था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत पर आरोप लगाने वाला पाकिस्तान का सुरक्षा परिषद को पत्र

284. श्री रामभद्रन : श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने 29 दिसम्बर, 1967 को संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद् को एक पत्र भेजा था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि भारत ने काश्मीर के लोगों को सताने और तंग करने का नया अभियान आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के पत्र से उत्पन्न हुई गलतफहमी को दूर करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या इस बारे में भारत ने भी पाकिस्तान को विरोध पत्र भेजा है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को 10 जनवरी, 1968 को लिखा है कि पाकिस्तान के पत्र में ऐसे मामलों की चर्चा की गई है जो भारत के निजी क्षेत्राधिकार में आते हैं और जिनका पाकिस्तान से कोई संबन्ध नहीं है और जिनसे भारत के अन्दरूनी मामलों में हस्तक्षेप होता है। उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के पत्र में जो आरोप लगाये गए हैं, वे झूठे और अनावश्यक हैं और भारत सरकार उन पर कोई बात-चीत अथवा पत्र व्यवहार करने को तैयार नहीं है।

दिल्ली नगर निगम का वर्ष 1968-69 का योजना परिव्यय

285. श्री अब्राहम : श्री सत्यनारायण सिंह :
श्री नम्बियार :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम के वर्ष 1968-69 के योजना परिव्यय में बहुत अधिक कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल योजना परिव्यय कितना है ; और

(ग) कटौती करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ख) दिल्ली नगर निगम के वर्ष 1968-69 के योजना परिव्यय के सम्बन्ध में जानकारी की दिल्ली प्रशासन से प्रतीक्षा की जा रही है

Post of Parliament Assistant in I & B Ministry

286. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7386 on the 31st July, 1967 and state :

(a) the date by which the change among Parliament Assistants in his Ministry would be made in the public interest ; and

(b) the educational qualifications of the person working since the 7th May, 1951 and the amount received by him in the form of special allowance and overtime allowance ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) The position is being reviewed from time to time and the present incumbent is being continued in the public interest ; there is only one parliamentary assistant and there is no proposal to change.

(b) B. A. Rupees 7,506.10 Paise; this amonnt, however, does not include the allowances paid during the periods of April, 1953 to March, 1954 and April, 1958 to May, 1961, as the figures for these periods are not readily available.

चीन द्वारा वायु तथा भूमि सीमा का उल्लंघन

287. **श्री यशपाल सिंह : श्री विश्वनाथ पान्डेय :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 6 महीनों में चीन द्वारा भारतीय राज्यक्षेत्रों की वायु तथा भूमि सीमा के उल्लंघन की घटनाओं में वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या उपाय किये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) गत 6 महीनों में चीन ने भारतीय तथा सिक्किम राज्यक्षेत्र का 12 बार उल्लंघन किया । अगस्त और सितम्बर 1967 में नाथूला घटना के दौरान उल्लंघन के मामले अधिक हुए । चीनियों ने एक बार वायु सीमा का उल्लंघन भी किया था । इससे पहले के 6 महीनों में चीनियों ने 6 बार सीमा का उल्लंघन किया था।

(ख) भारत सरकार ने चीन सरकार को इस बारे में विरोध-पत्र दिये थे । चीनियों ने सिक्किम के क्षेत्र पर कब्जा करने का जो दुस्साहस नाथूला में किया था, इसे भी भारतीय सुरक्षा बल ने विफल कर दिया था ।

चीन द्वारा भारत-विरोधी प्रचार

288. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री शिवकुमार शास्त्री :**

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन लगातार भारत विरोधी प्रसारण करता रहता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रचार को निष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, हां।

(ख) इस प्रकार का प्रचार बंद करने और सामान्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मार्ग पर वापस आने की माँग करते हुए विरोध प्रकट करने के अलावा भारत सरकार और उसके विदेश स्थित मिशन चीनी अखबारों, रेडियो और दूसरे माध्यमों द्वारा किए जानेवाले झूठे और विरोधी प्रचार का प्रधिकार करने के लिए हर सुलभ मौके का लाभ उठा रहे हैं।

व्यापारिक प्रसारण सेवा

289. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री प्र० ना० सोलंकी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में व्यापारिक प्रसारण सेवा के विस्तार के लिये सरकार ने क्या योजनायें बनाई हैं ; और

(ख) आकाशवाणी की प्रतीक्षा सूची में ऐसे कितने विज्ञापक हैं जो आकाशवाणी की वाणिज्यिक सेवा में समय पाना चाहते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) वाणिज्यिक प्रसारण के विस्तार करने की योजनाएं सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं।

(ख) फरवरी, 1968 के शुरू में बम्बई में जो विज्ञापनकर्ता वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी संख्या 215 थी।

दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का संगठन

290. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री शिव चन्द्र झा :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने दक्षिण–पूर्व एशिया के देशों से इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए एक संगठन बनाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संगठन के लक्ष्य किस प्रकार प्राप्त किए जाएंगे ;

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में से किसी देश ने इस प्रस्ताव का कोई प्रत्युत्तर दिया है ; और

(घ) इस प्रकार के संगठन की स्थापना से भारत को क्या लाभ होने की आशा है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां । इस क्षेत्र में आर्थिक सहयोग को समुन्नत करने के लिए व्यापक आधार वाले संगठन का विचार प्रस्तुत कर दिया है ।

(ख) आशा है कि इस तरह के संगठन से इस क्षेत्र के देशों में निकट और अधिक लाभदायक सम्बन्धों को समुन्नत करेगा और तटकर संबंधी बातचीत विश्व वस्तु मूल्यों को स्थिर करने आदि के बारे में औद्योगिक दृष्टि से अधिक समुन्नत देशों के मुकाबले में इनकी सौदेबाजी करने की स्थिति भी अच्छी हो जायगी ।

(ग) जी हां । राजनयिक मूत्रों के जरिये और अनौपचारिक बातचीत में हमें कुछ प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है लेकिन इन प्रतिक्रियाओं की जानकारी देना ठीक न होगा क्योंकि वे गोपनीय हैं ।

(घ) दक्षिण और पूर्व एशिया के पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, तकनीकी और अन्य सम्बन्धों को बढ़ाने में भारत का बड़ा हित है । आशा है कि "काउंसिल आफ एशिया" जैसे संगठन का निर्माण करने से क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के ढाँचे के अन्तर्गत इस तरह के सम्बन्ध सुधरने में सहायता मिलेगी । इस क्षेत्र में इस तरह के सहयोग से आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने और आर्थिक दासता से मुक्ति पाने में सहायता मिल सकेगी ।

नेफा में विमानों से सामान गिराने का कार्य

291. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेफा में विमानों से सामान गिराने के कार्य में भारतीय वायु सेना के कितने अधिकारी, कर्मचारी तथा विमान लगे हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना तथा इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने बारी-बारी से नेफा में विमान द्वारा सामान गिराने का प्रयत्न किया था और इस कार्य को करने में असमर्थ होने के कारण प्रयत्न करना छोड़ दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नेफा में भारतीय वायु सेना द्वारा विमान से सामान गिराने के कार्य पर होने वाला व्यय पिछले वर्ष गैर-सरकारी फर्म द्वारा इस कार्य पर होने वाले व्यय की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार नेफा में विमान द्वारा सामान गिराने के कार्य के लिए एक पृथक निगम के माध्यम से गैर-सरकारी फर्म के विमान चालकों तथा अन्य कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करने का है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नेफा प्रशासन की ओर से सामान गिराने का

काम 16 डकोटा विमानों का एक स्क्वेड्रन कर रहा है। ऐसे ऊबड़-खाबड़ स्थानों पर, जहां डकोटा विमान काम नहीं कर सकता, सामान डालने के लिये डाकोटा स्क्वेड्रन की सहायता केरीबो विमान करता है। विमान सेवा को बनाये रखने के लिये विमानचालकों के 16 दल काम पर लगाये गये हैं। प्रत्येक दल में 3 सदस्य हैं जिनमें दो अधिकारी और एक वायु सैनिक होता है।

(ख) जी हां। भारतीय वायु सेना ने सामान गिराने का काम बढ़ते हुए अन्य प्रतिरक्षा सम्बन्धी कार्यों की दृष्टि से बन्द कर दिया था और इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन ने यह काम यह सोचकर बन्द कर दिया था कि जो समझौता किया गया है वह यात्री-सामान एयरलाइन का सामान्य समझौता नहीं है।

(ग) कार्लिंग एयरलाइन्स को प्रति उड़ान के घन्टे के लिये 1-2-1967 से 920.41 रुपये दिया जाता था। इस समय जिस अस्थायी दर से वसूली की जा रही है वह निम्नलिखित है:

डकोटा 939 रुपये प्रति उड़ान का घन्टा

केरीबो 2305 रुपये प्रति उड़ान का घन्टा

(घ) नेफा में विमानों से सामान गिराने के लिये एक पृथक कारपोरेशन बनाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं में निदेशकों के पदों पर वैज्ञानिकों की नियुक्ति

292. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं में ग्रेड एक और ग्रेड दो के निदेशकों के पदों के लिये वैज्ञानिकों की भर्ती के तरीके के बारे में मंत्रालय को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है और उसका ब्यौरा क्या है?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) ग्रेड दो के निदेशक की सीधी भरती के तरीके के विरुद्ध एक ऐसी संस्था से शिकायत मिली थी जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है। प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा नियमों के अधीन इस ग्रेड के लिये सीधी भरती की व्यवस्था है।

ग्रेड दो के निदेशकों में से एक ने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के नाम एक अपील लिखी थी जिसमें उसने यह अनुरोध किया है कि ग्रेड एक के निदेशक के पद पर पदोन्नति के लिये ग्रेड दो के निदेशक के पद पर तीन वर्ष की सेवा संबन्धी जो शर्त है, उसमें ढील दी जाये। प्रतिरक्षा विज्ञान सेवा नियमों में ऐसी शर्त नहीं है। चूंकि ऐसे मामलों की अपील संघ लोक सेवा आयोग को नहीं भेजी जाती इसलिये यह अपील वहीं रोक ली गई और सम्बन्धित अधिकारी को तत्सम्बन्धी सूचना दे दी गई।

अनुसंधान तथा विकास संगठन में निदेशकों के पद

293. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मन्त्रालय के अनुसंधान तथा विकास संगठन में ग्रेड एक और ग्रेड दो के निदेशकों के कितने पद हैं और गत दस वर्षों में इस संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं में नियुक्त किये गये वैज्ञानिकों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(ख) संघ लोक सेवा आयोग को क्या-क्या अर्हताएं बताई गई थीं और ग्रेड एक और ग्रेड दो के निदेशकों के पदों पर नियुक्त वैज्ञानिकों की अर्हताएं क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) गत 10 वर्षों में चार ग्रेड एक के तथा दो ग्रेड दो के निदेशक संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरती किये गये थे। संघ लोक सेवा आयोग को जो अर्हताएं बताई गई थीं, नियुक्त किये गये वैज्ञानिकों के नाम तथा उनकी योग्यताओं का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 45/68]

British Arms for South Affrica

294. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the report published in British Newspapers to the effect that the Brtiish Government intend to supply arms to South Africa ;

(b) whether the intention of the British Government is in conformity with the decisions of United Nations Organisation ;

(c) if not, whether Government have drawn the attention of the Birtish Government and the U. N. Secretary General to this report ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi): (a) Yes, Sir.

(b) But, the British Prime Minister has since catagorically declared in the House of Commons on the 18th December, 1967 that Britain would not go back on the Security Council resolutions and sell arms to South Africa.

(c) and (d) : Do not arise.

Permission Sought by Tibetans to Go to Nepal

295. **Shri Ramji Ram** : **Shri Ram Autar Sharma** :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a party of 400 Tibetans had sought the permission of Government to go to Nepal Via Darchula ;

(b) whether it is also a fact that Government did not give the said permission ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (c) : His Majesty's Government of Nepal sought the Government of India's permission for the

transit through India of about 400 Tibetan Refugees who because of weather conditions wish to travel from one part of Nepal to another. As such transit movement is necessitated by the natural communications in the mountainous areas involved, the permission has been granted.

वायु सेना के कर्मचारियों के वेतनमान

296. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायु सेना के कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या नये वेतनमानों के द्वारा विभिन्न शाखाओं के अधिकारियों के वेतनों में विद्यमान वर्तमान विषमता को दूर करने का विचार है ; और

(ग) नये वेतनमान कब तक लागू हो जायेंगे और उन पर अनुमानतः कुल कितना अतिरिक्त धन व्यय होगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रूसी पत्रिका में लेखों के बारे में मास्को स्थित भारतीय दूतावास द्वारा विरोध पत्र

297. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को स्थित भारतीय दूतावास ने रूस की राजकीय पत्रिका "लिटरेरी गजट" द्वारा कांग्रेस दल के प्रमुख सदस्यों के विरुद्ध, जिनमें मन्त्रिमंडल स्तर के मन्त्री भी सम्मिलित थे, अपयशकारी लेख प्रकाशित किये जाने के प्रति रूस सरकार के विदेश कार्यालय को एक कड़ा विरोधपत्र भेजा था ;

(ख) क्या रूस सरकार ने विरोध को अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सोवियत सरकार की पत्रिका, 'लितरातूरनाया गज़ेता' के जिन लेखों का उल्लेख किया गया है उनकी ओर सोवियत विदेश कार्यालय का ध्यान आकर्षित किया गया था ।

(ख) और (ग) : सोवियत विदेश कार्यालय ने सफाई देते हुए बताया कि यह सोवियत लेखक संघ का मुखपत्र है और उनके व्यवस्थापकों को इस प्रकाशन की सामग्री के चयन की छूट है, और उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं ।

जोर्डन की ओर से पाकिस्तान द्वारा लड़ाकू विमानों की खरीद

298. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हाल में अमरीकी धन से जोर्डन के लिए फ्रांस से 60 मिराज जेट लड़ाकू विमान खरीदे हैं और इस खरीद के पीछे जोर्डन और पाकिस्तान के बीच ऐसा पक्का समझौता हुआ है कि यदि पाकिस्तान का भारत के साथ युद्ध हो जाये, तो पाकिस्तान इन लड़ाकू विमानों का भारत के विरुद्ध प्रयोग करेगा ; और

(ख) हमारी गुप्त सूचना के अनुसार पाकिस्तान के पास इस समय उन विमानों को मिलाकर, जो अन्य मुस्लिम देशों ने वहां मरम्मत के लिए भेजे हैं, अनुमानतः कितने लड़ाकू तथा बमवर्षक विमान हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) सरकार यह नहीं समझती कि इस तरह की जानकारी देना सार्वजनिक हित में है। सरकार को पाकिस्तानी हवाई शक्ति की जानकारी है और वह इससे उत्पन्न होने वाले खतरे का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त कदम उठा रही है।

श्रीमती शीरीं बाई का पाकिस्तान चले जाना

299. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय श्री एम० ए० जिन्ना की बहन श्रीमती शीरीं बाई, जो अब तक पूना में रह रही थीं, पाकिस्तानी नागरिक बन गई हैं और कराची चली गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और उनके साथ जाने वाले उनके परिवार के सदस्यों के नाम क्या-क्या हैं और वे भारत में क्या धन्धा अथवा कारोबार करते थे ;

(ग) श्रीमती शीरीं तथा उनके प्रत्येक रिश्तेदार को जवाहरात सहित कितनी धनराशि अथवा आस्तियां पाकिस्तान ले जाने की अनुमति दी गई अथवा दी जायेगी ;

(घ) क्या अन्य भारतीय मुसलमानों को भी हमारी सरकार से किसी रुकावट अथवा बाधा के बिना पाकिस्तानी नागरिक बनने की सुविधा सुलभ है ; और

(ङ) यदि हां तो ऐसे उत्प्रवास विशेषकर निधियों तथा अस्तियों के स्थानान्तरण के बारे में क्या नियम है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना इकट्ठा की जा रही है।

(घ) और (ङ) : राज्य सरकारें पाकिस्तानी नागरिकता ग्रहण करने के इच्छुक भारतीय राष्ट्र को प्रत्येक मामले पर सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद निर्गम (ऐक्जिट) परमिट देती हैं बशर्ते कि ये लोग भारत-स्थित पाकिस्तानी मिशनों से आवश्यक यात्रा-पत्र प्राप्त कर सकें। पूंजी स्थानान्तरण और धनराशि प्रेषण के विषय पर पाकिस्तान सरकार के साथ कोई करार न होने के कारण ऐसे उत्प्रवासियों की आजकल धनराशि और संपत्ति का स्थानांतरण करने की कई सुविधा सुलभ नहीं है।

पाकिस्तान में जा बसे मुसलमान

300. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले पाँच वर्षों में कितने मुसलमान पाकिस्तान चले गये और वे अपने साथ कुल कितने मूल्य की आस्तियां ले गये ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : सुलभ सूचना के अनुसार पिछले पांच सालों में (दिसम्बर, 1967 के अंत तक) 115, 111 (एक लाख पचास हजार एक सौ ग्यारह) मुसलमान लोग पाकिस्तान गये। सरकार को इसकी जानकारी नहीं है कि वे कुल कितने मूल्य की सम्पत्ति पाकिस्तान ले गये।

Broadcasts in English from All India Radio

302. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minster of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the total length of time increased during the last five years for broadcasts in English from various Stations of the All India Radio ; and

(b) its proportion in relation to the broadcasts in Indian languages from all stations of the All India Radio ?

The Minister of Information and Bradcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) 102 hours and 33 minutes per month mainly due to over all increases in transmission hour at All India Radio Stations. (Other language broadcasts total to 9203 hours 44 minutes per month)

(b) 1.1%

English News Bulletins

303. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in English news bulletins broadcasts from the All-India Radio, the pronounciation of Indian places and names is anglicized ;

(b) whether the attention of Government has been drawn to complaints appearing in the newspaper in this regard; and

(c) if so, the steps taken in the matter ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) to (c) Some complaints against the style adopted by the English Announcers in A. I. R., have been received and some criticism has also appeared in the press. However, besides bringing the criticism/suggestions made in the newspapers to the attention of the newspapers concerned, it is constantly emphasized on them to give more thought to communication than to 'styles' and to learn the correct pronounciation of names.

इंगलैंड में सिखों के प्रति भेद-भाव

304. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैंड वासी सिक्खों के प्रति अपनाये गये भेद-भाव के बारे में शिकायतें हाल में बढ़ रही हैं ;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप जाति, रंग और/अथवा धार्मिक पक्षपातों के कारण उस देश में उनके लिये रोजगार के अवसरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में भारतीय उच्च आयुक्त ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सिक्खों सहित सभी अश्वेत अप्रवासियों के विरुद्ध कुछ न कुछ भेदभाव बरता गया है लेकिन हाल में शिकायतों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) जी हां। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर।

(ग) हमारा हाई कमीशन जब कभी आवश्यक होता है, अलग-अलग मामलों को उठाता है। ब्रिटिश सरकार भी भेदभाव को दूर करने के लिए वैधानिक तथा अन्य उपाय बरत रही है।

रूस से पनडुब्बियां

305. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना को रूस से कोई पनडुब्बी मिली हैं जिनके लिये करार किया गया था ;

(ख) क्या निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सप्लाई हो रही है; और

(ग) इन पनडुब्बियों को चलाने आदि में अब तक भारतीय नौसेना के कितने कर्मचारी प्रशिक्षित किये गये हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) से (ग) उपरोक्त ब्यौरा देना लोकहित की दृष्टि से उचित नहीं है।

हिन्दी में प्रसारण

306. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में हिन्दी प्रसारणों में कोई वृद्धि की गई है; और

(ख) क्या आगामी वर्ष में इनमें कोई वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी, हां। 1967-68 में हिन्दी प्रसारणों में जो वृद्धि की गई है वह संलग्न विवरण में दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 46/68]

(ख) जी, हां। फिलहाल 7-4-1968 से भोपाल स्टेशन से हिन्दी में प्रसारण की

अवधि 25 मिनट प्रति मास बढ़ा देने का प्रस्ताव है । हिन्दी पाठों के प्रसारणों की अवधि बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

प्रतिरक्षा संबंधी उपकरणों का आधुनिकीकरण

307. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चालू वर्ष में प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को आधुनिक ढंग का बनाने तथा नवीनतम प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ख) चालू वर्ष में प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान तथा उपकरण बनाने के लिये यदि कोई कारखाने स्थापित किये गये हैं; तो कितने तथा देश में सामान बनाने की गति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वर्ष में अन्य देशों से प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरण तथा सामान प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) प्रतिरक्षा सम्बन्धी हमारी मांग की तुलना में हमारे पास प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों की स्थिति क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) प्रतिरक्षा सम्बन्धी उपकरणों को आधुनिक ढंग का बनाने के लिये उस प्रयोजन के लिये बनाई गई योजना के तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है । इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी देना लोक हित के विरुद्ध होगा ।

(ख) कुछ नहीं

(ग) केवल उन उपकरणों को, जो देशी संसाधनों से उपलब्ध नहीं है, विदेशों से मंगाकर आवश्यकता पूरी की जा रही है साथ ही विदेशी मुद्रा की बचत पर भी ध्यान दिया जाता है ।

(घ) प्रतिरक्षा की वर्तमान आवश्यकताओं को प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हुये तकनीकी तथा अन्य सुधारों पर ध्यान देते हुये उपकरणों को आधुनिक ढंग का बनाया जा रहा है और ऐसे उपकरण विदेशों से भी मंगाये जा रहे हैं ।

कच्छ न्यायाधिकरण पर खर्च

308. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : कच्छ न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला पेश करने पर अब तक भारत द्वारा कुल कितना धन खर्च किया गया है ?

प्रधान-मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : वास्तविक खर्च का हिसाब अभी तक नहीं लगाया गया है ।

भारत में अमरीकी मिशन का नया उपप्रधान

309 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अमरीकी मिशन के उपप्रधान के पद पर नया व्यक्ति नियुक्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि सरकार को उनका पूर्व परिचय मालूम है तो वह क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी हां ।

(ख) अमरीका के नए उप मिशन प्रमुख, श्री डब्ल्यू एच० वेदर्सवी सूडान में पहले अमरीका के राजदूत थे । इससे पहले 1962 से 1965 तक वह नई दिल्ली स्थित अमरीकी राजदूतावास में सार्वजनिक कार्य परामर्शदाता थे । 1951 से 1961 तक उन्होंने संयुक्त राज्य सूचना एजेंसी के साथ कई पदों पर काम किया ।

प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो

310. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो में कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) इस ब्यूरो में क्या काम होता है ;

(ग) क्या इस ब्यूरो के कर्मचारियों में से बनाया गया विशेष दल प्रधान मंत्री के साथ काम कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) 1020 (राजपत्रित-151 ; अराजपत्रित द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी-551 और चतुर्थ श्रेणी-318)।

(ख) निम्नलिखित मुख्य कार्यों को करते हुये ब्यूरो सरकार तथा समाचार-पत्रों के मध्य सम्पर्क रखने का काम करता है :—

समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचार सम्बन्धित मामलों पर सरकार को परामर्श देता है । सरकार की नीतियां और विकास तथा अन्य गतिविधियों के सम्बन्ध में सूचना देते हुये सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करता है, और सरकार की नीतियों और गतिविधियों की समाचार-पत्रों में प्रकाशित जनता की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में सरकार को सूचित करता है ।

(ग) और (घ) एक उप प्रधान सूचना अधिकारी, एक सहायक सूचना अधिकारी की सहायता से प्रधान मंत्री के सचिवालय तथा त्रिमण्डल सचिवालय और समाचार-पत्रों के मध्य सम्पर्क बनाये रखता है ।

हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी समिति

311. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी के प्रयोग सम्बन्धी मामलों पर मंत्रालय को परामर्श देने के लिये एक समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रादेशिक भाषाओं के बारे में भी ऐसी समितियां बनाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) प्रचार साधनों में तथा उनके माध्यम से हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग सम्बन्धी मामलों पर इस मंत्रालय को सलाह देने के लिये "सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति" के नाम से एक समिति गठित की गई है ।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या एफ; 12 (6)/67-प्रशासन-1 तारीख 12 जनवरी, 1968, जिसमें समिति का ब्यौरा दिया हुआ है, की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 47/68]

(ग) प्रादेशिक भाषाओं के बारे में ऐसी समितियां गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जवानों के लिये हिन्दी की परीक्षा

312. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री अनिरुद्धन :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि सेना का जवान पांच वर्ष में हिन्दी की परीक्षा पास नहीं कर लेता है तो उसे सेवामुक्त कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने जवान अब तक सेवामुक्त किये गये हैं; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के जवानों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Relics of Tantia Tope in British Museum

313. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the "Achkan" and Sword of Tantia Tope, hero of the Freedom Struggle are kept at the British Museum ;

(b) if so, whether Government propose to bring them back to India ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) A private individual had written to Government that this was so. Government are scertainaing the facts.

(b) and (c) The matter will be considered when the facts are ascertained.

Super Jet Aircrafts

314. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the minister of Defence be pleased to state ?

(a) whether it is a fact that the scheme to manufacture super jet aircrafts has been shelved by Government ;

(b) whether it is also a fact that the scheme related to conversion of H. F. jet planes into supersonic planes ;

(c) if so, the expenditure incurred on the scheme before shelving it ; and

(d) the amount further needed for the completion of the scheme ?

The Minister of (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) and (b) No, Sir. An advanced version of the HF. 24 aircraft, designated as HF. 24 Mk. IR is under development in Hindustan Aeronautics Limited. There is also a scheme for manufacture of a new military aircraft to meet the future requirements of the Air Force. Work is in hand to prove basic concents, and wind tunnel testing of models would be commenced shortly. The sanction of the scheme would arise only after the design concents have been proved satisfactorily.

(c) Does not arise.

(d) An estimate of the total expenditure of the project can be made after the preliminary design studies have been completed.

Indians Detained in East Pakistan

315. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Shri Charu Choudhri, Secretary of Noakhali Gandhi Camp, who accompanied Gandhiji to Pakistan in 1946 and who is imprisoned in East Pakistan for the last 21 years is lying in precarious condition there ;

(b) if so, the number of Indians thus detained in East Pakistan for the last 12 years so far ; and

(c) the steps taken by Government in this regard and in the case of Shri Charu Choudhri in particular ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) According to our information, Shri Charu Choudhri of the Noakhali Gandhi Camp who is a Pakistani national and reportedly a Leader of the National Awami Party, was arrested sometime in 1963-64. There is no information about his condition in jail. The Government understands, however, that the general condition of the palitical prisoners in East Pakistan is quite distressing.

(b) and (c) ; According to the information available with the Government of India, there are 43 Indian nationals present under detention in East Pakistan. There may be

more Indian nationals in jail and under detention in both the wings of Pakistan. The Government of Pakistan have been repeatedly requested to furnish full particulars of these Indians, the charges against them, their terms of imprisonment and probable dates of their release. Unfortunately, this information has not so far been made available by the Government of Pakistan.

नागालैंड में शांति समझौता

316. **श्री मयावन :** **श्री समर गुह :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्रोही नागाओं से शांति समझौते की अवधि बढ़ाने का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) क्या नागाओं की बढ़ती हुई आक्रमक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने शान्ति समझौते की अवधि, जो 1 फरवरी, 1968 को समाप्त हो गयी थी, न बढ़ाने का निर्णय किया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) चूंकि कार्रवाई स्थगन करार (युद्ध विराम नहीं) 31-1-68 को समाप्त होना था, इसलिये भारत सरकार ने 27 जनवरी 1968 को कार्रवाई स्थगन करार की अवधि तीन मास अर्थात् अप्रैल 1968 के अंत तक बढ़ाने की घोषणा की । लेकिन इसके बाद, 29-1-1968 को छिपे नागाओं की ओर से यह प्रार्थना मिली कि यह अवधि छः महीने तक बढ़ा दी जाये । करार की अवधि बढ़ाने पर विचार करते समय संविधानिक दृष्टि से चुनी हुई सरकार के जरिये अभिव्यक्त लोगों की इच्छाओं को और कुल मिलाकर विधि और व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है ।

Dalai Lama

317. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Dalai Lama is at present staying at Dharamsala, Kangra, (Himachal Pradesh), and

(b) if so, the total expenditure incurred by the Central Government on his security and lodging etc. so far ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) Government do not consider it to be in good taste to reveal figures of expenditure iucurred on His Holiness the Dalai Lama, who in his capacity of a great revered religious leader, has been received as a guest by the Government and people of this country.

सैनिक भूमि छावनी विभाग

318. **श्री निहाल सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सैनिक भूमि छावनी विभाग के कर्मचारियों की ओर से उस विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं के बारे में 12 मई, 1967 को कोई अभ्यावेदन मिला था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सैनिक भूमि तथा छावनी विभाग के कर्मचारियों की ओर से 12 मई 1967 को सरकार को कोई अभ्यावेदन नहीं मिला था । सैनिक सेवा के एक अस्थायी क्लर्क श्री एच० इ० एल० मुरीशर के नाम से छपा हुआ एक इश्तिहार, जिसका शीर्षक 'संसद के सदस्यों को अपील' था, 12 मई 1967 को मिला था।

(ख) उस अपील में श्री मुरीशर की कुछ व्यक्तिगत शिकायतें उल्लिखित थीं जो अनियमितताओं से सम्बद्ध बताई गई थीं। साथ ही उसमें कुछ सुझाव भी दिये गये थे। आरोपों की जांच से यह ज्ञात हुआ कि आरोप निराधार हैं । अपील के जो मामले सामने आये उनमें से कुछ अब भी विचाराधीन हैं या दीवानी न्यायलय में उनमें विचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Kashmir Shown as Part of Pakistan in Some Foreign Publications

319. **Shri Balraj Madhok** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Kashmir has been shown as a part of Pakistan in the Encyclopaedia Britannica, Time Atlas and Pears Encyclopaedia ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir.

(b) The requisite information is given in the statement laid on the Table of the House **[Placed in the Library See. No. LT- 48/68]**

वियतनाम में मिलीजुली सरकार का प्रस्ताव

320. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 20 वियतनामियों के एक दल द्वारा, जिनमें से अधिकांश दक्षिण वियतनाम की सरकार के भूतपूर्व सदस्य हैं, परिचालित एक प्रस्ताव की एक प्रति अथवा उसकी विषय-वस्तु प्राप्त हुई है जिसमें वियतनाम में बातचीत द्वारा शांति समझौते के लिये दक्षिण वियतनाम की वर्तमान सरकार तथा वियतकोंग नेशनल लिब्रेशन फ्रण्ट की मिली-जुली सरकार का सुझाव दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) सरकार ने इस बारे में अखबारों में खबरें देखी हैं ।

(ख) वियतनाम के प्रश्न पर सरकार के विचार सर्वविदित हैं। हम तो यह चाहते हैं कि वियतनामी लोगों की इच्छाओं के अनुरूप इस समस्या का कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल आये और हमारे विचार से 1954 के जेनेवा करार के अंतर्गत इस उद्देश्य के लिये समुचित ढांचा सुलभ है ।

वियतनाम की लड़ाई में विषैली गैस और विषाक्त पदार्थों का प्रयोग

321. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इन कथित आरोपों की पुष्टि की है कि अमरीकी सैनिक हाल में वियतनाम की लड़ाई में विषैली गैस तथा अन्य विषाक्त पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वियतनाम की लड़ाई में ऐसी गैसों तथा विषाक्त पदार्थों का प्रयोग न होने देने के लिये भारत सरकार ने अमरीका की सरकार से बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) यह पता चला है कि समय-समय पर अन्तर्राष्ट्रीय कमीशन को उत्तर वियतनाम की लोक सेना से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि संयुक्त राज्य अमरीका ने दक्षिण वियतनाम में विषैले रासायनिक पदार्थों और गैसों का प्रयोग किया । लेकिन हाल में इस तरह कोई रिपोर्ट आई मालूम नहीं होती ।

(ख) और (ग) कमीशन अपने कार्यकलापों की रिपोर्टें जेनेवा सम्मेलन के सहअध्यक्षों के पास भेजता है । भारत सरकार को इस विषय पर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

Programme in Sinhalese, Burmese and Pushto

322. **Shri Shasibushan Bajpai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the time allotted by the All India Radio in its daily programmes for broadcasts in Sinhalese, Burmese and language spoken in Pakhtoonistan ; and

(b) whether Government are formulating some special programme or scheme in regard to the broadcasts in the said languages of the neighbouring countries ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

	Service	Duration Hrs.	Mts.
(a)	(i) Burmese	1 —	35
	(ii) Sinhala	0 —	30
	(iii) Pushtu	1 —	30
	(iv) Afghan-Persian	0 —	30

(b) It is proposed to increase the ferquency and duration of services in Pushtu and Afghan-Persian when the Megawatt transmitter becomes available.

Broadcasting Station in Border Areas

323. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of broadcasting station Government propose to set up in border areas ; and

(b) whether Bhutan, Sikkim and Ladakh are also covered under this scheme ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) It has been decided to set up broadcasting stations at 2 new locations in border areas besides setting up additional transmitters or transmitters of higher power at 9 existing centres.

(b) Programmes specially meant for Bhutan and Sikkim are being broadcast from the Kurseong Station of All India Radio and these will be further augmented by some of the border installations proposed to be set up. It is also proposed to set up a broadcasting station in Ladakh to further augment the service already being provided to this area from Srinagar.

Programmes in Languages Spoken in Border Areas

324. **Shri Shashibhushan Bajpai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state the time allotted by the All India Radio in their daily programmes for broadcast in the languages of the people of the border areas i. e. Ladakh, Sikkim, Bhutan and Nagaland ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) : The required information is contained in the enclosed statement. [**Placed in Library. See No. LT 49/68**]

Cantonment Boards

325. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of Cantonment Boards in India ;

(b) whether there is any classification of the Cantonment Boards and if so, the details thereof ;

(c) whether Government are giving any grants to Cantonment Boards and, if so, the basis thereof and the amount of grant being given to the various Boards separately ; and

(d) the amount given as grant to Danapur (Patna, Bihar) Cantonment Board during the last ten years ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) 62.

(b) Yes, Sir. Cantonments are devided into three classes, namely—

(i) Class I, Cantonment in which the civil population exceeds 10,000 ;

(ii) Class II, Cantonment in which civil population exceeds 2,500 but does not exceed 10,000 ;

(iii) Class III, Cantonment in which civil population does not exceed 2,500.

(c) Yes, Sir. Ordinary grants-in-aid are given to the Cantonment Boards to meet the revenue deficit. Special grants-in-aid are sanctioned for developmental works. The amount of grant-in-aid sanctioned to the various Cantonment Boards during 1966-67 is given in the attached statement 'A'.

(d) The information is given in the attached statement 'B'. [**Placed in Library. See No. LT—50/68**]

Danapur Cantt. Board

326. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the size of budget of Danapur (Patna) Cantonment Board for the year 1968-69 ;

(b) the sources of income and the items of expenditure of the Board ;

(c) whether the Board have a deficit budget and if so, the extent of the deficit ;

(d) whether the Board have asked for some help from the Government of India to make up this deficit ;

(e) if so, the amount of the help asked for and the reaction of Government thereto ;

(f) whether the Board have asked for any special help for laying water pipes enlarging the water tank, constructing underground drains and repairing of roads ; and

(g) if so, the amount asked for and the reaction of Government thereto ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) Rs. 4,63,606/

(b) **Sources of Income**

1. Octroi ;
2. Tax on lands and buildings ;
3. Tax on animals and vehicles ;
4. Tax on trades and professions ;
5. Tolls ,
6. Water rate and water tax ;
7. Conservancy tax ;
8. Realization from Hackney Carriages ;
9. Rent from leases ;
10. Sale of trees and grass ;
11. Income from properties ;
12. Fees from educational institutes ;
13. Income from market and slaughter houses ;
14. Sale proceeds of water ;
15. Sale of compost ;
16. Military conservancy ;
17. Grant from State Government for imparting education in the Cantonment.

Items of Expenditure

1. Expenditure on office staff ;
2. Expenditure on tax Department ;
3. Expenditure on maintenance & repairs of Cantt. Fund Properties and expenditure on Public Works establishment.
4. Exependiture on Public safety and convenience comprising of :—
   (i) Lighting ;
   (ii) Markets & Slaughter Houses;
   (iii) Arboriculture ;
   (iv) Rewards for destruction of wild and rabid animals.

5. Sanitation, comprising of :—

(i) Vaccination ;
(ii) Latrines, Drainage, conservancy and scavenging ;
(iii) Water Supply ;
(iv) Military Conservancy.

6. Public instruction ;

7. Contribution of Bonuses, Provident Fund etc.

8. Miscellaneous expenditure viz., Stationery, Printing etc.

(c) The Board has a deficit budget to the extent of Rs. 84,800/.

(d) Yes, Sir.

(e) The Board has asked for an ordinary grant-in-aid of Rs. 93,253/-. Out of this sum, an amount of Rs. 30,000/- has been sanctioned so far. The question of sanction of the balance amount is under condsideration of Government.

(f) and (g) The Cantonment Board has asked for a special grant-in-aid of Rs. 80,000/- for completing its water supply scheme. Out of this amount, GOC-in-C, Central Command has sanctioned Rs. 50,000/- and the question of sanction for the balance amount is under consideration. The Cantonment Board has not asked for any special aid for construction of underground drains, repairs to roads etc.

Danapur Cantt. Board

327. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Defence** be pleased to to State:

(a) whether it is a fact that the people living within the jurisdiction of the Danapur Cantonment Board are experiencing various difficulties in the matter of the education of their Children as the Board has no High School of its own ;

(b) whether the Cantonment Board proposes to ungrade the Middle School at Turtaroli into a High School which has not been possible so far for want of funds ;

(c) whether the Cantonment Board has asked for any help from the Government for this purpose ; and

(d) if so, whether Government are considering any proposal for financial aid for the extension of the building of the said school?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) No, Sir. No representation in this regard has been received by Government.

(b) No such proposal for upgrading the Middle School to High School has been received by Government.

(c) and (b) : Do not arise in view of what is stated in (b) above.

Acquisition of Fertile Lands

328. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in pursuance of the order dated the 13th December, 1962 issued by Home Ministry under the Indian Defence Act 1962, the Government of India acquired fertile land of the farmers of village Mubarkpur, Police Station Danapur, District Patna in the months of May-June, 1964 for constructing an aerodrome there ;

(b) if so, the number of such farmers, their names and the area of the land acquired ;

(c) whether compensation has been paid to the farmers ;

(d) if not, the reasons therefor ;

(e) whether the said land is lying unutilized ; and

(f) if so, whether Government propose to hand over the land back to the said farmers or pay them compensation expeditiously at the present market rate ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) An area of approximately 77 acres of land was requisitioned on lst June 1964 for the construction of accommodation for Army personnel.

(b) to (f) : Rental amounting to Rs. 11,739. 50 per year has been assessed in respect of the lands and has been disbursed for the first year. Information regarding the remaining points is being collected and a statement will be laid on the table of the House.

दरभंगा, गोरखपुर और मोतीहारी में आकाशवाणी केन्द्र

329. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री क० मि० मधुकर :**
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दरभंगा और गोरखपुर में आकाशवाणी के प्रसारण केन्द्र और मोतीहारी में एक स्टूडियो स्थापित करने की योजनाओं में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) काम के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) अभी तक केवल गोरखपुर में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने की योजना स्वीकृत हुई है । इस प्रायोजना के लिये ट्रांसमिटर और स्टूडियो लगाने के हेतु स्थान प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । अपेक्षित उपकरण प्राप्त हो चुके हैं और आशा है कि ट्रांसमिटर के लगाने का कार्य 1970-71 में पूरा हो जायेगा । स्थायी स्टूडियो संभवतः कुछ समय बाद में तैयार होंगे ; सरकार से दरभंगा में भी आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना के लिये वित्तीय मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है ।

चम्पारा-सरन जिलों में स्टूडियो के लिये अति उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं । मोतीहारी के उचित स्थान होने के दावे पर भी विचार किया जायेगा ।

Invitation to Badshah Khan

330. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to State :

(a) Whether Government have invited Badshah Khan to visit India ;

(b) if so the reaction of Badshah Khan in regard thereto ; and

(c) if not, whether Government propose to invite him ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) and (b) : An invitation was extended in January 1965 to Badshah Khan to come

to India at any time convenient to him. Badshah Khan has indicated that he would visit India at a suitable opportunity.

(c) Does not arise.

Defence Research Laboratories

331. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether the targeters for various research projects in research laboratories are fixed in the context of defence needs and priorities and attaining defence self-sufficiency ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) Yes, Sir.

(b) Does not arise.

Defence Laboratories

332. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the major portion of the amount earmarked for defence laboratories is spent on administration and only a small portion thereof is spent on experiments ; and

(b) whether it is also a fact that these laboratories are staffed with more officers than actually required and if so the efforts being made by Government to stop this extravagance and spend more on experiments ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) No, Sir. The administrative expenditure to the total expenditure (excluding capital expenditure in R & D Establishments and Laboratories is approximately 18%.

(b) No, Sis. Posts are created after thorough scrutiny on the basis of load of work in an Establishment. There are about 1000 development projects, research studies and investigations in hand in these Laboratories and establishments at present.

पुरानी तथा अनुपयोगी मोटरगाड़ियां

333. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा विभाग की पुरानी तथा अनुपयोगी मोटरगाड़ियों को बेचने के मामले में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) दिसम्बर, 1967 तक नीलामी द्वारा या अन्य तरीकों से बेची गई जीपों, ट्रकों, लारियों और मोटर साइकिलों की संख्या कितनी है और ऐसी कितनी गाड़ियां शेष हैं जिन्हें बेचा जाना है;

(ग) क्या कुछ पुरानी तथा अनुपयोगी मोटर गाड़ियों को बेचने के बारे में समय पर निर्णय न किये जाने के कारण उनके खुले स्थान पर पड़े रहने से उन पर जंग लग रहा है और वे नष्ट हो रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 3453 पुराने तथा अनुपयोगी मोटरगाड़ियों को जो कि श्रेणी 6 और 7 के अन्तर्गत ऐसी घोषित कर दी गई थीं 1-11-63 से 31.12-67 के दौरान बेची जाने वाली घोषित की गईं। इनमें से 31-12-67 तक 3332 मोटरगाड़ियों बेची गईं। शेष 121 मोटरगाड़ियों को अभी बेचा जाना है।

(ख) श्रेणी 6 अथवा श्रेणी 7 के अलावा 1 नवम्बर, 1963 से 31 दिसम्बर 1967 तक बेचे गये जीपों; ट्रकों, लारियों और मोटर साइकलों की संख्या और 31 दिसम्बर, 1967 को बेचे जाने वालों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	मोटर गाड़ी का प्रकार	बेची गई गाड़ियों की संख्या	बेची जाने वाली गाड़ियों की संख्या
1.	जीपें	6645	2110
2.	ट्रक	8607	2766
3.	लारियां	16428	3017
4.	मोटर साइकिलें	7331	1501

(ग) और (घ) पुरानी और अनुपयोगी गड़ियों को तुरन्त बेचने के लिये भेज दिया जाता है। वास्तविक रूप में बेचने में कुछ समय लग जाता है, क्योंकि कुछ औपचारिकताएँ पूरी की जानी होती हैं। जैसे नीलामी का विज्ञापन, नीलामी, मूल्य का भुगतान और बोली में लेने वाले के द्वारा मोटरगाड़ी का ले जाना। स्थान के उपलब्ध होने या माल के स्वरूप के अनुसार ही उन्हें रखा जाता है। जहां माल को खुले में रखना पड़े तो उसे ढक कर रखा जाता है और उसे खराब होने से बचाने के लिये पूरी कोशिश की जाती है।

टेलीविजन स्टेशन

334. **श्री मणि भाई जे० पटेल : श्री दमानी :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में हुई एक गोष्ठी में इस बात पर जोर दिया गया था कि टेलीविजन का विस्तार भारत में अन्य बड़े नगरो तक किया जा सकता है और इस पर अधिक लागत नहीं आयेगी; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और भारत के अन्य बड़े नगरों में टेलविजन का विस्तार करने पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) सरकार को इस तथ्य का पता है कि दिल्ली में हुई एक गोष्ठी में इस बात पर जोर दिया गया था कि टेलीविजन जन-सम्पर्क का सबसे प्रभावशाली माध्यम है और दिल्ली के केन्द्र को शक्तिशाली बनाने के अतिरिक्त, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में

टेलीविजन केन्द्रों को लगाने के लिये ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। ये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। अनुमान है कि इस सेवा को ऊपर बताये गये बड़े शहरों में इसके विस्तार पर 3.75 करोड़ रुपये खर्च आयेगा।

वैमानिकी सम्बन्धी समिति

335. **श्री न० कु० साल्वे : श्री दमानी :**

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैमानिकी सम्बन्धी समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० न० मिश्र) : (क) जी नहीं। सरकार के संकल्प के अनुसार समिति को 30 अप्रैल, 1968 तक अपना प्रतिवेदन देना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-कानूनी गतिविधियाँ अधिनियम 1967 के अधिनियम पर पाकिस्तान को आपत्ति

336. **श्री न० कु० साल्वे : श्री मधु लिमये :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संसद द्वारा पारित गैर-कानूनी गतिविधियाँ अधिनियम के सम्बन्ध में पाकिस्तान सरकार ने सुरक्षा परिषद् को कोई आपत्ति प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां। पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि ने 28 दिसम्बर 1967 को सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष को एक पत्र लिखा था।

(ख) भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने 10 जनवरी 1968 को सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष के नाम पत्र लिखा है कि पाकिस्तान के पत्र में भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों का जिक्र किया गया है जिनसे पाकिस्तान का कोई सरोकार नहीं और यह भारत के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप है। हमारे स्थायी प्रतिनिधि ने बताया है कि भारत सरकार उनपर कोई बातचीत अथवा विचारों का आदान-प्रदान करने के लिये तैयार नहीं।

प्रचार साधनों के बारे में चंदा समिति का प्रस्ताव

337. **श्री म० कृ० साल्वे : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने चन्दा समिति के इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया है कि विभिन्न प्रचार साधनों के कार्यों को समन्वय के लिये एक केन्द्रीय सूचना बोर्ड स्थापित किया जाये; और

(ख) क्या सरकार इन प्रस्तावों के किन्हीं अन्य विकल्पों के बारे में विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) जी, नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पुनर्गठन सम्बन्धी अन्य सिफारिशों सहित इस सिफारिश पर प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के बाद बिचार किया जायेगा।

चीन के साथ नागाओं की सांठगांठ

338. **श्री रवि राय** : क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि छिपे हुये नागाओं की नेशनल परिषद् की गत जनवरी में हुई बैठक में वाद-विवाद के दौरान लगभग तीस वक्ताओं ने चीन के साथ सांठगांठ करने का समर्थन किया था;

(ख) क्या यह सच है कि चीन ने कहा था कि वह नागाओं की स्वतंत्रता को मान्यता देने के लिये तैयार है और यदि नागा लोग साम्यवाद को अपना लें और भारत सरकार से वार्ता छोड़ दें, तो वह नागाओं को सहायता देने को भी तैयार हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) सरकार के पास सुलभ रिपोर्टों के अनुसार छिपे नागाओं में से कुछ उग्रवादियों ने चीन के साथ सक्रिय रूप से सांठगांठ करने की हिमायत की है जबकि दूसरों ने इसकी निन्दा की है।

(ख) सरकार का ध्यान उन रिपोर्टों की ओर आकर्षित किया गया है जो संभवतः फीजो समर्थक नागा सूत्रों द्वारा जारी की गई हैं कि चीन लोक गणराज्य की सरकार नागालैंड में विद्रोही दल की "मान्यता" पर विचार कर रही है। लेकिन सरकार के पास इस विषय पर ठीक-ठीक कोई जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार का यह पक्का निश्चय है कि वह नागालैंड में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होने देगी जो कि भारतीय संघ का अभिन्न अंग है।

पाकिस्तान के वायुसेनाध्यक्ष का दौरा

339. **श्री रवि राय** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इन समाचारों की ओर दिलाया गया है कि पाकिस्तान के वायुसेनाध्यक्ष, एयर मार्शल नूरखां ने, जिन्हें एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह के साथ बात-चीत के लिये 15 जनवरी, 1968 को दिल्ली आना था अपना दौरा स्थगित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान के वायुसेनाध्यक्ष ने अपना दौरा स्थगित कर दिया है और हमें इसका कारण नहीं बताया गया ।

1968-69 में उड़ीसा के लिए योजना में धन का नियतन

340. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968-69 के लिये उड़ीसा के लिए योजना सम्बन्धी धन का नियतन निश्चित हो गया है ।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्र और राज्य का अंश कितना-कितना है ; और

(घ) राज्य मदवार अपना अंश किस प्रकार पूरा करने के लिये तैयार हो गया है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

1967-68 के लिए उड़ीसा की योजना के लिए धन राशि का नियतन

341. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967-68 के लिये उड़ीसा की योजना के लिये दी गई कुल राशि का उपयोग कर लिया गया है अथवा उसमें से कुछ राशि बची हैं; और यदि हां, तो किन-किन शीर्षकों के अन्तर्गत राशि बची है ;

(ख) वर्ष 1967-68 के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत 20 करोड़ रुपये की राशि का अपना भाग जुटाने के लिये, साधनवार कितनी राशि जमा हुई है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अपना पूरा भाग दे दिया है अथवा उसमें कुछ कमी रही है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) राज्य के हिस्से में कितनी कमी रही थी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) : (क) और (ग) वर्ष 1967-68 के समाप्त होने पर जानकारी उपलब्ध होगी।

(ख) 22 जून, 1967 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3338 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

नौसेना प्रशिक्षण संस्थान को पारादीप ले जाना

342. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना के वर्तमान प्रशिक्षण संस्थान को पारादीप में ले जाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे पारादीप में कब स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इसे किस स्थान से पारादीप में ले जाया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विशाखापटनम ।

भारत और तुर्की के सम्बन्ध

343. **श्री दीवीकन :** **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुर्की के विदेश मंत्री जनवरी, 1968 में भारत आये थे और उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ बातचीत की थी ।

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन विषयों पर बातचीत की थी ; और

(ग) भारत और तुर्की के सम्बन्ध बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : भारत-तुर्की संबंधों को सुधारने के लिए जिन विषयों पर बातचीत की गई और जो उपाय बताए गए, वे 9 जनवरी 1968 को सम्मिलित विज्ञप्ति में दिए गए हैं जो कि तुर्की के विदेश मंत्री की भारत यात्रा की समाप्ति पर जारी की गई थी । सम्मिलित विज्ञप्ति की एक प्रति सदन की मेज पर रख जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 51/68]**

कृषि आय-कर

344. **श्री दीवीकन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि आय-कर लगाने के बारे में योजना आयोग के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से कोई निर्णय कर लिया गया है :

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है : और

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) यह विषय अभी राज्य सरकारों के विचाराधीन है ।

कृषि क्षेत्र के लिये संशोधन

345. **श्री दीवीकन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सच है कि योजना आयोग कृषि क्षेत्र के लिये अधिक संसाधनों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किन-किन मुख्य प्रस्ताओं पर विचार किया जा रहा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी हाँ, । योजना आयोग कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रों के लिये अधिक संसाधन जुटाने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

(ख) 1968—69 सम्बन्धी वार्षिक योजना जिसके साथ योजना आयोग की सिफारिशें भी होंगी चालू सत्र में सभा के समक्ष रख दी जायेंगी ।

यमन के प्रधान मंत्री से संदेश

346. **श्री दीवीकन** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के प्रधान मंत्री को यमन के प्रधान मंत्री ने एक संन्देश भेजा जिसमें भारतीय सहायता तथा सहयोग के लिये अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता मांगी गई और भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) जी हां, ।

(ख) कुछ सुझाव आए हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

Hindi Training Scheme

347. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3647 on the 26th June, 1967 and state :

(a) the reasons for which the employees at various levels do not possess good knowledge of Hindi ;

(b) the number of Officers and other employees as have been imparted training so far under the Hindi Training Scheme of the Ministry of Home Affairs ; and

(c) the time by which the remaining Officers and other employees would be given training in Hindi ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi).

(a) It is difficult to expect an adequate knowledge of advanced Hindi enabling expression with precision and facility, especially of a generation educated before Hindi became the official language of the country.

(b) From December, 1960, to June, 1967, 62 and 51 officials have passed Pragya and Praveen Examinations respectively, under the Hindi Teaching Scheme.

(c) Although progress is being made, it is difficult to indicate any time limit.

विद्रोही नागा नेताओं को चीन जाने की योजना

349. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्रोही नागा सेना तथा विदेश सेवा के नेता मोऊ

अंगामी तथा इशाक सीरू चीन जाने की योजना बना रहे हैं और उन्होंने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान चीनी दूतावास से सम्बन्ध स्थापित किया था ;

(ख) यदि हां, तो जब वे दिल्ली में थे उस समय उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे राष्ट्र विरोधी कार्य को खत्म करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) : छिपे नागाओं और उनकी गतिविधियों से संबद्ध सूचना वर्गीकृत होती है। पिछले दो वर्षों में छिपे नागाओं के जो दल बातचीत करने के लिए दिल्ली आए थे मोवू अंगामी उनमें से किसी भी दल के सदस्य नहीं थे। अक्टूबर 1966 के बाद आइजक स्वू भी दिल्ली बातचीत के लिये नहीं आए।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छिपे नागाओं की गैर-कानूनी कार्यवाहियों को रोकने के लिए भारत सरकार नेसभी आवश्यक कदम उठाए हैं और उठा रही है।

Boats and Ships Impounded by Pakistan During 1965 Indo-Pak Conflict

350. **Shri Sitaram Kesri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Pakistan has replied to the protest note sent by the Government of India in regard to the auction of 184 ships and boats impounded by Pakistan during the 1965 Indo-Pak hostilitses :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the steps Government propose to take to save these 184 ships from being auctioned ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indra Gandhi) :

(a) to (c) : Yes Sir. In their reply, the Government of Pakistan have contended, inter alia, that assets seized during war became the property of the seizing govenment, whose legal right to their disposal is unquestionable. The Government of India have refuted this contentien stating that such a proposition has no support in international law, nor does it conform to State practices. The Government have again called upon thc Government of Pakistan to discuss the question of return of properties and assets seized during the Indo-Pak conflict of August-September, 1965 as provided in the Tashkent Declaration.

नागालैंड में जनमत संग्रह की मांग

351. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री ओं० प्र० त्यागी : **श्री श्रीधरन :**
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैंड के भविष्य का निर्णय करने के लिये छिपे हुए नागाओं ने उस राज्य में जनमत संग्रह कराने की माँग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने छिपे हुए नागाओं के साथ पुनः बातचीत आरम्भ करने के लिये कोई नये प्रस्ताव रखे हैं और यदि हाँ, तो इस मामले की नवीनतम स्थिति क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) नागालैंड में जनमत संग्रह कराने के लिए छिपे नागाओं की ओर से कोई प्रार्थना नहीं की गई है ।

(ख) नागालैंड भारत संघ का अभिन्न अंग है ; इस दर्जे को फिर से निश्चित करने के लिए जनमत संग्रह कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मामले में छिपे नागाओं ने भारत सरकार से कुछ नहीं कहा-सुना ।

श्री लंका से राज्यहीन भारत-मूलक व्यक्तियों का स्वदेश लौटना

353. **श्री हेम बरुआ** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीलंका में राज्यहीन भारत–मूलक व्यक्तियों की स्वदेश वापसी, जिसे जनवरी–फरवरी 1968 तक कार्यरूप दिया जाना था, फिलहाल रोक दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस स्वदेश-प्रत्यावर्तन को कब तक कार्य-रूप देने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी): (क) और (ख) 1964 के भारत-श्रीलंका करार को लागू करने के उनके विधान के अंतर्गत श्रीलंका की संसद द्वारा श्रीलंका विनियमों पर अनुमोदन दे देने के बाद श्रीलंका और भारत की नागरिकता के लिये साथ-साथ ही प्रार्थना-पत्र माँगे जाएँगे । स्वदेश प्रत्यावर्तन नागरिकता प्रदान किए जाने के बाद ही शुरू हो सकता है ।

दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच संयुक्त प्रतिरक्षा करार

354. **श्री हेम बरुआ** : क्या वैदेशिक-कार्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की सरकार ने अगामी दो वर्षों में हिन्द महासागर क्षेत्र में अपने सैनिक, नौसैनिक और वायु-सैनिक संस्थानों को बन्द करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों ने इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एक संयुक्त प्रतिरक्षा करार तैयार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं तथा इस क्षेत्र में भारत क्या कार्यवाही करना चाहता है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) हमें इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश इस क्षेत्र के लिये नया सम्मिलित समझौता तैयार कर रहे हैं । लेकिन, इस बात के संकेत हैं

कि मलेशिया, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और युनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सैनिकों की वापसी के परिमाणस्वरूप उत्पन्न रक्षा की समस्या पर सम्मिलित रूप से विचार करें।

दक्षिण पूर्व एशिया के अपने पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में निजी सम्बन्धों को और अधिक सुदृढ़ करने में भारत का बहुत हित है। गुटों से अलग रहने की अपनी नीति के अनुसार क्षेत्रीय सैन्य प्रबन्ध के बारे में हमारी कोई योजनाएं नहीं हैं ;

प्रधान मंत्री का नेफा का दौरा

355. **श्री हेम बरुआ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले उन्होंने नेफा का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या नेफा में चीनी अतिक्रमण के समाचार के कारण वह वहां गई थीं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ; और

(घ) यदि हां तो उसका क्या परिणाम रहा ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रमाण तथा परीक्षण संस्थान

357. **श्री स० कुन्दू** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदीपुर (समुद्र में) बालासोर स्थित प्रमाण तथा परीक्षण संस्थान में अनुसन्धान का विकास तथा अन्य विस्तार कार्य करने की कोई योजनायें सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार का ब्यौरा क्या है तथा 1967-68 में उसके लिये कितना धन नियत किया गया है तथा 1968-69 के लिए कितना धन नियत किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। बालासोर में प्रमाण तथा परीक्षण संस्थान सम्बन्धी अनुसंधान की योजना पहले ही कार्यान्वित कर दी गई हैं। कुल योजनाओं पर विचार हो रहा है। इनमें से कुछ का उद्देश्य नई तोपों की प्रहार क्षमता बढ़ाने का है और कुछ और तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करने का भी विचार है।

वर्ष 1967-68 के लिये सिविल कार्यों के लिये 6·44 लाख रुपये और 40.50 लाख रुपये स्टोर खरीदने के लिये रखे गये थे। वर्ष 1968-69 के लिये सिविल कार्यों के

लिये 16·67 लाख रुपये और स्टोर खरीदने के लिये 69 05 लाख रुपये रखे जाने पर विचार हो रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

एवरो–748 विमानों का निर्माण

358. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 और 1967 में कानपुर में एवरो-748 विमानों का कुछ और निर्माण हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ; और

(ग) क्या उसका निर्माण बढ़ाने के लिए समुचित कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

(क) जी हां।

(ख) 1966—— 3 विमान
1967—— 4 विमान

(ग) 1968–69 में 6 विमानों के निर्माण का प्रस्ताव है और 1969-70 से इसे बढ़ाकर 7 विमान करने का प्रस्ताव है।

आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों का सेवा सम्बन्धी करार

359. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के प्रसारकों तथा टेलीकास्टर गिल्ड से बात-चीत करने के बाद स्टाफ आर्टिस्टों के नये सेवा करार में कोई संशोधन किया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) नया करार फार्म जिसमें स्टाफ आर्टिस्टों की रिटायर होने की आयु 55 वर्ष, परन्तु सेवाकाल की सीमा 20 वर्ष रखी गई थी, 30 सितम्बर, 1967 को चालू किया गया था। इस फार्म में बीस वर्ष के सेवाकाल की सीमा हटाते हुए 2 नवम्बर, 1967 को संशोधन किया गया था। क्योंकि स्टाफ आर्टिस्ट एसोसियेशन तथा आल इंडिया रेडियो ब्राडकास्टर्स एन्ड टेलीकास्टर्ज गिल्ड समेत सभी स्टाफ आर्टिस्टों ने नौकरी से निकालने के थोड़ी अवधि के नोटिस पर आपत्ति की थी, अतः इस संशोधित फार्म में नौकरी से हटाने के लिये 3 महीने के नोटिस को बढ़ा कर 5 महीने के नोटिस देने का और संशोधन करने का प्रस्ताव है।

राजनैतिक शरण के बारे में विदेशी दूतावासों को जारी की गई हिदायतें

360. **श्री स० मो बनर्जी :** **श्री स० कु० तापड़िया :**
श्री वे० कु० दास चौधरी : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित सभी दूतावासों को ऐसी हिदायतें जारी की गई हैं कि वे भगोड़ों को राजनैतिक शरण नहीं दें ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है तथा हिदायतें जारी करने के क्या कारण थे ; और

(ग) इस बारे में दूतावासों की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी हां ।

(ख) 30 दिसंबर 1967 को भारत-स्थित सभी विदेशी मिशनों को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें उन्हें इस बात की सूचना दी गई थी कि भारत सरकार इस बात को नहीं मानती कि विदेशी मिशनों को अपने अहाते में किसी व्यक्ति को शरण, आश्रय या प्रश्रय देने का अधिकार है क्योंकि यह किसी राजनयिक मिशन के उद्देश्यों में नहीं आता और सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के भी विरुद्ध है। विदेशी मिशनों से कहा गया था कि अगर भविष्य में उनके पास ऐसी कोई प्रार्थना आए तो उसे मंजूर न किया जाए और इसकी सूचना तत्काल विदेश मंत्रालय को दी जाए । यह परिपत्र भारत-स्थित विदेशी मिशनों को इस बात की याद दिलाने के लिए जारी किया गया था कि इस तरह के मामले फिर न होने दें ।

(ग) विदेश मंत्रालय को अभी तक विदेशी मिशनों की इस सम्बन्ध में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है ।

वार्षिक योजना

361. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्याप्त विदेशी सहायता न मिलने के कारण भारत को तीसरी योजना के समाप्त होने के तुरन्त बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आरम्भ करने के स्थान पर वार्षिक योजनायें आरम्भ करनी पड़ी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वार्षिक योजनायें कहाँ तक आन्तरिक साधनों पर आश्रित हैं और यदि विदेशी सहायता पर निर्भर करती हैं, तो कहां तक ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) विदेशी सहायता के बारे में अनिश्चितता एक कारण था ।

(ख) 1966–67 की वार्षिक योजना के लिये आन्तरिक साधनों के 1321 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया और 900 करोड़ रुपये की विदेशी सहायता, प्राप्त हुई । 1967–68 की योजना के लिये तुलनात्मक आंकड़े 1245 करोड़ रुपये और 1001 करोड़ रुपये हैं ।

चीन द्वारा अणु बम का विस्फोट

362. **श्री शिवचन्द्र झा :** **श्री हेमराज :**
श्री निहाल सिंह :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन ने हाल ही में अणु बम का एक और विस्फोट किया है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय राज्य क्षेत्र की सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या भारत चीन के आण्विक आक्रमण का सामना करने की स्थिति में है ; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) जी हां। चीन ने 24 दिसम्बर, 1967 को एक अणु बम का परीक्षण किया था परन्तु इसके वास्तविक स्वरूप के बारे में शंका है।

चीन के आण्विक विकास से हमारी प्रतिरक्षा की व्यवस्था के खतरे पर संसद के पिछले सत्रों में चर्चा हो चुकी है। लोक सभा में 21 जून, 1967 के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा और राज्य सभा के 1 अगस्त, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 184 और 19 दिसम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 623 के उत्तरों की ओर इस सम्बन्ध में ध्यान दिलाया जाता है ।

चीन द्वारा आण्विक हथियारों के विकास से हमारी सुरक्षा व्यवस्था होने के प्रभाव पर सरकार निरन्तर विचार करती रहती है।

भारतीय समाचार पत्र

363. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय समाचार पत्रों में मालिकों की सत्ता के सकेन्द्रण की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिये पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, और

(ख) इस कार्य में कितनी सफलता मिली है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : अपने मूल उद्देश्य के अनुसार भारतीय प्रेस परिषद् ने इस बारे में अध्ययन करना पहले ही शुरू कर दिया है। अगस्त, 1967 में विभिन्न लोगों को जारी की गई प्रश्नावली के उत्तर मिलने पर इसकी रिपोर्ट मुकम्मल होगी । परिषद प्रश्नावली के उत्तरों पर विचार करने के बाद जो सिफारिशें देगी उसको ध्यान में रखते हुए सरकार आगे कार्रवाई करने पर विचार करेगी।

भारतीय दूतावासों के हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

364. **श्री वाल्मीकि चौधरी : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में नियुक्त कितने प्रतिशत व्यक्तियों को कार्य करने योग्य हिन्दी की जानकारी है; और

(ख) क्या अन्य देशों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिये दूतावासों ने हिन्दी की कक्षायें शुरू की हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) विदेश स्थित अधिकांश मिशनों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारी हैं। ठीक-ठीक प्रतिशत

संख्या बताना मुश्किल है क्योंकि कर्मचारियों के स्थानांतरण और आवागमन के साथ स्थिति बदलती रहती है ।

(ख) लंदन, अक्रा और कोलंबो में या तो वहां पर स्थित भारतीय मिशनों द्वारा अकेले ही या इन मिशनों के प्रोत्साहन से हिन्दी की कक्षाएं चलाई जा रही हैं ।

चीन-नेपाल सीमा पर चीनियों द्वारा जेट विमानों के लिये हवाई अड्डों का निर्माण

365. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीनियों ने चीन–नेपाल की समूची सीमा के साथ जेट विमानों के लिए बहुत से हवाई अड्डों का निर्माण कर लिया है ; और

(ख) हवाई हमले की स्थिति में सरकार नागरिकों की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) हमने अपनी प्रतिरक्षा योजना में इस प्रदेश में हवाई हमले के भय का ख्याल रखा है ।

व्यापारिक प्रसारणों के लिए शुल्क

366. **श्री क० प्र० सिंह देव** : **श्री प्र० के० देव** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञापन प्रसारित करने के समय के लिए आकाशवाणी का प्रशुल्क रेडियो सीलोन द्वारा ली जाने वाली दरों से दुगुना है अथवा उससे भी अधिक है : और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :

(क) और (ख) : आकाशवाणी सेवा से विज्ञापनों के प्रसारण की दरें रेडियो सीलोन द्वारा ली जाने वाली दरों से ऊँची हैं, इसका कारण आकाशवाणी की सेवा की श्रेष्ठता और उसके अच्छे प्रभाव का होना है । लोक-प्रिय का कार्यक्रम देने के अतिरिक्त आकाशवाणी का सेवा मीडियम वेव पर प्रसारित की जाती है, परिणामस्वरूप एक बैंड वाले सस्ते मीडियम वेव ट्रांजिस्टरों और रेडियो सैटों की बिक्री में वृद्धि हुई है जिससे रेडियो उद्योग को मदद मिली है और जो रेडियो सीलोन का वाणिज्यिक सेवा के शार्ट वेव सेवा प्रसारणों की अपेक्षा बहुत अच्छी तरह सुना जाता है ।

व्यापार संबंधी प्रसारणों के लिए ठेके

367. **श्री क० प्र० सिंह देव** : **श्री प्र० के० देव** :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से पुराने प्रचार संगठनों को रेडियो से विज्ञापन

देने के लिये मान्यता प्राप्त ठेकेदारों की सूची से बाहर रखा गया है, जब कि नये बने हुए संगठनों को उस सूची में शामिल कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) यह नीति नहीं है। जिन्होंने नियमों का पालन किया है, उनको मंजूर कर लिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Tariq Abdullah

368. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan has decided to appoint Tariq Abdullah, son of Shekh Mohammed Abdullah, as its representative in the U. N. O.;

(b) the present whereabouts of Shri Tariq Abdullah, his nationality and whether his name appears in the electoral rolls of Srinagar; and

(c) the steps taken by Government to prevent Indian nationals from indulging in anti-Indian activities as foreign agents?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Government have no information.

(b) According to our last information, he was in London but we don't know his present whereabouts. As to his present nationality we have no information. His Indian passport stands cancelled since October, 1965.

According to the information received from the State Government, his name appears in the electoral rolls of Srinagar.

(c) whenever an offence is committed under the Indian Law, necessary action is taken against the individual.

Compensation for Indian Soldiers Killed in Gaza

369. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether compensation to the families of the Indian soldiers killed or injured during the Israel-U. A. R. conflict has been paid;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of Defenee (Shri Swaran Singh) :

(a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the details of financial arrangements made is attached. **[Placed in Library. See No.LT—52/68]**

(c) Does not arise.

Changes in Broadcasting Programmes

370. **Shri Y. S. Kushwah :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any changes have been made in the broadcasting programmes as a result of coming into force of the Official Languages Bill passed by Parliament; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) and (b) Not yet, Sir.

Implementation of Tashkent Declaration

371. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the extent to which the Pakistan Government have not implemented the Tashkent Declaration so far; and

(b) the action taken by the Government of India in that regard ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) Most of the provisions of the Tashkent Declaration have remained unfullfiled, due to the insistence of the Government of Pakistan that "meaningful" discussions on the so-called Kashmir dispute should take place first. Among the important provisions which have not been implemented so far due to lack of response from the Government of Pakistan are: non-interference in the internal affairs of India, resumption of trade, return of assets and properties seized during the August 1965 conflict, removal of restrictions on travel, discouraging anti-India propaganda and restoration of air, land and river communications.

(b) The Government of India have expressed their willingness on several occasions to hold unconditional talks with Pakistan about the implementation of the Tashkent Declaration and continue to make all efforts towards this end.

Indian Embassy in Rome

372. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the premises of the Indian Embassy in Rome have been changed;

(b) if so, whether the rent of old and new Embassy buildings is the same or there is a wide difference between the two;

(c) if there is a wide difference in the rent, the reasons for changing the premises ;

(d) whether Government have received any complaints in this regard from the Indians living in Rome ; and

(e) if so, the nature thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi).

(a) Yes, Sir. In February, 1966.

(b) The rent of the new house is a little higher. The total rent of the old house was Rs. 4198.60 (pre-devaluation) per month. The new house was rented at Rs. 4390 (pre-devaluation) per month. After devaluation the rent worked out to Rs. 6913.52 from 6th June 1966 onwards.

(c) The landlord of the old house was not willing to renew the lease on existing rent beyond 7th February 1966.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

तेलगू भाषा की सामयिक पत्रिकायें

373. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेलगू भाषा की विभिन्न सामयिक पत्रिकाओं की संख्या कितनी है और उनके प्रत्येक अंक की कितनी-कितनी बिक्री होती है ;

(ख) देहाती क्षेत्रों तथा जिला मुख्यालयों से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों तथा साप्ताहिक पत्रिकाओं को केन्द्र की ओर से कितनी सहायता तथा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, और

(ग) ऐसी सहायता लेने के लिए विशिष्ट शर्तें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) आवश्यक जानकारी "प्रेस इन इंडिया 1667, भाग-2" की रिपोर्ट जो कि 14 दिसम्बर, 1967,को सदन की मेज पर रखी जा चुकी है, में दी गई है ।

(ख) भारतीय भाषा के छोटे और माध्यम समाचार-पत्रों की उच्चित विज्ञापन सहायता, अखबारी कागज के बटवारे में तरजीह, प्रेस रोलोजा, फीचर लेखों, फोटो कापियों एबोनाइड ब्लाक आदि को नियमित रूप से देकर प्रोत्साहन और सहायता दी जाती है।

(ग) विज्ञापनों को देने के मामले में, प्रकाशन में नियमितता, उत्पादन का उचित स्तर और पत्रकारिता की मान्य नीतियां का पालन देखा जाता है ।

Radio Station in Bundhelkhand

374. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4783 on the 18th December, 1967 and state :

(a) Whether the location of a radio station in Bundelkhand area has since been decided, and

(b) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah) :

(a) No, Sir.

(b) Though a radio station in Bundhelkhand area is included in the draft Fourth Five Year Plan, in the context of current acute scarcity of resources and foreign exchange, it would not be possible for some time to take up the Bundelkhand project for execution.

दक्षिण अफ्रीकी देशों में भारतीय दूतावास

375. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन दक्षिण अफ्रीकी देशों के नाम क्या हैं जो हाल में स्वतंत्र हुए हैं और जहां हमारे देश ने दूतावास स्थापित किया है ।

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जहां ऐसे दूतावास स्थापित नहीं किये गये है । और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा

गांधी) : (क) और (ख) : बोत्स्वाना और लेसोथो, जो पहले बेचुआनालैंड और बसूतोलैंड कहलाते थे, दक्षिण अफ्रीका के दो देश हैं जो क्रमशः 30 सितंबर और 4 अक्तूबर, 1966 को स्वाधीन हुए थे। भारत सरकार ने उन्हें मान्यता दे दी है लेकिन अभी तक वहां कोई मिशन नहीं खोला है।

(ग) किसी दूसरे देश में स्थित अपने प्रतिनिधियों को साथ ही इन देशों में भी प्रत्यायित करने के सवाल पर अभी विचार किया जा रहा है।

कुरनूल में आकाशवाणी केन्द्र

376. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में कुरनूल में एक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) और (ख) : द्वितीय और तृतीय पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश में मीडियम वेव प्रसारण-क्षेत्र बढ़ाने पर विचार करते समय यह ख्याल किया गया था कि रायलसीमा क्षेत्र कार्यक्रम देने के लिए एक मीडियम वेव ट्रांसमिटर लगाने के लिए आन्ध्र प्रदेश में अनंतपुर और कड़पा के साथ-साथ कुरनूल में भी एक संभव स्थान हो सकता है। बाद में वृस्तृत चांच के परिणामस्वरूप राज्य सरकार के परामर्श से ट्रांसमिटर कड़पा में लगाने का निर्णय किया गया और वह जून, 1963 में चालू हो गया।

विशाखापत्तनम में नौसैनिक गोदी

377. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम् में प्रस्तावित नौसैनिक गोदी के बारे में प्रस्तुत किये गये विशेषज्ञों के दल के प्रतिवेदन की जांच पूरी कर ली गई है और उस पर निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) परियोजना प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और वह विचाराधीन है।

Work Done in Hindi in Indian Missions Abroad

378. **Shri Tulshidas Jadhav** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the arrangements that exist at present in the Indian Missions abroad for conducting the work in Hindi, India's Official Language;

(b) the efforts being made for doing correspondence work between the Government of India and the Indian Missions, as well as between Indian Missions and various foreign Governments in the official Language of our country; and

(c) the total number of employees and officers posted in the Indian Missions for handling work in Hindi, the number of Hindi Typewriters and Libraries in each of these Indian

Missions and the number of Indian newspapers and Journals reaching these missions in comparison to those in other languages ?

The Prime Minister, Miniter of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi).

(a) At present, most Indian Missions abroad are in a position to deal with relatively simple correspondence in Hindi. For other work requiring high technical standards in Hindi, they have been advised to seek the assistance of the Ministry.

(b) Efforts to conduct correspondence in Hindi continue but despite this, we are not yet in a position to correspond in Hindi between the Government o India and the Indian Missions abroad as well as between Indian Missions and foreign Governments to which they are accredited due mainly to the prevailing shortage of personnel who can express themselves in Hindi with the requisite precision and facility.

(c) In most Indian Missions abroad Hindi knowing personnel are available. Two Hindi stenographers and one trained Hindi typist are specifically posted for doing Hindi work at Kathmandu and Moscow, respectively. Hindi typewriters have been supplied to Indian Missions Gangtok, the Hague, Karachi, Kathmandu, London, Mauritius Moscow, New York, Peking, Suva, Tokyo and Trinidad. Most Indian Missions are subscribing to Hindi newspapers and periodicals though exact figures are not available. There are libraries in 52 Indian Missions abroad and books in Hindi are being supplied to them.

Extradition of Dr. Dharma Teja

379. **Shri Tulshidas Jadhav :** **Shri Valmiki Choudhary :**
Shri Mrityunjay Prasad :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the difficulties being experienced by Government to obtain the extradition of Dr. Dharma Teja from Costa Rica; and

(b) the nature of charges against Dr. Teja and when prosecution would be launched ?

The Prime Minister, Miniser of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) Extradition of Shri & Shrimati Teja was agreed to by the U. S. Court in New York but before it could pass orders they jumped bail and fled to Costa Rica where they made an application for grant of political asylum. This application was strongly resisted by the Government of India and the relevent facts relating to cases leading against the Tejas were brought to the notice of the Costa Rican Government at the highest level. The application for political asylum has now been rejected and a Presidential Decree has also been issued by the Costa Rican Government permitting Government of India to institute extradition proceedings in Costa Rica. Necessary action in this regard is being taken by the Government of India.

(b) The charges against Tejas are criminal conspiracy, criminal breach of trust (embezzlement), cheating (larceny by false pretence), forgery and falsification of accounts through which they succeeded in securing wrongful gains for themselves and causing wrongful loss to the Jayanti Shipping Company Ltd. to the tune of about 3 million dollars. The charges are under Sections 120B read with Section 409,420,467 and 477-A of the Indian Penal Code.

As regards launching of prosecution, criminal proceedings were instituted against

Dr. & Mrs. Teja in a Magistrate's court in New Delhi who, having found a **Prima facie** case against them, issued warrants for their arrest on 27th April, 1967. On the basis of this and other evidence, extradition proceedings were instituted against Dr. & Mrs. Teja in the United States, where they were staying. These, however, could not be completed as they jumped bail and fled to Costa Rica. Extradition proceedings are now being instituted against them in Costa Rica and on return to India, they will face the prosecution pending against them.

गोलपाड़ा स्थित सैनिक स्कूल

380. **श्री मी० रु० मसानी :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में गोलपाड़ा स्थित सैनिक स्कूल में काम करने वाले देश के विभिन्न भागों के अध्यापकों का (राज्यवार पृथक-पृथक) ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या हाल में वहां यह मांग की गई है कि अन्य राज्यों के अध्यापकों के स्थान पर अतिशीघ्र उसी राज्य के अध्यापक नियुक्त किये जायें :

(ग) क्या इस मांग का समर्थन करने के लिये कुछ समय से पहले स्कूल के विरुद्ध काफी आन्दोलन किया जा रहा है ; और

(घ) स मामले में सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (घ) जानकारी सैनिक स्कूल गोलपुड़ा से प्राप्त की जा रही है और यथा समय से सभापटल पर रख दी जायेगी ।

उलग्ज़ादे के मामले में अमरीकी दूतावास और ब्रिटिश उच्चायोग का रुख

381. **श्री पीलु मोडी :** क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 28 दिसम्बर, 1967 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने ओलूग जेड के मामले में नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास और ब्रिटिश उच्चायोग द्वारा अपनाये गए रवैया की मौखिक रूप से कड़ी आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में इन दोनों राजनयिक मिशनों की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : जी हाँ । यूनाइटेड किंगडम के हाई कमीशन से कहा गया था कि उलग्जादे ने जैसे ही उनसे शरण मांगी थी वैसे ही उन्हे हमें सूचित करना चाहिए था । अमरीका राजदूतावास से कहा गया था कि वे उलग्ज़ादे को तत्काल हमारी देखरेख में दे दें क्योंकि किसी आदमी को या आदमियों को अपने अहाते में शरण या प्रश्रय देना किसी राजनयिक मिशन के उद्देश्यों में नहीं है और यह सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के भी विरुद्ध है ।

(ग) बाद में अमरीकी राजदूतावास ने हमें बताया कि अज़ीज़ उलग्ज़ादे उनके अहाते को छोड़ रहा है और हमने उसे अपनी निगरानी में ले लिया ताकि हम अपने कानून, नियम और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के मुताबिक उसके साथ कार्रवाई कर सकें । इसके बाद यूनाइटेड किंगडम

के हाई कमीशन ने हमें बताया कि उनकी सरकार ने इस बात की इजाजत दे दी है कि उलस्टर अगर चाहे तो यूनाइटेड किंगडम आ सकता है।

श्रीलंका से भारत लौटने वाले व्यक्तियों को चीनियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाना

382. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्रीलंका में रहने वाले पेकिंगवादी लोग उत्तरी लंका तथा तटीय क्षेत्रों में भारत को वापस लौटने वाले लोगों में से लोगों को संगठित करके उन्हें तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों का प्रशिक्षण दे रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री, तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने इस आशय की कुछ प्रेस रिपोर्ट देख ली हैं लेकिन इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है।

चलचित्र वित्त निगम

383. **श्री क० प्र० सिंह देव** :
श्री श्रीधरन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री अनिरुद्धन :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री प० गोपालन :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के चलचित्र वित्त निगम को कुछ फिल्म निर्माताओं को दिये गये 30 लाख रुपये के ऋण बट्टे खाते में डालने पड़े थे ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) ऋण की राशि बट्टे खाते में डालने से पूर्व सरकार ने इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की थी ; और

(घ) इस प्रकार दिये गये ऋणों की राशि सुरक्षित रहे इसके लिये क्या उपाय तथा पूर्वोपाय किये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : (क) जी नहीं। 1466-67 तक 12,66,089 रु० के ऋण बट्टे खाते में डाले गये थे। लेखों का सही रूप दर्शाने की दृष्टि से ऐसा किया जाता है और वसूली के लिये निगम पर कोई रोक नहीं है।

(ख) बट्टे खाते में डालने के कारण ये थे कि कुछ फिल्में अधिक पैसा नहीं कमा सकीं और कुछ अन्य फिल्में पूरी नहीं हो पाईं जिनसे पुनर्भुगतान की संभावना समाप्त हो गई।

(ग) अपूर्ण फिल्मों को पूरा करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं तथा उपयुक्त कानूनी कार्यवाही करके ऋणों की वसूली के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(घ) सभी आवेदनपत्रों की जांच की जाती है। विस्तृत रूप से विचार करने के

पश्चात् निगम के विशेषज्ञों के परामर्श से ऋण मंजूर किये जाते हैं। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निर्माता अपने हिस्से की 25 प्रतिशत पूंजी लगाये। ऋणों की वसूली को सुरक्षित करने के लिये प्रतिभूतियाँ स्वीकार करते सयय उचित ध्यान रखा जाता हैं।

जनवरी 1968 में दिल्ली में विद्रोही नागा नेताओं का दौरा

384. **श्री हेमराज :** **श्री अम्बेचेजियान :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत जनवरी में विद्रोही नागाओं के कोई नेता दिल्ली आये थे।

(ख) क्या उनके और सरकार के बीच कोई बातचीत हुई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उन बातचीतों का क्या परिणाम निकाला ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) : जी नहीं। जनवरी में सरकार और छिपे नागाओं के प्रतिनिधियों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।

1962 में चीनियों द्वारा पकड़े गये भारतीय सैनिकों को बहकाया जाना

385. **श्री हेम बरूआ :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 के आक्रमण के दौरान चीनियों द्वारा पकड़े गये भारतीय सैनिकों तथा प्रतिरक्षा कर्मचारियों को बहकाये जाने के बारे में की जा रही जांच पूरी हो चुकी है ;

(ख) क्या कोई प्रतिवेदन तैयार किया गया है और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) प्रतिवेदन सेना की रुचि का ही है। इसको प्रकाशित करना वांछनीय नहीं समझा जाता।

शिक्षा प्रयोजनों के लिये टेलीविजन का प्रयोग

387. **श्री मोहसिन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनता में शिक्षा का अध्ययन बढ़ने के लिए तथा अन्य विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए टेली-विजन का प्रयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) : देश में इस समय टेलीविजन केवल दिल्ली में ही सीमित है। कार्यक्रमों का विषय मुख्यतः शैक्षणिक और सूचनाप्रद होता है। 323 स्कूलों के लिए टेलीविजन पर भौतिक, रसायन, सामान्य विज्ञान और अंग्रेजी में पाठ प्रस्तुत किए जाते हैं, जबकि 217 टेली-क्लब के लिए सायंकाल के समय कार्यक्रम प्रस्तुत किए

जाते हैं । इसके अतिरिक्त, दिल्ली के इर्द-गिर्द 80 ग्रामों में सामुदाकि केन्द्र हैं जिनके लिए कृषि के उन्नत तरीकों, परिवार नियोजन, आदि पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं ।

अपेक्षित साधन उपलब्ध होने पर इस प्रकार का टेलीविजन केन्द्र बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और कानपुर में भी चालू करने का प्रस्ताव है ।

पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का तुर्की का वचन

388. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुर्की ने पाकिस्तान को हथियार और गोला-बारूद वेचने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति, मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) ऐसी कोई सूचना हमारी जानकारी में नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पश्चिमी पाकिस्तान में प्रकाशित भारतीय लेखकों की पुस्तकें

389. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय लेखकों की कई पुस्तकें इन लेखकों की पूर्वानुमति लिये बिना प्रकाशित हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी) :

(क) जी हां ।

(ख) चूंकि कापीराइट के बारे में पाकिस्तान सरकार के साथ अभी तक कोई द्विपक्षीय करार सम्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए सरकार इस मामले में कोई सक्रिय कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है । इस तरह के जाली संस्करण छाप से जिस व्यक्ति का कापीराइट का अधिकार तोड़ा गया है, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता खुला है और वह यह कि वह पाकिस्तान के न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही करे । लेकिन, इस समय दोनों देशों के बीच जैसे राजनीतिक और आर्थिक सम्बन्ध हैं, उनको देखते हुए, भारतीय राष्ट्रिकों के लिए यह रास्ता अख्तियार करना कठिन है ।

(ग) पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय करार के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ।

चीन का सातवां आण्विक परीक्षण

390. **श्री दी० चं० शर्मा** : **श्री समर गुह** :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने 24 दिसम्बर, 1967 को अपना सातवां आणिवक परीक्षण किया था ;

(ख) क्या आण्विक परीक्षण से उत्पन्न धूल (फॉल आऊट) के भारत पर प्रभाव का अनुमान लगा लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) मापने योग्य धूल केवल 10–12 दिन तक ही पैदा हुई । चूंकि धूल केवल एक छोटी-सी अवधि के लिये ही उत्पन्न हुई और रेडियो एकटीविटी अधिकतम अनुज्ञेय स्तरों के केवल 1--2 प्रतिशत तक ही थी, इसलिये इससे स्वास्थ्य को कोई अन्देशा नहीं है।

भारत तथा जापान के बीच वार्ता

391. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री रवि राय :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा जापान के बीच हाल में नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर बातचीत हुई थी जिसमें आण्विक फैलाव को रोकने सम्बन्धी सन्धि और आर्थिक सहायता तथा हाल में दोनों देशों के बीच व्यापार के विकास के प्रश्न शामिल हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिमाण निकला ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी):

(क) जी हां ।

(ख) इस बातचीत से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर और आपसी हित के मामलों पर एक–दूसरे के विचारों को ज्यादा अच्छी तरह समझने में मदद मिली है । इसी के परिणाम-स्वरूप भारत और जापान के बीच आपसी समझ–बूझ और मित्रता के सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं ।

Transfer of Berubari

392. **Shri Baswant** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether a decision has been taken to transfer the Berubari area on the basis of Nehru-Noon Agreement and if not, the reasons for the delay ; and

(b) whether Pakistan has fulfilled all the conditions laid down in the Nehru-Noon Agreement ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

(a) Before a part of the Berubari area can be transferred to Pakistan on the basis of Nehru-Noon Agreement, it has to be demarcated for the purpose. The transfer shall take place with effect from an "appointed day", which the Central Government may by notification in the Official Gazette appoint. This has not yet been done because the demarcation in the Berubari Union area was the subject of a writ petition filed in the High Court of Calcutta. The High Court in its judgment announced on the 3rd January, 1968 passed

an order restraining the respondents, including the Government of India, from announcing the "appointed day" and from constructing any pillars to demarcate Berubari Union No. 12 for the purpose of effecting the transfer of the portion of that Union to Pakistan until a law is passed by the appropriate legislature providing for payment of compensation to the petitioners in respect of their disputed properties.

(b) The Nehru-Noon Agreement envisaged the demarcation of the Indo-East Pakistan boundaries in certain disputed sectors, in accordance with the decisions contained therein The demarcation of the boundaries could only be carried out jointly by the two countries. Some parts of the agreement were implemented. Progress in the implementation of the other important provisions has been retarded as Pakistan has been withholding cooperation on the plea that demarcation of the concerned sectors can only be taken up with that of Berubari.

हिन्द महासागर में परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बियों का तैनात किया जाना

394. श्री दामानी: क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्द महासागर में अमरीका तथा रूस की परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बियां तैनात करने के समाचार की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है।

Study Team on Public Undertakings

395. **Shri Deorao Patil** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the planning Commission have appointed any study team to enquire into the profit or losses of the public undertakings ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

वार्षिक योजनाएं

396. श्री देवराव पाटिल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने निर्णय किया है कि चौथी योजना 1970 में आरम्भ होगी तब तक प्रत्येक वर्ष के लिये वार्षिक योजनायें होंगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना में तीन वर्ष का अन्तर पड़ने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) 6 दिसम्बर, 1967 को सभापटल पर रखे गये प्रधान मंत्री के वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

चन्दा समिति

397. श्री गाडिलिंगन गौड : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेडियो और टेलीविजन पर पहले ही किये जा चुके निर्णय के अतिरिक्त चन्दा समिति की सभी सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है ; और

(ख) क्या इन सिफारिशों पर किये गये निर्णय की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह):

(क) सरकार ने चन्दा समिति की पांच रिपार्टों में से चार रिपोर्टों, जो "रेडियो और टेलीविजन", "वृत-चित्र और समाचार चित्र", "प्रेस सूचना और प्रचार" और "विज्ञापन और दृश्य प्रचार" पर थी, में निहित अधिकांश सिफारिशों पर निर्णय कर लिया है। शेष सिफारिशों पर अभी विचार हो रहा है। "जन सम्पर्क के साधनों का समन्वय" पर पांचवी रिपोर्ट पर प्रशासनिक सुधार आयोग, जो कुछ समय के लिए इसपर विचार किया जाना स्थगित करना चाहता था, की सिफारिश प्राप्त हो जाने के बाद विचार किया जाएगा।

(ख) 18 दिसम्बर, 1967 को सदन की मेज पर रखी गई पिछली "प्रगति रिपोर्ट" के अतिरिक्त "प्रेस सूचना और प्रचार" और "विज्ञापन और दृश्य प्रचार" पर समिति की रिपोर्टों के बारे में दो और प्रगति रिपोर्ट भी चालू अधिवेशन में सदन की मेज पर रख दी जाएंगी।

पाकिस्तान के लिए ईरानी जहाज

398. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समाचार-पत्रों में छपे इस आशय के समाचार का सत्यापन कर लिया है, कि ईरान में मरम्मत होने के पश्चात् हवाई जहाज पाकिस्तान वापिस चले गये हैं ; और

(ख) क्या ईरान सरकार को कोई विरोध-पत्र भेजा गया है तथा यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकल है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख) इरान की सरकार ने विभिन्न स्तरों पर हमें आश्वासन दिलाया है कि एफ-86 किस्म के जो विमान पाकिस्तान भेजे गए थे वे सिर्फ मरम्मत, सफाई और रद्दोबदल के लिए ही भेजे गए थे और अंततः वे ईरान में ही लौट आएंगे। लेकिन, भारत सरकार को बराबर इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि ये विमान अभी पाकिस्तान में ही हैं।

पाकिस्तान द्वारा वायु तथा भूमि सीमा का उल्लंघन

399. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 तथा जनवरी, 1968 के महीनों में भारतीय राज्यक्षेत्र का पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा कितनी बार वायु तथा भूमि सीमा का उल्लंघन किया गया; और

(ख) इस संबन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 के महीनों में जम्मू तथा काशमीर में पकिस्तान द्वारा एक बार भूमि तथा एक बार

वायु युद्धविराम सीमा का उल्लंघन किया गया। संयुक्त राष्ट्र प्रेक्षकों के पास युद्धविराम उल्लंघनों की शिकायतें भेजी गई हैं।

भूमिगत नागा नेताओं की चीन की यात्रा

400. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासचिव श्री मुइवा के नेतृत्व में भूमिगत नागा नेताओं का एक दल हाल ही में चीन का समर्थन प्राप्त करने के लिए पेकिंग में चेयरमैन माओ से मिला था ;

(ख) क्या उसके बाद श्री मुइवा श्री फिजो को चेयरमैन माओ के साथ हुई बातचीत का खुलासा देने के लिए लन्दन गये थे ;

(ग) क्या मुइवा वापस चीन चले गये हैं और वहां रह रहे हैं और चीन के साथ सांठ-गांठ कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार के पास जो जानकारी है उसका ब्यौरा क्या है और नागा विद्रोहियों के बुरे इरादों को नाकारा बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, योजना मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) से (ग) भारत सरकार के पास इस आशय की कोई जानकारी नहीं है ।

(घ) इस तरह के हर मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए हर मुमकिन कार्रवाई की जा रही है ।

लंदन के हवाई अड्डे पर रोक लिये गये भारतीय

401. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैध यात्रा कागजातों के न होने के कारण ब्रिटेन के आप्रवजन प्राधिकारियों द्वारा लंदन के हवाई अड्डे पर रोके गये अनेक भारतीयों के बारे में 16 जनवरी, 1968 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत के विभिन्न पत्तनों पर सीमा शुल्क और आप्रवजन प्राधिकारियों ने किन परिस्थितियों में भारतीयों को जाने की अनुमति दी थी ; और

(ग) क्या बिना वैध यात्रा कागजातों के उनकी यात्रा के कारणों के बारे में कोई जांच की गई है और उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है तथा कर्तव्य उपेक्षा के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी):

(क) जी हां । सरकार की सूचना के अनुसार, अप्रवास अधिकारियों ने 14 जनवरी, 1968 को लंदन हवाई अड्डे पर सिर्फ भारतीयों को यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने से इनकार किया। इनमें से एक ब्रिटिश पासपोर्ट पर आया था जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने जाली पाया। बाकी जो 10 भारतीय लोग वैध भारतीय पासपोर्ट पर गए थे, उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया क्योंकि ब्रिटिश अप्रवास अधिकारियों के अनुसार, वे ब्रिटिश कामनवैल्थ इमीग्रेन्ट्स एक्ट, 1962 के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश करने के पात्र नहीं थे।

(ख) चूंकि सम्बद्ध व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट थे, इसलिए भारत के विभिन्न भागों में चुंगी एवं आप्रवास अधिकारियों ने उन्हें अनुमति दे दी । जो भारतीय पासपोर्ट-धारी यूनाइटेड किंगडम जाने के इच्छुक होते हैं, उन्हें खबरदार कर दिया जाता है कि यूनाइटेड किंगडम जाने से पहिले उन्हें सावधानी के तौर पर भारत-स्थित ब्रिटिश हाई कमीशन से प्रवेश परमिट प्राप्त कर लेने चाहिए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अशिष्ट तथा अश्लील इश्तहारों का लगाया जाना

402. **श्री क० हाल्दर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अशिष्ट तथा अश्लील इश्तहारों तथा विज्ञापनों के प्रदर्शन पर नियंत्रण लगाने के लिये राज्य सरकारों से कार्यवाही करने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे कार्य रूप दिलाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह):

(क) जी, हां ।

(ख) भारतीय दण्ड विधान की धारा 292, जिसमें अश्लील सामाग्री के विरुद्ध कार्यवाही की अनुमति दी गई है, की ओर राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया था । राज्य सरकारों का ध्यान नगर निगम अधिनियम की धारा 142 जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक विज्ञापन जो जनता के प्रदर्शनार्थ होता है, अश्लीलता से सम्बन्धित बातों को सम्मुख रखते हुए, आयुक्त की अनुमति के लिए भेजा जाता है । अशिष्ट तथा अश्लील इश्तहारों तथा विज्ञापनों के प्रदर्शन पर नियंत्रण हेतु, राज्य सरकारों को अनुरोध किया गया था कि वे अपने राज्य की नगर पालिका के नियमों में इस प्रकार के उप नियमों को सम्मिलित करने पर विचार करें।

(ग) भारतीय दन्ड विधान या किसी भी स्थानीय विशेष कानून के अन्तर्गत अश्लील सामाग्री के प्रचार को रोकने का कार्य राज्य सरकारो पर निर्भर करता है जिनमें से कई राज्यों ने अर्थात् पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मैसूर, बम्बई, गुजरात, केरल, बिहार और आंध्र प्रदेश ने पहले ही उचित कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है।

भारत से रूसी राष्ट्रजनों का देश त्याग

403 **श्री जी० ना० हजारिका** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी सरकार ने इस बात पर औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूप से चिन्ता व्यक्त की है कि भारत की यात्रा पर जाकर उसके राष्ट्रजनों ने बार-बार देश त्याग किया है और यह धमकी दी है कि इन परिस्थितियों में वह अपने उन तकनीकी कर्मचारियों को, जो इस समय विभिन्न विकास परियोजनाओं में लगे हैं, वापस बुला लेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) रूस की सरकार ने भारत-स्थित कुछ विदेशी मिशनों द्वारा अपनी चहारदीवारी में भारत आनेवाले सोवियत राष्ट्रिकों को शरण देने पर अनौपचारिक तौर से चिंता व्यक्त की है । लेकिन उन्होंने विकास प्रायोजनाओं में आजकल काम करनेवाले अपने तकनीकी कर्मचारियों को वापस बुलाने की कभी कोई धमकी नहीं दी।

(ख) 30 दिसम्बर को भारत स्थित तमाम विदेशी मिशनों के पास एक परिपत्र भेजा गया जिसमें उन्हें सूचना दी गई है कि भारत सरकार विदेशी मिशनों को अपनी चहारदीवारी में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को शरण या पश्रय या आश्रय देने के अधिकार को नहीं मानती क्योंकि ऐसा करना राजनयिक मिशनों के उद्देश्य के अन्तर्गत नहीं आता और वह सुस्थिर अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के विरुद्ध भी है । विदेशी मिशनों से कहा गया कि भविष्य में अगर कोई उनसे ऐसा अनुरोध करे तो वे उसे स्वीकार न करें और विदेश मंत्रालय को तत्काल सूचना दें ।

उक्त परिपत्र भारत-स्थित विदेशी मिशनों को यह याद दिलाने के लिए जारी किया गया था कि इस तरह के मामले उनके सामान्य कार्यों में नहीं आते और यह कि भविष्य में इस तरह के मामले फिर न होने पाएं ।

अमृतसर जिले के देहातों के पास गोली चलाने का अभ्यास

404. श्री गु० सि० ढिल्लों : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमृतसर जिले के सुनराओं और कुटिवाला गांवों के निवासिओं ने प्राधिकारियों से यह शिकायत की है कि पिछले कई महीनों से उनकी भूमि में गोली चलाने का लगातार अभ्यास किया जा रहा है;

(ख) गोली चलाने का अभ्यास करने के लिये जिस भूमि का उपयोग किया जा रहा है क्या उसके मालिकों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनको कितना धन दिया गया है ;

(घ) गोली चलाने का अभ्यास करने के कारण जो भूमि जोती नहीं जा सकी उसके मालिकों को मुआवजा देने के लिये क्या कसौटी निर्धारित की गई है ;

(ङ) क्या गोली चलाने का अभ्यास वहां बन्द करने अथवा अन्य स्थानों पर करने का सरकार का विचार है; और

(च) यदि हां, तो इस क्षेत्र में गोली चलाने का अभ्यास कब तक बन्द कर दिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (च) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

जंजीबार में भारतीय लोग

405. श्री काशीनाथ पाण्डेय : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंजीबार सरकार ने उन भारतीय लोगों को, जो 1964 से उस देश से बाहर चले गये हैं, निष्कासित करने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जनवरी 1964 की क्रांति के तत्काल बाद भारतीय मूल के कोई 1500 व्यक्ति जंजीबार से रवाना हुए थे; जंजीबार की सरकार ने उनकी वापसी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिससे वे अपनी संपत्ति और व्यापार की देखरेख करने के लिए वहां नहीं जा सकते। इन लोगों पर अब भी प्रतिबन्ध लगा है ।

(ख) भारत सरकार ने अपने हाई कमीशन के जरिए इस मामले को लिखित और मौखिक रूप से तंजानिया सरकार के साथ उठाया। इसके परिणामस्वरूप एक देशीकरण ब्यूरो खोला गया है और भारतीय मूल के एशियाई लोगों को जो निवासी परमिट जारी किए गए थे वे नवीकरण के लिए तंजानियाई अधिकारियों के पास पड़े हैं और वे उनकी जांच कर रहे हैं। अब तक कोई बीस मामलों पर इस बात का प्रमाण पेश कर देने पर अनुकूल निर्णय लिए गये हैं कि जंजीबार से उनके प्रस्थान का प्रबन्ध इस क्रांति से पहिले किया गया था।

सेना के कर्मचारियों को पेंशन

406 श्री रणजीत सिंह : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में और 1965 में कच्छ की लड़ाई में मारे गये सभी सेना कर्मचारियों को भारत सरकार के प्रतिरक्षा मन्त्रालय के दिनांक 16 सितम्बर, 1966 के पत्र संख्या 195163/पी० ई० एन–सी० के अनुसार बढ़ी हुई दर से पेंशन दी गई थी ;

(ख) क्या यह आदेश चीन के साथ हुए युद्ध में मारे गये सेना कर्मचारियों पर भूतलक्षी तारीख अर्थात् अक्तूबर 1962 से लागू हुआ था; और

(ग) क्या ये लाभ नागा विद्रोहियों के साथ लड़ाई में मारे गये सैनिकों को भूतलक्षी प्रभाव से दिये गये ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह): (क) और (ख) भारत सरकार, प्रतिरक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 195163/पैन–सी, दिनांक 17.9.65 तथा संख्या 195163 / पैन–सी, दिनांक 7.10.1965 के अनुसार, पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई में 5 अगस्त, 1965 या इसके पश्चात् लड़ते हुए मारे गये सेना अधिकारियों या कर्मचारियों को कुछ अधिक विशेष परिवार पेंशन मंजूरी की गई थी । बाद में ये लाभ भारत सरकार के पत्र संख्या 195163/पैन–सी, दिनांक 17.11.65 के अनुसार 1962 में चीनी आक्रमण 1965 में कच्छ की लड़ाई में मारे गये व्यक्तियों को भी दिये गये थे । चीनी आक्रमण के परिणामस्वरूप मारे गये व्यक्तियों के ये लाभ 17 नवम्बर, 1965 से दिये गये थे ।

(ग) जहां तक नागा जैसे सशस्त्र विद्रोहियों के विरुद्ध मारे जाने वालों का सम्बन्ध है, ये लाभ 16 सितम्बर, 1966 से दिये गये हैं जो कि सम्बन्धित सरकारी आदेशों को जारी करने की तिथि है ।

Annual Plan for 1968-69 For M. P.

408. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whethere provisional targets have been fixed for various projects of Madhya Pradesh under the Annual Plan for the year 1968-69 ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

भारत तथा पाकिस्तान के सम्बन्ध

409. **श्री को० सूर्यनारायण** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को रूस के प्रधान मंत्री के माध्यम से पाकिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से ताशकन्द घोषणा के आधार पर भारत के साथ उसके (पाकिस्तान के) विवादों को हल करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पाकिस्तान के साथ विवादों को हल करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख) इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

(ग) भारत सरकार दोनों देशों के बीच की समस्याओं को निबटाने के लिए हमेशा तैयार रही है । उसने पाकिस्तान सरकार से प्रस्ताव किया है कि दोनों देशों के बीच संबन्धों को सामान्य करने के लिए दोनों पक्षों को तत्काल कदम उठाने चाहिए ।

Aircraft Parts Manufacturing Factory

410. **Shri O. P. Tyagi** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) whether Government had given their approval to the setting up of an aircraft parts manufacturing factory with American collaboration, at Village Hazrat Nagar Garhi, Thana Mainather, District Moradabad, U. P.;

(b) if so, whether the said factory is in the public or in private sector ;

(c) the amount of financial assistance which the Central Government have agreed to give ;

(d) the reasons due to which the said factory has not started functioning ;

(e) whether Government have received any information regarding the management of the factory having misused the funds thereof ; and

(f) if so, the details thereof ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri L. N. Mishra) :

(a) Licence No. L/I A. (7)/N-160 (60) dated 25. 1. 1960 was issued under the Industries (D & R) Act to M/S Mohanwi Corporation Pvt. Ltd., Delhi (now known as M/S Allied International Products Ltd.) by the Ministry of Industrial Development and Company Affairs for the establishment of a new industrial undertaking in Delhi (later changed to district Moradabad in U. P.) for the manufacture of (i) automobile and aircraft general spares (such as aircraft nuts, bolts, pins, brackets, couplings, union, ignition harness & safety belts parts), (ii) self-tapping screws and self-lubricating bearings & bushes. Collaboration with M/S Allied Products Corpn.USA was approved in March, 1962 but

later the firm had sought permission for collaboration with M/S Taxtron Inc. of USA instead of the above firm and approval for this was given in November 1963.

(b) In the private sector.

(c) No financial assistance has been agreed to be given by the Central Government.

(d) The amounts of financial assistance agreed to be given by the underwriters viz. the Industrial Finance Corporation of India and Industrial Development Bank of India have not yet been released to the firm. Consequently, the firm is not able to finance its imports of plant & equipment which have to come from abroad. On this account, the firm have informed Government that they are not able to complete the installation and establish the production.

(e) and (f) we have received no such information.

Foreign Trainees in Army Training Centres

411. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Army and Air Force personnel and technicians of some foreign countrtes are getting training in the training centres of the Indian Army;

(b) if so, the number of the Army and Air Force personnel and the technicians under training in these centres, countrywise;

(c) the number of Military and Air Force personnel trained in these centres during the last 15 years, country-wise; and

(d) the details regarding the training imparted to the foreigners and the schemes and agreements under which this training has been imparted in different training centres ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) ;

(a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Participation by Foreign Cadets in Republic Day Parade

412. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some foreign cadets also participated in the Republic Day parade on the 26th January, 1968;

(b) if so, the number of these cadets, country-wise; and

(c) the period of their stay and the amount spent on them during that period ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :

(a) to (c) ; Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Exhibition of New Hindi Films

413. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in January last film producers made a declaration to the effect that exhibition of new Hindi films would be discontinued within some months;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of Information and Broadcasting : (Shri K. K. Shah) :

(a) to (c) : Government have seen press reports about the dispute between the producers and the distributors of Central circuit, U. P., Delhi and Panjab in regard to mode of paymant for the prints of films. The matter is reported to be under negotiation between the producers and the distributors. The Government has not received any reference from the film industry and, therefore, no action is called for.

हज यात्री

415. **श्री मेघचन्द्र** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965, 1966 तथा 1967 में मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र से हज यात्रा के लिये मुगल लाइन, बम्बई को कितने आवेदनपत्र भेजे गये;

(ख) गत तीन वर्षों की अवधि में मनीपुर से वस्तुतः कितने व्यक्तियों को हज जाने की अनुमति दी गई ;

(ग) क्या यह सच है कि भूतपूर्व हज समिति, मनीपुर ने बहुत से आवेदनपत्र मुगल लाइन, बम्बई को नहीं भेजे यद्यपि आवेदनपत्र मय शुल्क ठीक समय पर प्राप्त हो गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इन आवेदनपत्रों को मय शुल्क मुगल लाइन, बम्बई को न भेजने के क्या कारण थे और क्या एकत्रित राशि आवेदकों को लौटा दी गई थी ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) केंद्र शासित प्रदेश, मणिपुर से हज यात्रियों के प्रार्थना-पत्रों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	प्रार्थना-पत्रों की संख्या
1965	(सूचना सुलभ नहीं है। इसका निश्चित पता लगाया जा रहा है, और सदन की मेज पर रख दी जायगी)
1966	157
1967	131

(ख) केन्द्र शासित प्रदेश, मणिपुर से जो यात्री हज यात्रा पर गए, उनकी संख्या :—

वर्ष	यात्रियों की संख्या
1965	(सूचना सुलभ नहीं है। इसका निश्चित पता लगाया जा रहा है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी)
1966	15
1967	69

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

हिन्द महासागर में ब्रिटिश अमरीकी अड्डे

416. श्री रा० बरुआ : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में ब्रिटिश तथा अमरीकी अड्डे बनाने के लिये वहां स्थित द्वीपों का ब्रिटेन द्वारा अर्जन किये जाने के सम्बन्ध में आगे और कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह मामला अंतिम रूप से तय हो चुका है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार ने चार द्वीप समूह अधिग्रहीत किए थे—मारिशस से डीगो गारसिया सहित चागोस द्वीप समूह और सीचेलीस के अन्य तीन द्वीप समूह – अल्डावरा, फरकुहर और डेसरोचेस । उन्होंने चागोस द्वीप समूह के लिए मारिशस को अनुग्रहपूर्वक 30 लाख पौंड की राशि दी और स्थानीय प्लांटरों से तीन अन्य द्वीप ले लिए।

(ग) ब्रिटिश सरकार ने आश्वासन दिए थे कि वह ब्रिटिश हिंद महासागर प्रदेश का सैनिक अड्डों के लिए उपयोग नहीं करेगी बल्कि उन्हे सुदूर पूर्व को संचार सुविधाए पहुंचाने के लिए मार्ग केन्द्र के रूप में उपयोग में लाएगी । लेकिन नवम्बर 1967 में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि अवमूल्यन के बाद के दबावों का मुकाबला करने के एक उपाय के रूप में उसने ब्रिटिश हिंद महासागर प्रदेश में अलडाबरा की योजना को आगे बढ़ाने का इरादा खत्म करने का निर्णय कर लिया है ।

Shooting Ranges in Madhya Pradesh

417. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Defence** be pleased to state :

(a) the names of the districts of Madhya Pradesh where shooting ranges have been provided;

(b) whether it is a fact that some shooting ranges have no walled enclosures resulting in bullets going astray;

(c) if so, whether Government propose to construct high-walled enclosures for these ranges; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) : (a) to (d) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Haj Pilgrims From Madhya Pradesh

418. **Shri G. C. Dixit** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Haj pilgrims belonging to Madhya Pradesh out of the Pilgrims who had gone for Haj during the last year;

(b) whether it is a fact that the number of Haj pilgrims from Madhya Pradesh was lower than those from other States; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Planning and Minister of External Affairs (Shrimati Indira Gandhi):

The total number of pilgrims who went on Haj pilgrimage in 1967 was 15,544. Out of this 395 pilgrims belonged to Madhya Pradesh.

(b) and (c) : The allocation of Haj seats is done on the basis of the Muslim population of the respective States. The seats allotted to pilgrims from Madhya Pradesh were therefore, naturally, fewer than those of States having larger Muslim population and more than those having smaller Muslim population.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय की दुखद मृत्यु की ओर गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाता हूँ ।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि गृह-कार्य मन्त्री इस समय राज्य सभा में है, इसलिये में उत्तर को पढ़ता हूँ । वह शीघ्र ही यहां आ जायेंगे । जनसंघ के अध्यक्ष श्री दीनदयाल उपाध्याय का शव 11 फरवरी 1968 के सबेरे मुगलसराय रेलवे स्टेशन के समीप पाया गया । उत्तर प्रदेश की पुलिस उन परिस्थितियों की जाँच कर रही है जिनमें एक लोक नायक, जिनका देश के राजनैतिक जीवन में महत्व-पूर्ण योगदान है, की दुखद मृत्यु हुई । केन्द्रीय सरकार ने 12 फरवरी 1968 को व्यवहार-आयुर्विज्ञान (फोरेन्सिक साइंस) के तीन विशेषज्ञों की सेवाएं जाँच करने वाले अधिकारियों को उपलब्ध कराई । उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के अनुरोध पर इस मामले की जांच को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने का निश्चय किया गया है और ब्यूरो का एक डी० आई० जी० शीघ्र ही घटना-स्थल की ओर रवाना हो जायेगा । गहन चिंता के बावजूद सभा यह अनुभव करेगी कि श्री उपाध्याय की मृत्यु के कारणों के बारे में इस समय कुछ भी कहना मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Shri Upadhyaya was found dead in mysterious circumstances. It is not an accident but it is a murder. If this trend continues unchecked no political leader in our country will be safe. I welcome the attitude of Central Government that they have agreed to institute a separate enquiry into the matter.

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जांच-पड़ताल दंड विधि प्रक्रिया के अधीन की जायेगी और वह राज्य सरकार द्वारा की जायेगी । एक ही मामले में कई जांच नहीं की जा सकती । उत्तर प्रदेश सरकार मामले में जाँच कर रही है और केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का एक वरिष्ठ अधिकारी भी वहां भेजा जा रहा है । इस प्रकार वह मिला-जुला दल जांच करेगा । केन्द्र की ओर से अलग से जाँच नहीं कराई जायेगी ।

माननीय सदस्यों की चिंता और भावनाओं को मैं भली भाँति समझता हूँ परन्तु इस समय मृत्यु के कारण पर मैं प्रकाश नहीं डाल सकता।

Shri Kanwar Lal Gupta : I understand that the Home Minister is as much keen as we are in the investigations. I would like to point out that the Railway Department is also involved in it because Shri Upadhyaya's dead body was found in the premises of railway yard. It is only after five hours that his body could be recognized. It is due to the indifference of the Railway Authorities. I would like to know whether the Railway Administration will take more precautions to provide protection for such political personalities, so that such incidents may not recur in future.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इन सब बातों पर जाँच पूरी हो जाने के बाद ही ध्यान दिया जा सकेगा। यदि कोई कार्यवाही रेलवे द्वारा की जानी आवश्यक होगी तो अवश्य की जायेगी।

Shrimati Lakshmi Kanthamma (Khammam) : May I know whether Government will take certain steps to check the recurrence of such accidents in future and whether certain security arrangements will be made for prominent political leaders ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यदि सुझाव यह है कि राजनैतिक दलों के सदस्यों को सरकार सुरक्षा प्रदान करे तो जो लोग सुरक्षा की माँग करेंगे उनकी सुरक्षा के लिये प्रबन्ध अवश्य किया जायेगा।

श्री प्र० के देव (कालाहाँडी) : इस जाँच की रिपोर्ट इस सभा को कब तक मिल जायेगी ?

श्री यशवतराव चह्वाण : महत्वपूर्ण मामला होने के कारण यह अपेक्षा की जाती है है कि यह जाँच शीघ्रातिशीघ्र पूरी हो। परन्तु जाँच के रिपोर्ट देने की अवधि निर्धारित करना कठिन है।

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh): May I know whether it is a fact that there was no attendent in the first class bogey, in which Shri Upadhyaya was travelling and that his bed-roll was missing? At what time was the order for sealing that bogey issued after the dead body was found at 3—25 A. M.?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब तक जाँच पूरी न होगी तब तक मैं इन प्रश्नों का उत्तर न दे सकूंगा।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : It is good that the Central Government is taking keen interest in the investigations. But I would like to know whether the representative of the railway Department was also included in the investigating team?

Shri Y. B. Chavan : It should be well understood that it is not an Enquiry Commission, but it is investigation and investigation is conducted by the Police. If it will be necessary, the Police will discuss the matter with railway administration also.

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

आसाम में दंगे

अध्यक्ष महोदय : मुझे स्थगन प्रस्तावों की कई सूचनाएं मिली हैं । उन सब को एक साथ नहीं लिया जा सकता । आसाम में हुए दंगों के बारे में श्री मधु लिमये द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव को मैं सभा के सामने अनुमति के लिये रखता हूँ ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I seek the leave of the House.

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं इस प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने का विरोध करता हूँ । वहाँ दंगे सरकार द्वारा की गई गैर जिम्मेदार घोषणाओं के कारण नहीं हुए हैं । आसाम के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है । यह भी दंगों का कारण नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जो इस स्थगन प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में है वे खड़े हो जायें । 50 से अधिक सदस्य खड़े हुए हैं अतः उसे अनुमति दी जाती है । यह प्रस्ताव आज 4 म० प० से 6–30 म० प० तक लिया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : पश्चिमी बंगाल विधान सभा से सम्बन्धित एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी दी गई थी । उसे स्थगित न किया जाये । कम से कम मन्त्री महोदय उसके बारे में वक्तव्य तो दे ही सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना विचाराधीन है और अस्वीकृत नहीं की गई है । एक समय पर एक ही स्थगन प्रस्ताव लिया जा सकता है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

चीनी उद्योग तथा सड़क परिवहन उद्योग के लिये मजूरी बोर्डों पर सरकारी संकल्प

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–7 (1) /67 दिनांक 30 दिसम्बर, 1967 की एक प्रति, जिसके द्वारा सेवा-निवृति की आयु तथा वार्षिक वेतन-वृद्धियों के बारे में चीनी उद्योग के लिये दूसरे केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई अन्तरिम सिफारिशों को स्वीकृत की घोषणा की गई । [पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 35/68]

(2) सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–14 (2)/67 दिनांक 16 जनवरी, 1968 की एक

प्रति, जिसके द्वारा अन्तरिम मजूरी वृद्धि दिये जाने के लिये सड़क परिवहन उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड द्वारा की गई कतिपय सिफारिशों की स्वीकृत की घोषणा की गई है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 36/68]

राज्य सभा से संदेश
Message from Rajya Sabha

सचिव : मुझे सभा को राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

कि राज्य सभा ने अपनी 13 फरवरी, 1968 की बैठक में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियायें विधेयक, 1967, संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को पेश करने का समय राज्य सभा के 65वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया जाय।

प्राक्कलन समिति द्वारा सरकार के उत्तरों का स्वीकार किया जाना
ACCEPTANCE OF GOVERNMENT REPLIES BY ESTIMATES COMMITTEE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को निम्नलिखित सूचना देनी है :

कि प्राक्कलन समिति के सभापति ने उन्हें सूचना दी है कि प्राक्कलन समिति की उप समिति के प्रतिरक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद, सम्बन्धी तदर्थ गुप्त प्रतिवेदन में, जो 28 मार्च, 1968 को प्रतिरक्षा मंत्री को भेजा गया था, सम्मिलित सिफारिशों/निष्कर्षों पर की गयी कार्यवाही बताने वाले सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

———

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

19वां प्रतिवेदन

श्री र० के० खाडिलकर : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का 19वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

———

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

13वां प्रतिवेदन

श्री मी० रु० मसानी : मैं विनियोग लेखे (डाक तथा तार), 1965–66 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (डाक तथा तार), 1967 के बारे में लोक लेखा समिति का 13वां प्रतिवेदन पेश करता हूँ।

———

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

24वें से 28वें प्रतिवेदन तक

श्री पें वेंकटासुब्बा (नन्द्याल) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन पेश करता हूँ:

(1) भूतपूर्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय--केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्था, कटक--के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 77वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 24वां प्रतिवेदन ।

(2) खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (सामुदायिक विकास विभाग)--भाग 1 केन्द्रीय कार्यक्रम के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा के 98वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 25वां प्रतिवेदन ।

(3) रेलवे मंत्रालय--उत्तर पूर्वी रेलवे--के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 65वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 26वां प्रतिवेदन ।

(4) प्रतिरक्षा मंत्रालय--प्रतिरक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद,--के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 94वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 27वां प्रतिवेदन ।

(5) प्रतिरक्षा मंत्रालय—इलेक्ट्रानिक्स तथा राडार विकास स्थापना तथा प्रतिरक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला—के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 95वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 28वां प्रतिवेदन ।

कार्य मंत्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

Motion Re : Thirteenth Report of the Business Advisory Committee

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य मंन्त्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से जो 13 फरवरी, 1968 को सभा में पेश किया गया था सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंन्त्रणा समिति के 13वें प्रतिवेदन से, जो सभा में 13 फरवरी, 1968 को पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

———

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं सभा के सामने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए:—'कि इस सत्र में समवेत लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने 12 फरवरी, 1968 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है उनके अत्यन्त आभारी हैं।'"

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : एक ओर तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा है दूसरी ओर सभा में प्रधान मन्त्री और उप प्रधान मन्त्री उपस्थित नहीं हैं। हम इसका विरोध करते हैं।

संसदीय कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : वे आ रहे हैं।

Shri Chandra Jeet Yadav : We are greatful to the President for his putting national problems—economic, social and political—before us. It is a matter of concern that such problems are still existing in our country. We are facing economic crisis. We boldly faced the famines during last years. For it the President has congratulated us all. We have the questions of development and progress before us. Economic disparities still exist in our society. We have not been able to achieve the target of setting up socialistic pattern of society.

The most important of the existing problems is that of the security of our independence. We can protect our freedom only by being united. Our greatest misfortune is that there is not sense of national unity or national feeling in us. We have differences in respect of region community and language etc. There is not an iota of patriotism. We should begin to love our country and we should be nation-conscious. We should dismantle the political barriers and come up on national level while finding out the solution for the existing problems. The President has called all the political leaders to take the lead in this matter.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The problem of the political instability, which has come up recently, is alarming one. In states Governments are changing in no time. This is not good in the interest of political life. Communal riots in different parts of our country are damaging our national unity. We should accept these problems as a challange before our nation. These are national problems and they cannot be solved by one or the other party. We all Indians should endeavour to find the way to solve them forgetting our political differences.

Political instability in our country, in my opinion, is caused by economic crisis which our country is continuously facing. This crises can be overcome by increasing agricultural production. We should pay special attention to agriculture because ours is an agricultural country. Irrigation facilities, better seeds and modern agricultural implements should be made available to all agriculturists in our country. Barren land lying in lakhs of acres should be reclaimed and distributed to landless farmers. Government should try to see that farmers get reasonable price for their agricultural produce. No doubt that Government have followed the policies favourable to agriculture. I hope Government will continue to do so. Moreover, we are facing recession in industrial sector. We should not be afraid of such phenomena, because they are bound to occur in a developing economy. We should steadily step forward

on the way of our progress. To overcome such difficulties we are taking assistance from abroad. In this respect the policy of our Government is right.

At present our economy is in a jeopardy. Even after 20 years since we attained independence we have not been able to fulfil the promises we had held out to the people. There is a yawning gulf between the incomes of the haves and the have-nots. The entire wealth of the nation is concentrated in the hands of a few people only. If we want to make our country self-reliant we will have to bridge this gulf. Ours is a socialistic pattern of society and we must strive to boost our economy. Ours is the mixed economy. We are not against private enterprise, but there should not be the exploitation of the down-trodden people and the vulnerable sections of the society.

If it is found difficult to remove economic disparity through social control of banks and general insurance, Government should not hesitate in resorting to nationalisation of banks. The Government should take over the entire productive resources of the country to remove discontentment among the masses.

It is true that the language is closely related to our sentiments and our livelihood, but the unity and integrity of the country should reign supermost in our minds . The unity of the country cannot be imperilled for the sake of language. At the same time it is also true that national unity cannot be achieved without a national language. Our Government has an open mind over this issue and it is prepared to have a meeting with the leaders of the various political parties with a view to evolving a national consensus on this question. Then there are some powers which are raising their ugly heads in the country and it is against these that we have to guard ourselves. They may be Shiv Sena or Lachit Sena or Rashtriya Swayam Sewak Sangh, they all spread regionalism and promote fissiparous tendencies. We have to rise above party politics to discuss these issues dispassionately.

India is a country whose freedom struggle was carried under the leadership of that great man who, after evaluating the Indian culture and the morale of the people had said that morality will find a place in the politics of this country. During the last twenty years Congress has done a number of good things. I do not say that Congress is infallible, But efforts should be directed towards minimising those mistakes and checking the recurrence in future.

After the fourth general elections Governments of different complexions emerged in various States and our Prime Minister welcomed them and said that there are evidence of the fact that democracy can be run successfully in our country. Our Deputy Prime Minister had also on a nnmber of occasions assured that the Central Government will not discriminate against any State in the matter of extending assistance to them and that full cooperation will be extended to them.

Congress had lost the confidence of the people to a certain extent in the last general elections and they gone have tried to find out an alternative. Political parties of diametrically opposite views came together and formed Governments. All principles were thrown to the winds. Now if these alternatives do not come to their expectations, the people will be very much disappointed. If we cannot win the confidence of the people our country cannot progress. These are grave matters and require serious consideration.

As regards our foreign policy, I am happy that the basic principles on which it is based have stood the test of time. We have made it clear to the world that we believe in non-interference in the internal affairs of others, we are against colonialism and we want that the imperialism should be removed from the rest of the world. We want peace in the world and friendly relations with the neighbouring countries.

Vietnam war is fraught with grave conseqnences for the world peace. There is every liklihood of the nuclear arms being used in Vietnam war and if that happens humanity will vanish from this planet. We should convene a world conference to discuss issue and mobilise world opinion to wards bringing an end to the Vietnam war. This will enhance our prestige in the eyes of the world. This country has traditions. It has always shown the path of peace to the world.

After the Pakistani aggression some of our friends criticised the action of the Government in surrendering the captured territory. But we rose above politics and presented to the world a shining example of our adherence to high ideals and basic principles. This aspect of country's foreign policy has also been reiterated in the presidential address. India should take initiative in dispelling poverty and indigence from the earth and in preventing affluent nations from exploiting the undeveloped nations.

It is true that internal and foreign policies are closely inter-related. If we want our country to be independent in the international world, we will have to strengthen our economic independence. A country which cannot stand on its own legs economically, cannot be independent in the international field.

श्री मु० न० नाघनूर (बेलगांव) : श्रीमन, मैं मेरे माननीय मित्र श्री चरंजीत यादव द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। पिछले वर्ष हमारे देश में भारी सूखा पड़ा फिर भी सरकार ने अपने प्रयत्नों से देश में अकाल नहीं पड़ने दिया। सरकार ने खाद्यान्न के समाहार के कार्यक्रम को गहन किया और विदेशों से भी अनाज आयात किया। सरकार ने अपने प्रयत्नों में कोई कसर नहीं उठा रह रखी। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि वे समाहार कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से चालू रखें।

बड़ी, मझली तथा लघु सिंचाई योजनाओं में सरकार ने करोड़ों रुपया लगा रखा है। पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में करोड़ों रुपया लगा कर सरकार ने सिंचाई क्षमता को काफी बढ़ाया है।

इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha then re-assembled after lunch at Fourteen of the Clock

श्री मु० न० नाघनूर : कृषि के कार्यक्रमों ने बढ़ावा देने के लिये सिंचाई योजनाओं के अतिरिक्त पम्पों और लिफ्ट सिंचाई कार्यक्रमों के माध्यम से भूमिगत जल के प्रयोग, उर्वरक तथा अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। बाढ़ नियंत्रण के लिये भी कार्यवाही की गई है।

तीन योजनाओं की अवधि से पूर्व देश में उपलब्ध सिंचाई क्षमता 510 लाख एकड़ भूमि की थी। इस समय सिंचाई क्षमता 890 लाख एकड़ की है। हमने देश के प्रत्येक

भाग में बिजली पहुँचाने का प्रयत्न किया है । उस पर हमने तीन योजनाओं के दौरान लगभग 2400 करोड़ रुपये व्यय किये हैं और हमारे पास बिजली की विस्थापित क्षमता 101·7 लाख किलोवाट है । अब तक हमने 55 करोड़ रुपये व्यय करके 60,000 ग्रामों में बिजली पहुंचाई है । अब तक देश में आठ लाख पम्पों की व्यवस्था की है ।

राष्ट्रपति ने उर्वरकों का भी उल्लेख किया है । तृतीय पंचवर्षीय योजना तक हमने देश में उर्वरक तथा मिश्रित सामग्री पर 138 करोड़ रुपये लगाये थे ताकि हमें उर्वरक के आयात पर निर्भर न रहना पड़े ।

पत्तनों के विकास पर भी हमने ध्यान दिया है । सरकार ने दो महत्वपूर्ण पत्तनों अर्थात् तूतीकोरीन और मंगलौर के विकास के लिये स्वीकृति दी है जिसके लिये वह बधाई की पात्र है ।

हमने देश में परमाणु विज्ञान का भी विकास किया है । हाल ही में थुम्बा स्टेशन से सफलतापूर्वक एक राकेट छोड़ा गया है । हमें अपने देश में औद्योगिक विकास के लिये बहुत शीघ्र ही परमाणु शक्ति उपलब्ध हो जायेगी ।

सरकार प्रशासन का मनोबल तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये पूरा प्रयत्न कर रही है । सरकार ने इस प्रयोजन के लिये प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति की है जो देश के प्रशासन को सुचारु बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है । अपने एक सुझाव में आयोग ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिये लोकपाल की संस्था की स्थापना का सुझाव दिया है । मुझे आशा है कि इससे भ्रष्टाचार शीघ्र समाप्त हो जायेगा ।

मैं महाजन आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ । उस आयोग ने महाराष्ट्र, मैसूर तथा केरल की सीमाओं के बारे में जो प्रतिवेदन दिया है, वह एक निष्पक्ष प्रतिवेदन है और उसे पूर्णतया स्वीकार किया जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं श्री चंद्रजीत यादव के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रंगा : (श्रीकाकुलम) : इस बार राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत ही निराशाजनक है । इतनी निराशा पहले किसी भी अभिभाषण से नहीं हुई थी । सरकार का कोई कट्टर समर्थक भी इसे प्रेरणादायक तथा आशाजनक नहीं बता सकता । इसमें हमारे शीघ्र उद्धार की कोई आशा निखाई नहीं देती और सरकार की ओर से भी त्याग की कोई भावना दिखाई नहीं देती ।

सभी ओर अराजकता फैली हुई है और उसके लिये सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं । सरकार ने भाषा-संकलन पारित करके दक्षिण के छात्रों को उत्तेजित किया है ।

पश्चिमी बंगाल में घेराव की घटनायें हुई हैं । सरकार ने अपने अधिकार का प्रयोग नहीं किया और यह सामाजिक बुराई हमारे राजनैतिक क्षेत्र में आ गई । यह एक भारी चुनौती बन गई है और सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । अब वामपक्षी अतिवादी कृषि-श्रमिकों तथा

आदिवासियों में उपद्रव पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने क्या किया है ?

राज्यपाल की शक्तियों का दुरुपयोग किया गया है। पश्चिमी बंगाल में सरकार बदल दी गई और नई सरकार पहली सरकार से अच्छी नहीं थी। उसने बामपक्षियों तथा संयुक्त मोर्चे के लोगों को विधि तथा व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने का अवसर दिया ।

निवारक विरोध अधिनियम का दुरुपयोग किया गया है और उसे शान्त व्यापारियों तथा अन्य लोगों के विरुद्ध बरता जा रहा है और उन्हें कैद कर लिया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा खाद्य पदार्थ अपमिश्रण अधिनियम का भी प्रयोग व्यापारियों को डराने के लिये किया जा रहा है । इससे अराजकता बढ़ती है ।

क्या मूल्यों में लगातार वृद्धि नहीं हो रही है । वित्त मन्त्री देश को यह आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हैं कि मूल्यों में वृद्धि को रोका जायेगा या जनता पर और अधिक दबाव नहीं डाला जायेगा । मुद्रास्फीति के कारण रुपये का मूल्य कम होता जा रहा है तथा इसके फलस्वरूप हमारे देश की आम जनता, कृषक तथा श्रमिक अधिक निर्धन होते जा रहे हैं ।

सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये गये भारी उद्योग अकुशलता के परिचायक हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग का सुझाव है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र एक स्वतन्त्र सांविधक निगम को सौंपे जाने चाहिये। सरकार को इन संयंत्रों से प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये की हानि हो रही है। फिर भी सरकार उस सिफारिश को लागू करने में बहुत समय ले रही है । कहा गया है कि 30 करोड़ रुपये के इस्पात उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। परन्तु वास्तविकता यह है कि उन्हें राज सहायता दी जा रही है ।

कहा जाता है कि भारी उद्योगों का विकास किया जा रहा है। उनका विकास इस प्रकार गलत किया गया है कि वे स्वयं यह मानते हैं कि मितव्ययता, कार्यकुशलता आदि की आवश्यकता है । गैर-सरकारी उपक्रमों के लिये खतरा लगातार बना हुआ है। सरकार द्वारा जो गलत नियंत्रण लागू किया गया है, उसके उत्पादन में रुकावट हो रही है।

कृषकों के विरुद्ध भी ऐसे तरीके लागू किये गये हैं जिनसे उनका उत्साह समाप्त हो गया है। जूट, तम्बाकू, चाय, रबड़ तथा दाल के उत्पादकों को समर्थ मूल्य द्वारा संरक्षण नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने संविधान के सत्रहवें संशोधन अधिनियम द्वारा भूमि की सीमा निर्धारित कर दी है ।

इसके पश्चात् सहकारी खेती तथा किसानों की भूमि का अनिवार्य रूप से अर्जन की धमकी दी जाती है । यह सब किसानों के हित के विरुद्ध हो रहा है ।

क्या अब समय नहीं आ गया है कि क्षेत्रीय नियन्त्रणों को समाप्त किया जाये क्यों कि इस वर्ष सब क्षेत्रों में अच्छी फसल दिखाई दे रही है ? इन नियन्त्रणों का लाभ केवल कुछ मंत्रालयों को ही हो रहा है । कांग्रेस दल स्वयं इन क्षेत्रीय नियन्त्रणों का समर्थन नहीं

करता । यह तो केवल कुछ अधिकारियों के कहने पर जारी हैं। इसी प्रकार अब समय आ गया है कि अन्न की जबरी वसूली को समाप्त किया जाये विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सूखा तथा कमी है जैसे आंन्ध्रप्रदेश में विशाखापटनम, रायलसीमा तथा राजस्थान में जैसलमेर और ऐसे ही उड़ीसा के कुछ भागों में भी है ।

क्या हम कह सकते हैं कि कृषि के मामले में सब ठीक है ? क्या सिंचाई का हमने पूरा विकास किया है ? क्या हमने नालियों की अपराधपूर्ण रूप से अपेक्षा नहीं की है ? क्या कारण है कि नर्मदा घाटी योजना के विकास में देर हो रही है ? जब सरकार को अपने हितों की रक्षा करनी होती है तो यह राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करती है परन्तु जब देश की अर्थ व्यवस्था को सुधारने की बात होती है तो यह हस्तक्षेप नहीं करती ।

खाद्यान्न में राज्य व्यापार है परन्तु इस व्यापार में सेवा की लागत स्वतन्त्र व्यापार करने वालों से तीन गुना होती है । फिर यह कहते हैं कि खाद्य के व्यापारी किसानों का शोषण करते हैं ! जब तक खाद्यान्न निगम तथा खाद्यान्न व्यापार में स्वस्थ्य रूप से मुकाबला नहीं होगा यह कार्य ठीक रूप से नहीं चलेगा ।

हमारे देश पर विदेशों का बहुत ऋण है। सरकार ही कहती है कि वह उनका सूद भी नहीं दे सकती । उसके मुकाबले पर हमने 2900 करोड़ रु० सरकारी उपक्रमों में लगा दिया है। उनसे लाभ एक प्रतिशत से भी कम होता है । यदि कोई व्यक्ति गैर-सरकारी क्षेत्र में अपनी पूंजी पर 10 प्रतिशत से कम लाभ दिखाये तो उद्योगपति उसे नौकरी से निकाल देगा । क्या हम सरकार से 5 प्रतिशत लाभ की भी आशा नहीं कर सकते ? इस अधिक धन के व्यय करने से हमारे लोगों का शोषण हो रहा है।

चौथी योजना के बारे में हमने कहा था कि कम से कम तीन वर्ष के लिये इस योजना को समाप्त किया जाये । परन्तु क्या यह मानेंगे ? नहीं । यह बोकारो इस्पात कारखाना लगा रहे हैं जिसमें सैकड़ों करोड़ों रु० लगाया हुआ है । बड़ी से बड़ी सिंचाई योजना पर भी 160 करोड़ रु० से अधिक व्यय नहीं होगा । परन्तु उसकी लागत तो बढ़ती ही जा रही है और एक अनुमान के अनुसार यह 100 करोड़ रु० पर पहुंच गई है ।

हमारे मन्त्री महोदय भीख का कटोरा लेकर विदेशों में जाते हैं ।

हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में बेकारी है। वह स्वयं मानते हैं कि 140 लाख व्यक्ति बेकार हैं । यदि अर्द्ध बेकारों की भी गिनती की जाये तो बहुत प्रतीत होगी ।

एक ओर कहा जाता है कि अधिक स्त्री डाक्टरों की आवश्यकता है परन्तु दूसरी ओर आंध्र में उनकी छटनी हो रही है । हजारों डाक्टरों को नौकरी से हटाने के नोटिस दिये जा रहे हैं ।

केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध में भी सरकार ने सारा प्रभाव गैर-कांग्रेसी मंत्रिमण्डलों को समाप्त करने पर लगाया है । इन्होंने पश्चिमी बंगाल, हरियाणा तथा बिहार में ऐसा ही किया है । कांग्रेस दल को विपक्ष में बैठने की आदत नहीं पड़ी है। अंग्रेजों की भाँति यह जात-पात

के मतभेदों को एक दूसरे के विरुद्ध उपयोग कर रहे हैं। जब महात्मा गांधी जीवित थे तो इनमें ऐसा करने का साहस नहीं होता था।

वियतनाम के मामले में सरकार अमरीका की भर्त्सना तो कर सकती है परन्तु वियतकांग के विरुद्ध कुछ नहीं कहती। तिब्बत को चीन के लिये छोड़ कर इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या यह लज्जा की बात नहीं है? चीन न केवल भारत के लिये अपितु सारे एशिया के लिये एक धमकी है।

यद्यपि 15 राज्यों में से 9 राज्यों में जनता ने कांग्रेस की सरकारें समाप्त कर दी हैं परन्तु इन्होंने अभी कुछ सीखा ही नहीं है। आज समय है कि यह वास्तविकता को समझें और उसके अनुसार कार्य करें।

मेरे मित्र मसानी तथा प्रधान मंत्री के बीच कुछ बात-चीत हुई थीं परन्तु प्रधान मंत्री ने वचन भंग किया है।

हमें चाहिये कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्याओं को दलों से ऊपर रखें। यह सरकार महाराष्ट्र तथा मैसूर के झगड़ों को शान्तिपूर्ण ढंग से हल नहीं कर सकी यद्यपि दोनों राज्यों में कांग्रेस दल के मंत्रिमंडल हैं। आंध्र प्रदेश में इन्होंने श्री विश्वानाथन की प्रजा पार्टी को भंग किया। आज कांग्रेस दल में स्वार्थपरता है तथा देशभक्ति नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री यह मानने को तैयार नहीं है कि वहां 9 विधायक जेल में हैं। मैं चाहता हूँ कि सदन की बैठक इस कारण स्थगित कर देनी चाहिये क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका इस सदन से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री पें० बेकटासुब्बया (नन्द्याल) : महोदय, मैं राष्ट्रपति द्वारा दिये गये अभिभाषण के लिये उन्हें धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूँ। ऐसे गंभीर अवसर पर कुछ सदस्यों ने ऐसा आचरण किया जिससे न केवल संसदीय लोकतन्त्र अपितु संविधान को भी लांछन लगा।

[**श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए**
Shri S. M. Joshi in the Chair]

श्री दी० ना० मुकर्जी जैसे संसद सदस्य, जो लोकतन्त्र के समर्थक हैं, ने भी उस दिन सदन से बहिर्गमन किया। ऐसे सदस्यों की भर्त्सना की गई और उसमें श्री मुकर्जी का नाम भी है।

राष्ट्रपति जी ने देश में हो रही हिंसात्मक कार्यवाहियों की ओर चिन्ता प्रकट की है। ऐसे ही उन्होंने अलगाव की नीति पर भी चिन्ता व्यक्त की है। मैं सब सदस्यों से अपील करता हूँ जिनका देश की सर्वभौमिकता में विश्वास है कि ऐके का उदाहरण स्थापित करें।

हमारे देश को स्वतन्त्र हुए 20 वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी यह पता नहीं कि हम जा

कहां रहे हैं। क्या हम अराजकता और भ्रम की ओर जा रहे हैं अथवा हम देश के टुकड़े करने जा रहे हैं ?

मुझे प्रसन्नता है कि अब मद्रास के मुख्य मंत्री श्री अन्नादुरै राष्ट्रीय ध्वज का आदर करते हैं और उन्होंने देश से पृथक होने की मांग को छोड़ दिया है।

गोहाटी में लछित सेना द्वारा की कार्यवाहियों से स्पष्ट हो रहा है कि यह देश के टुकड़े-टुकड़े कर देंगी। इसलिये हमें यह देखना है कि देश की एकता को कैसे बनाये रखें। राष्ट्रपति जी ने भी इस प्रकार की कार्यवाहियों को दबाने पर बल दिया है।

श्री रंगा का यह आरोप उचित नहीं है कि कांग्रेस दल गैर-कांग्रेसी राज्यों में उन सरकारों को समाप्त करने पर तुला हुआ है। वह सरकार को अपने आपसी भेदों के कारण ही समाप्त हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के ही मुख्य मंत्री ने एक सप्ताह में 7 बार त्यागपत्र देने की धमकी दी थी। इसमें कांग्रेस का क्या दोष है ?

भाषा की समस्या के बारे में मेरा कहना यह है कि देश की एक सम्पर्क भाषा होनी है और वह संविधान में दी गई 15 राष्ट्रीय भाषाओं में से एक होनी चाहिये। जब तक सारे राज्य एक भाषा पर सहमत नहीं होते देश में दो भाषायें बहुत समय तक चलेंगी। हिन्दी भाषी लोगों को गैर-हिन्दी भाषी लोगों की कठिनाइयों की ओर ध्यान देना चाहिये। त्रिभाषा सूत्र को गैर-हिन्दी भाषी राज्यों ने तो लागू कर दिया था परन्तु हिन्दी भाषी राज्यों ने उसे कार्यान्वित नहीं किया था। अभी तक एक परिपक्व राष्ट्र की भांति आचरण नहीं कर रहे हैं।

देश की आर्थिक स्थिति अच्छी होती जा रही है और फसल भी इस साल अच्छी है। मन्दी भी अब कम होती जा रही है और हम खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं। परन्तु यह स्पष्ट है कि विदेशों से हजारों करोड़ रु० लेकर भी हमारा कार्य अच्छा नहीं था।

हमने पी० एल० 480 के अन्तर्गत 1400 करोड़ रु० का अन्न मँगाया। कुछ हमारी ऐसी योजनायें हैं जैसे राजस्थान नहर, कोसी-गंडक परियोजना तथा नागारजुनसागर परियोजना कि यदि हम उन पर 100 करोड़ रु० के लगभग व्यय करें तो अन्न के मामले में हम आत्म-निर्भर हो सकते हैं।

भाषा के आधार पर राज्यों का गठन इसलिये किया गया था कि प्रशासन से जनता का सहयोग हो। परन्तु अब भाषाई राज्य अपने आपको अलग देश समझने लग गये हैं जोकि बुरा है। मद्रास तथा आंध्र प्रदेश के मुख्य मत्रियों ने राज्य में सीमा का झगड़ा सुलझा लिया। मैं आशा करता हूँ कि अन्य प्रदेश के मुख्य मंत्री भी आपसी समझौतों से इस सीमा की समस्या को सुलझा सकते हैं।

मैं अब द्रविण मुन्नत्र कषगम सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की भाषायी अल्प संख्यों को संरक्षण न देने की प्रवृति बन

गयी है। मुझे इस बात का खेद है कि मद्रास में भाषायी अल्प संख्यों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता।

श्री मनहोरन (मद्रास उत्तर) : क्या वह उसका प्रमाण दे सकते हैं ?

श्री पें वेंकटसुब्बया : मद्रास में तेलगू बोलने वालों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। वे लोग यह महसूस करते हैं कि विभिन्न शिक्षा संस्थाओं से तेलगू को हटाया जा रहा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि भाषायी अल्प संख्यकों के साथ न्याय किया जाना चाहिये। वे लोग किसी पृथक देश में नहीं रह रहे, वे तो हमारे देश के अभिन्न अंग हैं।

इसी प्रकार अन्तर्राज्जीय पानी के बटवारे के मामलों का भी शान्तिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाना चाहिये। ऐसे मामलों को न्यायाधिकरण आदि को नहीं भेजना चाहिये। पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिये। जिस राज्य में पानी के शीघ्र और उचित उपयोग की व्यवस्था हो, उसे पानी दिया जाना चाहिये।

अब भी कई सौ देहात हैं जहाँ पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40 या 50 देहात है जहां मोटरों द्वारा पानी भेजा जाता है। पानी सप्लाई करने की एक योजना बनायी गयी थी परन्तु उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। सरकार को इस प्रकार की योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये जिससे जनता को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

Mr. Chairman : It was announced some time before that the hon'ble Members who want to move amendments should send their names. I want to say that following numbers of amendments will be treated as moved.

The amendment Nos. 1 to 4, 22 to 32, 43 to 55, 68 to 72, 74, 93 to 102, 106 to 130, 170 to 176, 230 to 234, 244, 245, 260 to 268, 273 to 276.

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : मैं संशोधन संख्या 1, 2, 3 और 4 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नो० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं संशोधन संख्या 22, 23, 24, 25, 26, और 27 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नायनार (पालघाट) : मैं संशोधन संख्या 28, 29, 30, 31 और 32 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री क० लक्प्पा (तुमकुर) : मैं संशोधन संख्या 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रमानी (कोयम्बत्तूर) : मैं संशोधन संख्या 51, 52, 53, 54 और 55 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री श्रीधरन (बडागरा) : मैं संशोधन संख्या 68, 69, 70, 71 और 72 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री लषण लाल कपूर (किशनगंज) : मैं संशोधन संख्या 74 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नायनार : मैं संशोधन संख्या 93, 94 और 95 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मो० रु० मसानी (राजकोट) : मैं संशोधन संख्या 96, 97, 98, 99, 100, 101 और 102 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं संशोधन संख्या 106, 107, 108 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 और 117 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं संशोधन संख्या 118, 119, 120, 127, 128, 129 और 130 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री सी० दास (तिरुपति) मैं संशोधन संख्या 170 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं संशोधन संख्या 171, 172, 173, 174, 175 और 176 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं संशोधन संख्या 230, 231, 232, 233, और 234 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री बृज भूषण लाल (बरेली) : मैं संशोधन संख्या 244 और 245 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : मैं संशोधन संख्या 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 और 268 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम्) : मैं संशोधन संख्या 273, 274, 275 और 276 प्रस्तुत करता हूँ ;

सभापति महोदय : निम्नलिखित संशोधनों को प्रस्तुत किया गया समझा जाये ।

क्रम संख्या
12 से 21
80 से 84
131 से 134
158 से 160
235 से 243
269 से 272

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुझा) : मैं संशोधन संख्या 12,13,14,15 और 16 प्रस्तुत करती हूँ ।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या 17,18,19,20 और 21 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 80,81,82,83, और 84 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं संशोधन संख्या 131 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री बलराज मोधक (दिल्ली दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या 132,133,134 को पेश करने की अनुमति मांगता हूँ ।

श्री बेगी शंकर शर्मा (बंका) : मैं संशोधन संख्या 158, 159, 160 पेश करने की अनुमति माँगता हूँ ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ) : मैं संशोधन संख्या 235, 236, 237, 238, 239, 240,241,242,243, पेश करने की अनुमति मांगता हूँ ।

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह (भिंड) : मैं संशोधन संख्या 269, 270, 271, 272 पेश करने की अनुमति माँगता हूँ ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, the Address of the President to both the. Houses of Parliament is an important occasion. It is in accordance with the provisions of the Constitution which we have adopted. At the time of Presidential Address the walk out from the joint session of the Houses should not have been staged. It is not a question of party but it is a question of establishing healthy democratic conventions. Though I have full respect to the feelings and resentment of the parties, which walked out, but I do not approve the method in which they have shown their resentment against the present Government. We have conflict with the Government over their policies and actions ; but we should respect the constitution provisional and democratic tradition. We being MPs. should behave in an ideal manner.

Our national flag is a symbol of nation. We got independence after centuries and we stood united under this flag. Is it fair that we should insult our national flag by tearing it off or by putting it under our feet. Our flag is a symbol of our unity and sovereignty and we should not allow the recurrence of such incidents in future. There are diversities in our national life. We speak different languages, follow different paths of religions. But there is unity in diversities. We should try to develop these diverse modes of life. But we should not encourage the fissiparous tendencies to raise their heads. The unity of our country is in danger at present. We should boldly overcome this crisis.

The President has rightly said that there are some national problems which should be solved by all sitting united irrespective of political shades and ideologies. For example crossing of the floor, the adoption of official language, resolving the economic crisis etc. are some of such problems. These all can be solved if all political parties come together to find their solution in the interest of the whole country. The party is above an individual and the country is above the party-politics. An individual comes and goes, political parties are organized and disorganized, Governments take over and retire, but our country from Kashmir to Cape Comerin should remain in existence for ever.

I am not in favour of holiday in planning. If it is there on temporary basis, it is is on account of defective planning by the present Government. Planning should be reoriented, should have new priorities. Our dependence on foreign aid is increasing day by day. Simultaneously foreign interference in our domestic affairs is increasing. This should be put to an end. We should pay due attention to south East Asia situation. We should make efforts in setting up a Council of Asia as suggested by Shri M. C. Chagla sometimes back. With these words I conclude. Thank you.

स्थगन प्रस्ताव

MOTION FOR ADJOURNMENT

आसाम में उपद्रव

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to move the Adjournment Motion The main reason for moving this is that the disturbances, which recently broke out in Assam are causing danger not only to the property and life of non-Assamese living in Assam but causing danger to the security and integrity of the whole country. The State Government as well as the Central Government have failed in saving the country from this crisis. To-day in protest to the policies of Congress Governments in the State and at the Centre we take up this matter to show them right path, which they should follow in the interest of the whole country.

If the Government continue to follow such a policy of indifference in respect of North-East region of India, it will soon secede from India. At present there are five foreign powers which are secretly preparing the ground for such a misfortune. China, Pakistan, American and foreign bishop missionaries and the foreign owners of tea estates all the five agents are creating conditions there for unrest, disturbances and riots. Unless these five powers are controlled fully peace will not be restored to riot affected areas of Assam. The Government of State i.e. Chaliha's Government is equally responsible for deteriorating situation in Assam. So either he should resign voluntarily or his Ministry should be dismissed. Central Government should not adopt vascillating policy in respect of reorganization of Assam. All the tea testates in Assam should be nationalized and all the foreigners should be expelled from he Assam. Unless foreign interference in Assam State affairs, inflow of foreign weapons and money into Assam is completely checked, the problem of restoring peace in Assam will remain unsolved.

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : अध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये ने गोहाटी तथा आसाम के अन्य क्षेत्रों में हुए उपद्रवों के लिये केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। परन्तु मेरा उनसे भिन्न विचार है । केन्द्रीय सरकार ने तो तत्काल स्थानीय प्रशासन को सेना आदि की सहायता उपलब्ध करा दी थी परन्तु उपद्रवों को शान्त करने में उसका उपयोग करने में स्थानीय प्रशासन असफल रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ की पुलिस ने दंगों को दबाने की बजाय उन्हें भड़काने में रुचि ली। स्थानीय शासन अथवा पुलिस लोगों की जान और माल की रक्षा न कर सकी और मूल दर्शक की भांति मार-पीट, लूट-पाट और विनाश का ताँडव नृत्य देखती रही। कर्फ्यू के दौरान भी ऐसी घटनाएं घटीं।

आसाम में रहने वाले सभी गैर आसामियों की सम्पत्ति को नष्ट किया गया । यह एक प्रकार का सुनियोजित षडयंत्र था । इस शंका की पुष्टि इस बात से होती है कि काफी समय पहले से गैर-आसामी लोगों अथवा संस्थाओं के नाम इस आशय के चेतावनी-पत्र भेजे गये थे कि यदि अपने आपको सुरक्षित रखना चाहते हो तो आसाम छोड़ कर चले जाओ। इसके बावजूद स्थानीय प्रशासन कोई भी ठोस कार्यवाही न कर सका । जो लोग आसाम में सैकड़ों वर्षों से रहते चले आ रहे हैं, उन्हें गैर-आसामी क्यों माना जाये और यदि माना भी जाये तो वे भारतीय नागरिक तो अवश्य है जिन्हें भारत की भूमि के किसी भी भाग पर रहने का अधिकार है। अतः गैर-आसामी लोगों को इस आधार पर तंग क्यों किया जाने दिया। दोषी लोगों को

पकड़ कर उन्हें दंड क्यों न दिया गया जिससे वहां के लोगों के मन में शान्ति और सुरक्षा की भावना पनपती। इससे मैं तो यही निष्कर्ष निकालता हूँ कि उपद्रवों को दबाने में केन्द्रीय सहायता के बावजूद स्थानीय शासन बिल्कुल असफल रहा है।

आसाम एक सीमावर्ती राज्य है तथा वहां के प्रशासन को इतना उदासीन और अकर्मण्य नहीं होना चाहिये। इससे बड़ी उदासीनता और क्या होगी कि राष्ट्रीय झंडे का अपमान होता रहे और पुलिस मौन खड़ी देखती रहे। अतः इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि आसाम में मुख्य और महत्वपूर्ण पदों पर सक्षम अधिकारी रखे जायें, जो भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटने दें। सीमावर्ती राज्य होने के नाते आसाम की रक्षा तथा वहाँ शान्ति व्यवस्था बनाये रखने का सरकार को पूर्ण प्रयास करना चाहिये। आसाम का स्थानीय प्रशासन विशेषकर गुप्तचर विभाग सुदृढ़ तथा कार्यकुशल होना चाहिये जिससे वहां की जानकारी सरकार को तत्काल मिल जाये और पूरे आसाम को सुरक्षित रखा जा सके।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : जो आसाम में घटनाएँ घटी उसके लिये कांग्रेस अथवा विरोधी-दलों को दोष देने से कोई लाभ नहीं है। अब वह समय आ गया है जबकि हम सबको मिलकर उस उपाय को सोचना चाहिये जिससे उस विघटनकारी प्रवृत्ति को रोका जा सके जो क्षेत्रीयवाद अथवा भाषावाद आदि का आवरण ओढ़कर उभरती आ रही हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान के अनुसार भारत के प्रत्येक भाग में रहने अथवा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है फिर 'आसाम आसामियों के लिये' 'बंगाल बंगालियों के लिये' 'राजस्थान राजस्थानियों के लिये, जैसे नारे लगाना कहां तक तर्कसंगत और वैध है। अब उपयुक्त समय आ गया है जबकि फूट डालने वाली अथवा विघटन करने वाली शक्तियों का अन्त कर दिया जाये और देश में एकता की भावना को उभारा जाये। हमें दुख है कि श्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जैसे एकता के प्रतीक आज कांग्रेस दल और हमारे देश में विद्यमान नहीं हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री शास्त्री बहुत महान नेता हुए हैं। देश में अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे उनकी श्रेणी में रखा जाये। उनकी मृत्यु से देश में एक बड़ा स्थान खाली हो गया है। उस रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये देश को उनके समान महान नेता की आवश्यकता है। देश में जो जाग्रति की लहर आई थी वह धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है। हम सब को एक होना चहिये और व्यक्तिगत अथवा संगठित रूप से उस रिक्त स्थान की पूर्ति करने का प्रयास करना चाहिये। यदि प्रादेशिकता की यह भावना फैलती रही तो हम में से अधिकांश लोग इस बात पर विचार करेंगे कि अब समय आ गया है कि राज्यों को समाप्त कर दिया जाय और क्षेत्र बनाये जायें।

प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि सरकार उसके जीवन और सम्पत्ति की रक्षा करे। लेकिन आजकल बहुत से स्थानों पर नागरिकों का जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं है। वह यात्रा करने तथा व्यापार करने में भी सुरक्षा अनुभव नहीं करता। ऐसा समय आ गया है

जबकि एक सशस्त्र नागरिक को अपने जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये हथियार का प्रयोग करना होगा। सरकार को कुछ कानून बनाने चाहिये जिसके अनुसार कानून और व्यवस्था समाप्त हो जाने पर नागरिक अपनी, अपने परिवार तथा सम्पत्ति की सुरक्षा करने के लिये अपने हथियारों का प्रयोग कर सके।

मैं गृह-मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे सभी मुख्य मंत्रियों तथा सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायें और इन विघटनकारी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के उपाये ढूंढें जो हमारे देश में पनप रही हैं। यदि हमने देश को संगठित करने का कार्य आरम्भ नहीं किया तो ऐसा समय आ जायेगा जबकि इस देश के टुकड़े होकर इतने देश बन जायेंगे जितने कि हमारे राज्य हैं।

मैं गृह-मन्त्री से यह भी जानना चाहूँगा कि क्या आसाम में राष्ट्रपति शासन लागू करने का विचार है ?

Shri Sita Ram Kesri (Kathihar) : The incidents occurred in Assam are very painful. There is regional feeling behind these disturbances. We should solve this problem at national level. There was no necessity of bringing this adjournment motion. There is no truth in saying that Chief Minister of Assam is behind these disturbances. It is a fact that these incidents occurred in the presence of the police.

Assam has got some strategic importance. It is sorrounded by Pakistan and China. Peace can only be brought by law-abiding feelings. The solution of these problems should be made at the national level, so that they may not arise again in future.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : (जालौर) इतने बड़े पैमाने पर जो क्षति हुई है ऐसी क्षति पहले नहीं हुई। प्रशासन यहां की भांति वहां भी असमर्थ रहा। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं 26 जनवरी को हुईं, जबकि वहां पुलिस का प्रबन्ध किया हुआ था। इसमें कोई शंका नहीं कि वहां जो घटना घटी वह प्रशासन और पुलिस की जानकारी में घटी।

लचित सेना लगभग एक वर्ष से बढ़ रही है। वे विभिन्न तरीके से राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लगी हुई है जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने अपने गुप्त विभाग द्वारा काफी जानकारी प्राप्त कर ली है।

26 जनवरी को राष्ट्र-विरोधी प्रदर्शन किये जाने का निर्णय किया गया था। इसकी केन्द्र तथा राज्य सरकार को जानकारी थी। यदि केन्द्रीय सरकार का यह रवैया रहा तो स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जायेगी। स्थिति की जानकारी होने के बावजूद भी दंगों से पूर्व या दंगों के समय कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। दंगों से तीन दिन बाद तक कोई गिरफ्तारियां नहीं की गईं, कोई खोज नहीं की गई और पुलिस का रिकार्ड ही रखा गया। मेरे विपक्षी मित्र ने कहा है कि इसके लिये केन्द्र का जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिये। क्या सीमावर्ती राज्य में केन्द्र सरकार के खुफिया प्रबन्ध पर्याप्त नहीं हैं। यदि ऐसा नहीं है, तो उनका खुफिया विभाग कमजोर है। क्या उन्हें यह जानकारी नहीं है कि राज्य सरकार ने उन्हें स्थिति के बारे में पहले ही जानकारी दे दी थी। क्या ऐसी स्थिति में संविधान के अन्तर्गत कुछ कार्यवाही

करने के उन्हें अधिकार नहीं हैं। वहां करोड़ों रुपये की सम्पति नष्ट हो गई है और मंत्री महोदय कहते हैं कि मुआवजे का प्रश्न कठिन है । सरकार सुरक्षा प्रबन्ध करने में असमर्थ है, वह पर्याप्त कार्यवाही करने में असमर्थ है, वह मुआवजा देने में भी असमर्थ है । सरकार को पर्याप्त मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिये । प्रभावित क्षेत्र के व्यक्तियों का आत्म-विश्वास लौटने के लिये यह आवश्यक है ।

आसाम सीमावर्ती राज्य है। वह सामरिक महत्व का क्षेत्र है । उस क्षेत्र में इतनी क्षति और अराजकता होने के बावजूद भी प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । क्या हम अपने क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान को फिर से बुलाना चाहते हैं । इस प्रकार लोक तन्त्र की कैसे रक्षा की जा सकती है ।

हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जबकि देश में आर्थिक संकट के साथ-साथ सामाजिक संकट भी है । यदि केन्द्र में नेतृत्व मजबूत है तो कोई भी राज्य सरकार आसाम सरकार की तरह व्यवहार नहीं कर सकती । अतः यदि हमें अपने देश को विघटन से बचाना है तो केन्द्र का नेतृत्व प्रभावशाली होना चाहिये ।

श्री रा० बरुआ : गोहाटी में जो घटनाएं घटी हैं वह समस्त देश में फैले व्यापक रोग का लक्षण हैं ।

आज हमारे सामने मुख्य समस्या यह है कि प्रभावित व्यक्तियों को किस प्रकार बसाया जाये और उन लोगों में किस प्रकार आत्म विश्वास उत्पन्न किया जाये । हमें गोहाटी में फैले उपद्रव को आसाम के दूसरे भागों में फैलने से रोकना है । मैं सभा तथा सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि प्रभावित व्यक्तियों को बसाने का प्रबन्ध किया जाये ।

मुझे विश्वास है कि यदि समस्या का सहानुभूति से हल करने का प्रयत्न किया गया तो जो लोग पथभ्रष्ट हुए हैं, वे इसको फिर से नहीं दोहरायेंगे । स्वतन्त्रता आन्दोलन में आसाम का बहुत बड़ा भाग रहा है ।

यह सुनकर आश्चर्य होता है कि आसाम के मुख्य मंत्री ने आसाम के लोगों को अलग राज्य स्थापित करने की मांग के लिये उसकाया है । इस प्रकार का आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्य-पूर्ण है । यह भी कहा गया है कि आसाम के मुख्य मंत्री ने बहुत भड़काने वाले भाषण दिये हैं ।

ऐसा भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की । राज्य सरकार ने शीघ्र ही जांच आयोग की नियुक्ति की । इसके साथ ही तीन उच्च पदाधिकारियों को भी स्थानान्तरित किया गया ।

इस समस्या पर सब सदस्यों को ध्यान देना चाहिये और हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि ये बातें भविष्य में फिर से न घटें ।

यह सच है कि आसाम में विघटनकारी तत्व हैं । अतः यह उचित नहीं है कि इस मामले में अधिक उलझनें पैदा की जायें, इस तरह से यह मामला और उलझ जायेगा ।

Shri J. B. Kripalani (Guna) : It is not correct to say that Government had no prior information regarding the trouble in the State. Even three months before the incidents photographs of posters "Assam is not part of India ; Assam is for Assamese ; all the fereigners must go away" the Home Minister and his colleagues must have received those photographs Had the action been taken immediatety, the present state would have not arised. It is unfortunate that the Government only take action after events had taken place. If this state of affairs remains to be continued, it will be difficnlt to preserve national unity and independence in the country.

Now it is high time that Governor's rule in various States and particularly in Assam may be imposed. It is not the work of educated people. It is the work of wicked elements. Disrespect to our national flag and national anthem cannot be tolerated at any cost. Those who do not consider themselves to be Indians should leave India.

सरकार विश्व में शान्ति का गठन करती है परन्तु अपने ही देश में शान्ति नहीं बना सकती। जब इस सरकार का पतन होगा तो समस्त देश का पतन हो जायेगा। यह ठीक है कि एक सरकार जाती है दूसरी सरकार आती है।

Shri Manubai Patel (Damoh) : It is not correct to say that the recent trouble in Assam is the result of inconsistency between the Central leaders and the Prime Minister. No member has produced any documents in its support.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार नहीं है ? आप क्या बात कर रहे हैं ? क्या कांग्रेस वालों को शर्म नहीं आती कि उनकी सरकार क्या कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : इसमें किसी सरकार के बचाव की बात नहीं है। मैं तो केवल सभा के सामने तथ्य रख रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी ओर देखिये।

Shri Manubhai Patel (Damoh) : Sir, nobody would tolerate insult to the national flag. The Minister has not tried to shield anybody. He has himself stated that the administration totally failed when there were riots in Gauhati. But I am not in favour of the adjournment motion when it says that the policy of Central Government about the States reorganisation was always inconsitent. I cannot agree to this argument. Even in regard to Bombay the Government agreed to the bilingual formula yet it could not satisfy the people. About the Assam affairs too one cannot blame the Government if the tribal leaders and the hill leaders do not attend the meeting. The Central Government has been most consistent in these matters. Mr. Patodia was saying that there is Naxalbari. Again Shri Karni Singh, Maharaja of Bikaner was saying that there is no leader after Nehru's death who is a national leader. It is not good on his part to say such a thing. This Parliament is the biggest national forum.

I agree with the reasons advanced by Shri Madhu Limaye about Assam that there is exploitation of the people, that there is foreign hand behind these troubles and that due recognition should be given to the people of Assam. But I cannot agree with him when he says that Shri Chaliha should be removed. This thing can be done by the Assam Assembly and not by Parliament.

I want the adjournment motion to be rejected.

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : Sir, it was not proper on the part of Shri Manubhai Patel to have annoyed Acharya Kripalani. He is an elder leader of ours and we should have respect for his sentiments.

I have visited Gauhati and within three hours, property worth crores of rupees has been destroyed. There were slogans in favour of Pakistan, Ayub Khan and Mao-tse-tung. Members were saying that Lechat Sena was behind these troubles. No one knows who is the leader of Lachat Sena. Assam is a very sensitive area surrounded from three sides by countries which are inimical to us. Since 1901 there are some elements who want trouble there. In 1947 the population of Muslims was only 10 percent but in 1961 it become 25 percent. I saw in Gauhati that the shops and houses of non-Muslims were destroyed or looted. But nothing was done to the property of Muslims. No one can challenge my statement. They are trying to scare away the Hindus from there. I want to ask Mr. Chavan whether he has asked the State Government not to eject the persons who have illegally entered Asssam ?

I know that the pro-chinese and Pro-Pakistani element is very active there. Even in 1962 there were news that areas of Assam north of river Brahmputra were to be given to China and those to the north of that river to be given to Pakistan. I hold the central Government's policy responsible for it to a large extent.

Than the Government made a mistake in creating Nagaland which has a population of only 3 Lakh persons. The impression has gained ground that if 3 Lakh people can have one reparate state why not others too to have it. Even in 1962 when there was talk about Nagaland I stated that we are opening floodgate of disruption. That is coming true now. The Central Government has adopted a double standard, one in regard to Jammu and Kasmir with has been given a spcial status and the other in regard to other States.

For the solution of Assam problem I want the following things to be done :

1. A Commission should be appointed to solve the problem of reorganisation of Assam which may be defence-oriented and which may include among others, the army people and the nationalist.

2. The constant infiltration taking place there should be checked.

3. All foreign missionaries should be expelled from Assam as they want to make it a base of western powers.

4. We should not abdicate that area and the feeling of insecurity in the people should be removed.

5. The strength of the Central police in those areas should be increased.

6. The people who have been looted there should be conpensated. Grants should be given to poorer people.

In the end I want to say that there should be a strong Central Government as it was only when Central Government was weak that India was invaded by foreign powers.

We should not look at this motion from the point of view of parties and support this motion.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Sir, I find that the atmosphere of India has been poisoned to a large extent. Whether it is Gauhati or some other State the same type of poisonous atmosphere is to be seen. This is not going to do any good to the country. There is an atmospher of peacelessness and disorderliness in the country. It is not proper on the part of the opposition to blame the Congress simply because it is in power these days. I find that the atmosphere prevalent now was also seen when Gandhiji was murdered.

Some Harijans are being put to trouble in Madhya Pradesh which is not proper.

It was not proper on the part of Shri Madhok to given this matter a communal tinge. Such statements are dangerous to the nation. We should now even take risk to safeguard th nation.

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री मधु लिमये ने अपने प्रस्ताव में

बताया है कि अल्प संख्यकों को असम में किस प्रकार तंग किया गया । जब वहां स्त्रियों आदि को छेड़ा जा रहा था तो असम के मुख्य मंत्री वहाँ असम में उपस्थित नहीं थे। वह कहीं राज्य से बाहर चले गये थे । सारे देश में यह विश्वास होता जा रहा है कि यह सब असम के मुख्य मंत्रीं के इशारे पर हुआ । वहाँ केवल अल्प संख्यकों पर ही आक्रमण हुए हैं। किसी भी राज्य में वहाँ के लोगों को कुछ अधिकार मिलें इस पर तो आपत्ति नहीं हो सकती परन्तु अल्प संख्यकों को तो न भगाया जाये । यह बहुत दुःख की बात है कि केन्द्रीय सरकार यह सब कुछ देख कर भी हाथ पर हाथ रखे बैठी है । राज्यपाल को चाहिये कि इसके बारे में रिपोर्ट पेश करे ।

इसी प्रकार की घटनायें बम्बई में शिव सेना ने की और गृह कार्य मंत्री स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि यह ठीक नहीं है। परन्तु मैं तो उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि इसके बारे मे उन्होंने क्या किया है ।

मद्रास के मुख्य मंत्री से जब "शिव सेना" आदि के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज "शिव सेना" और "लछित सेना" की आवश्यकता नहीं अपितु "सेवा सेना" की आवश्यकता है। इसे कहते हैं नेतृत्व !

मैं गृह कार्य मंत्री जी से कहूँगा कि इन प्रश्नों पर लोकतान्त्रिक दृष्टि से देखें न कि राजनीतिक दृष्टि से । मैं चाहता हूँ कि वह तुरन्त इसका समाधान तालाश करें।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकता-उत्तर-पूर्व) : जो असम में हुआ है वह आज सारे देश के लिये कलंक है । यह केन्द्रीय नेताओं की असफलता है । असम की कांग्रेस में आज राजनीतिक लड़ाई चल रही है जिसमें भाग लेने वाले श्री चातिदा, श्री देवकान्त बोरुआ, श्री महेन्द्र मोहन चौधरी तथा श्री देबेश्वर शर्मा । शायद यहां के औद्योगिक विकास मंत्री भी चुपचाप नहीं बैठे होंगे । जैसे 'शिव सेना" ने शिवा जी का नाम बदनाम किया है उसी प्रकार "लचित सेना" ने "लचित बारफोकन" का नाम बदनाम किया है जिन्होंने मुगल साम्राज्य का मुकाबला किया था।

श्री मधोक ने इस प्रश्न को साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयत्न किया है। मेरे साथी श्री कलिता ने मुझे बताया है कि वहां मुहम्मद सूफी नाम के मुसलमान का भी मकान जलाया गया था ।

परन्तु इससे वहाँ की क्षेत्रीय सरकार के निकम्मेपन का पता चलता है ।

गोहाटी में साम्यवादी दल के कार्यालय में तथा प्रजा साम्यवादी दल के कार्यालय में फहराये गये राष्ट्रीय झण्डों को गुण्डों ने फाड़ दिया था। जिस टैक्सी में बैठकर गुण्डे झण्डा फाड़ने जाते थे, उसका नम्बर पुलिस को बताया गया था परन्तु फिर भी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इन घटनाओं के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों को क्यों नहीं पकड़ा गया है ।

केन्द्रीय सरकार आसाम के लोगों की समस्या का दीर्घकालीन समाधान नहीं ढूंढ़ सकती है। वह पहाड़ी लोगों से कुछ कहती है और आसाम घाटी की जनता से कुछ और ही कहती है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न लोगों से भिन्न-भिन्न बातें की जाती हैं। परिणाम यह होता है कि कोई भी व्यक्ति सरकार की बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर सकता। आसाम ऐसे राज्यों में से एक है जिन्हें स्वावलम्बी बनने के लिये सहायता नहीं दी जा रही है। शिव सेना और लचित सेना जैसे फासिस्ट संगठन बनाये जाने का कारण यह है कि उन्हें औद्योगिक विकास की ऐसी सुविधायें नहीं दी जा रही है जिनसे उन्हें रोजगार मिल सके। इससे असन्तोष तथा निराशा उत्पन्न हो रही है और इन्हीं परिस्थितियों में फासिस्ट आन्दोलन पनपते हैं।

आसाम की स्थिति सामरिक महत्व की है। इसलिये हमें बहुत सावधान रहना चाहिये। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही पूर्णतया असफल रही हैं। इसलिये सभा को यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिये।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I was one of those members of Parliament who went to Gauhati during these happenings. I take it as my duty to say that the Home Minister has very ably acted in this matter. It is wrong to hold the Central Government responsible for the recent disturbances in Assam. Chinese agents and Pro-Pakistan elements have a hand in those disturbances and those disturbances were pre-planned.

All the political parties should get together and find a way out in order to avoid the recurrence of such disturbances in future. Citizens of this country have a fundamental right to acquire property in any part of the country. An attenpt is being made to put up barrirs between people belonging to different States. This is unconstitutional.

The incumbents of key posts like that of Inspector General of Police have a hand in these disturbances. The intellgence service in Assam is weak and needs to be strengthened. Steps should be taken to instil confidence amongst the people of different States living in Assam.

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : देश में यह सभी कठिनाइयां पैदा होने का मूल कारण यह है कि राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं है और सम्पूर्ण शक्ति केन्द्र के पास है। यदि हम देश की एकता चाहते हैं तो वह एकता अनेकता में एकता ही हो सकती है।

भारत सरकार आसाम पुनर्गठन के प्रश्न पर किसी निश्चित नीति का अनुसरण नहीं कर रही है। वह अपनी स्थिति से पीछे हट रही है। इसलिये राज्य में उत्पन्न हुई वर्तमान स्थिति के लिये भारत सरकार ही प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है।

भारत सरकार के 13 जनवरी, 1967 के वक्तव्य में आसाम राज्य की इकाइयों के आधार पर आसाम का पुनर्गठन करने का निश्चित वचन दिया गया है। यह कोई प्रस्ताव नहीं था। सभा को बाद में होने वाली घटनाओं का पता है कि आसाम कांग्रेस ने ही उस योजना का किस प्रकार विरोध किया था। राज्य सरकार यह चाहती है कि भारत सरकार संघ के सिद्धान्त से अपना कोई सम्बन्ध न रखे। वह चाहती है कि भारत सरकार यह विचार छोड़ दे। राज्य सरकार का यह भी कहना है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी। इसी से यह स्पस्ट हो जाता है कि राज्य सरकार का इन सभी घटनाओं में हाथ था क्योंकि वह संघ के विचार को समाप्त करना चाहती है। आसाम की जनता उपद्रव नहीं करना

चाहती परन्तु उच्च स्तर के कुछ निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति जन साधारण के असन्तोष का लाभ उठा कर उस वर्तमान परिस्थितियों के विरुद्ध भड़काना चाहते थे । उसी उद्देश्य से उन्होंने ऐसा किया तथा वहां पर ऐसी अव्यवस्था पैदा की ।

इसीलिये, मैं यह कहता हूँ कि भारत सरकार पुनर्गठन के प्रश्न पर दृढ़ नीति नहीं अपना रही है बल्कि समय-समय पर अपनाई गई नीति को बदलना ही आसाम की वर्तमान स्थिति के लिये जिम्मेवार है । अतः वहाँ पर हुई घटनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार ही जिम्मेवार है । यदि हम देश की एकता चाहते हैं तो हमें वहां की जनता की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश की भिन्न-भिन्न भाषायें बोलने वाली तथा विभिन्न रीतिरिवाजों पर चलने वाली जनता की भावनाओं को जीत लेना चाहिये ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : गोहाटी में गणतन्त्र दिवस पर जो विनाश हुआ, उसके कारण तथा स्वरूप के बार में सभी भली जानते हैं । इसमें सन्देह नहीं है कि विनाश बहुत अधिक हुआ है । इस प्रकार की सभी घटनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है ।

[श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

हम कहते हैं कि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है परन्तु उसका क्या कारण है कि शेष भारत के लोगो को काश्मीर में सम्पत्ति खरीदने नहीं दिया जाता । स्वाधीनता प्राप्ति के बाद न तो सत्तारूढ़ दल ने और न ही किसी अन्य राजनैतिक दल ने देश में सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है और यही कारण है कि विघटनकारी शक्तियां बढ़ रही हैं ।

गोहाटी मे 20 जनवरी को राष्ट्रीय झंडे का अपमान बड़े ही दुख की बात है । गोहाटी के एक थान म जब झंडा लहराया गया तो उसे नीचे गिरा दिया गया और वहा पर उपस्थित राज्य पुलिस के कर्मचारी मौन खड़े रहे और उन्हान कुछ नहीं किया । मेडीकल कालज में भी ऐसा करना जानबूझकर संगठित तरीके से राष्ट्राय झण्डे के प्रति अपमान का प्रदर्शन था । इससे हमें बहुत दुख हुआ है ।

आसाम राज्य के नवयुवकों में रोजगार के सम्बन्ध में बहुत निराशा है । वहां कुछ केन्द्रीय सरकार के काम भी चल रहे है परन्तु इनके लिये स्थानीय नवयुवकों को पर्याप्त संख्या में नहीं रखा गया है । इसके लिये राज्य सरकार भी उत्तरदायी है, वह सरकार नवयुवकों की समस्या पर ध्यान देने में असफल रही है । यह निहित स्वार्थों के विरुद्ध लड़ने का प्रश्न है । एक सामाजिक कार्यक्रम के साथ उन निहित स्वार्थों का मुकाबला करने का प्रयत्न करने की बजाय राज्य सरकार ने कुछ भी नहीं किया है जिसका परिणाम इतना भयंकर हुआ । गृहकार्य मन्त्री ने भी यह माना है कि 26 जनवरी को गोहाटी म स्थानीय प्रशासन बिलकुल असफल हो गया था ।

जब मैंने गोहाटी में मुख्य मन्त्री की उपस्थिति मे पुलिस अधिकारी से पूछा कि उस दिन आपकी पुलिस क्यों कार्य नहीं कर रही थी तो उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं । पुलिस की संख्या बहुत अपर्याप्त है । जब मैंने यही बात मुख्य मन्त्री की उपस्थिति में श्री चव्हाण से

कही तो उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस का दस्ता आसाम में भारत में सब से अधिक है ।

हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि आसाम सामरिक महत्व का राज्य है और सभी विनाशकारी शक्तियाँ वहां पर एकत्र हो गई हैं। साइकिल फैक्ट्री के विनाश के लिये उत्तरदायी व्यक्ति ने यह स्वीकार किया है कि उसका सम्बन्ध बामपक्षी साम्यवादियों के नक्सलबाड़ी ग्रुप से था। उसने यह भी कहा है कि वह उन 11 व्यक्तियों की भी सूची देगा जो उसके साथ थे। यह लोग नक्सलबाड़ी में असफल रहे। उसके पश्चात् वह गोहाटी चले गये तथा उन्होंने लचित सेना के साथ, जिसने छिपे नागाओं के साथ कोई समझौता कर लिया है, साठगांठ करके यह भयानक उपद्रव किया। इन घटनाओं को सम्प्रदायिक रूप देना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि इससे सम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। आसाम इस प्रकार के और अधिक तनाव के लिये तैयार नहीं हैं।

प्रसन्नता की बात है कि इस मामले में न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिये कि केवल आसाम में ही नहीं अपितु समूचे देश में शान्ति स्थापित की जाये, गृह-कार्य मन्त्री को सभी राजनैतिक नेताओं तथा विभिन्न संस्थाओं के लोगों का एक गोलमेज सम्मेलन बनाना चाहिये और एक कार्यक्रम बनाना चाहिये तथा उसे पूरा करने का पक्का इरादा करना चाहिये। परन्तु हमारी सरकार समितियां नियुक्त करती है, समितियां प्रतिवेन प्रस्तुत करती हैं और उन प्रतिवेदनों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैंने गोहाटी के अपने दौरे में देखा है कि वहां बड़े भारी पैमाने पर आग लगी है और लूटपाट की गई है। इसीलिये, मैं यह कहता हूँ कि गोहाटी की घटनायें न केवल सरकार के लिये ही बल्कि सभी राजनैतिक दलों के लिये तथा उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिये चेतावनी हैं।

पटस्कर आयोग का प्रतिवेदन 1966 में आया और मन्त्रि मन्डल की एक उप-समिति ने इसकी छानबीन की। मैं उस उप-समिति का सदस्य था। हमने आसाम के, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ इस प्रस्ताव पर चर्चा की। वास्तव में यह एक बड़ी जटिल समस्या है तथा कुछ समय और ऐसी रहेगी। याद रखने वाली मूल बात यह है कि पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की इच्छाओं पर सहानभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

आसाम के पुनर्गठन के प्रश्न को बड़ी सूझबूझ के साथ सुलझाया जाना चाहिये। सरकार की यही नीति है। यह किसी एक दल की समस्या नहीं है। बल्कि यह तो राष्ट्रीय समस्या है। देश में चुनाव होने वाले थे। हम चाहते थे कि शान्ति का वातावरण बना रहे। आसाम एक सीमा क्षेत्र है। अतः उसका विशेष महत्व है वहां पर कुछ आन्दोलन भी चल रहे थे। हम चाहते थे कि इन्हें समाप्त कराया जाये। प्रधान मन्त्री वहाँ दौरे पर गईं और वहां के लोगों से मिलीं और उन्होंने वक्तव्य दिया कि लोगों की आकांक्षाओं का आदर किया जायेगा। यह उन्होंने आसाम के मुख्य मन्त्री से मश्विरा करने के बाद कहा था। उसके बाद मेरे साथ आसाम के कुछ लोगों से मेरी भेंट हुई। जो समझौता हुआ वह 13 जनवरी, 1967 के वक्तव्य में दिया हुआ है। उसके लिये मैं जिम्मेदार हूँ। अब उसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमें आसाम को एक प्रशासनिक एकक बनाये रखना है। इस मुख्य बात को ध्यान में रखना होगा। हाँ इस क्षेत्र को स्वायत्तशासी दर्जे देने के बारे में यदि कोई सुझाव हों तो उस पर विचार किया जा सकता है। हमें सभी पक्षों को साथ लेकर चलना है।

मई, 1967 में मैं स्वयं आसाम गया था और दो दिन वहां रहा था। मैंने वहाँ देखा कि मैदानी इलाकों के लोग आसाम का एक अलग संघ बनाने के विरुद्ध हैं। ऐसी स्थिति में हम किसी पर कोई निर्णय लाद नहीं सकते। मैं सभा से अपील करता हूँ कि आसाम के पुनर्गठन के प्रश्न को दलगत राजनीति से न लेकर राष्ट्रीय दृष्टिकोण की नीति से लें। मैंने आसाम के सभी पक्षों का दिल्ली में सम्मेलन बुलाया था। परन्तु उसमें कोई प्रगति न हो सकी। हां उससे हमें अशोक-मेहता समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई। उस पर हमें विचार करना है। यह समस्या एक बड़ी समस्या है।

प्रधान मंत्री के वक्तव्य को गलत रूप देकर प्रकाशित किया गया था। उन्होंने कहा था कि इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट के रद्द किये जाने की बात को उछाला गया है।

श्री हेम बरुआ : जब इस बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है तो प्रधान मंत्री ने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने वक्तव्य नहीं दिया। यही मैं आपको बता रहा हूँ।

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। कुछ लोग मुझसे मिलने आये थे और बातों ही बातों में बहुत से विषयों का उल्लेख हुआ था। मैंने उस समय भी कहा था कि अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

श्री हेम बरुआ : प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के कारण गौहाटी में गड़बड़ हुई है। प्रधान मन्त्री को चाहिये था कि यदि कोई गलत बात छप गई थी तो उसका खंडन करतीं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरा सभी राजनैतिक दलों से अनुरोध है कि इन विषयों में हमें सहयोग दें। यह मैंने कहा था कि वहाँ का स्थानीय प्रशासन असफल रहा है। वहाँ का कलेक्टर कानून और व्यवस्था बनाये रखने में असफल रहा है। अब जाँच में यदि राज्य सरकार दोषी पायी गई तो उसे इसके परिणामों को भुगतना पड़ेगा। राज्य सरकार ने जांच कराने का आदेश दे दिया है। 26 जनवरी को जो व्यक्ति वहां तैनात थे उन्हें बदल दिया गया है। जांच का काम अन्य अधिकारियों को सौंपा गया है।

बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ सम्पत्ति भी कब्जे में कर ली गई है। इस बारे में न्यायाधीश श्री सेन को अदालती जाँच के लिये नियुक्त कर दिया गया है।

श्री लिमये ने आरोप लगाया है कि हमने पूर्व जानकारी होते हुए भी इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की थी । मैं इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमें इसकी पूर्व सूचना बिल्कुल नहीं थी । हाँ वहाँ पोस्टरों आदि के बारे में कुछ रिपोर्टें हमें मिली थीं परन्तु हमें यह मालूम नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ होने जा रही है । इसलिये यह आरोप निराधार है ।

मुझे खेद है कि आज हमारे देश में यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि हम सभी विषयों का निपटारा सड़कों पर करना चाहते हैं । यह ठीक नहीं है । हमें संविधान की परिधि में रहते हुए निर्णय करने हैं । विघटनकारी प्रवृत्तियों का दमन करना है । इस रवैये को बदलना होगा । हमारे बच्चे भी देखा देखी गड़बड़ करने लगते हैं । इसलिये हमें सभी बातों पर ध्यान देना चाहिये । हमें इन विषयों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । हमें राष्ट्रीय जीवन में प्राथमिकताओं पर भी सोचना है । देश की एकता सब से अधिक महत्व की बात है ।

डा० कर्णी सिंह : क्या आसाम में राष्ट्रपति का शासन लागू किया जायेगा ?

श्री बलराज मधोक : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन घुसपैठियों को नागरिकता प्रदान की जायेगी कि जो पाकिस्तान से आसाम में आ गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : बात ऐसी है कि हमारे देश में कुछ लोग वर्षों तक करुणामूलक कारणों से रह रहे थे और उन्हें प्रति वर्ष एक-एक वर्ष के लिये नागरिकता दी जा रही थी । उनमें से बहुत से लोगों के सम्बन्धी यहाँ रहते हैं । उनके बारे में विचार करने के लिये राज्य सरकारों को लिखा गया है । ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक नहीं है ।

सरकार का आसाम में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रस्ताव नहीं है । एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे देश में कोई बड़ा नेता नहीं है । इसके लिये हम क्या कर सकते हैं । गाँधी और नेहरू जैसे नेता हमेशा पैदा नहीं होते हैं । व्यक्तिगत सुरक्षा की बात भी कही गई है । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान और कानूनों में उसके लिये आवश्यक उपबन्ध हैं । यदि कोई माननीय सदस्य मुझसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहें तो वे मुझसे मिल सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye : I would like the hon. Minister to consult opposition parties before arriving at a decision. There is no use consulting opposition after the decision has been taken on some vital matter. He is the Minister of Home Affairs. He should be considerate. The reorganiation of Assam has passed through three stages. Once when Constitution was formed. A special provision was made when a scheme was appended in the eighth schedule. Then the States Reorganisation Commission considered over this. A promise of autonomy was given by Shri Nehru. The Pataskar Commission considered this question, but no solution was found. Now this statement of 13th January has come. This statement gives a proposal from Government in which decisions of far-reaching consequences have been envisaged. There is no mention in it that others would be consulted in this. I do not know if Manipur and Tripura have been consulted or not. There was stiff opposition to this proposal in Assam. At that stage Ashok Mehta Committee was appointed. That Committee opposed the reorganisation. Thus two decissions of the Government

were contradictory. Thereafter in October we are invited for consultation. I object to this because they had complicated the matter first and then they wanted to consult us. How is it proper ? Now these serious disturbances have taken place. The Central Government cannot disown its responsibility in this. There were indications of this agitation taking place. I understand the C. B. I. sent reports of wide spread unrest. The feelling against the non-Assamese was spreading. I hold this Government responsible for this.

I am not in favour of President's rule being imposed. That is not the solution. You imposed President's rule in Kerala where happenings of comparatively less magnitute had taken place. Now large scale disturbance have taken place in Assam and nothing has been done by the Central Government. They should not have double standards. They have not made use of Article 256 in this matter. This Government has badly failed in its duty. I cannot forgive them. I cannot withdraw this motion. I request the hon. House to pass this motion and ask them to vacate the treasury benches.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सभा अब स्थगित हो।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The Motion was negatived

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी

Motion on President's address—Contd.

Dr. Govind Das (Jabalpur) : Sir, I support the motion of thanks on President's address.

इसके पश्चात लोक सभा गुरुवार, फरवरी 15, 1968/माघ 26, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday the 15th February, 1968/Magha 26, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119 Swami Vivekanand Marg, Allahabad.